[Shri Asoka Mehta]

going to exist, is of paramount importance.

All the arguments that the Food Minister has put forward that we hope to develop these co-operatives in the next three or four years and this State trading in foodgrains will therefore be taken over by these co-operatives within a measurable distance of time and that corporations need not be set up because they will have their own vested interests later on and might duplicate unnecessarily the work that has to be done, all these arguments are valid to the extent these co-operatives are going to come up, and the co-operatives will come up to the extent the controversy on the legal framework for the co-operatives is set at rest. I hope that, that will be done and that as far as State trading in foodgrains is concerned, the Food Minister will be willing to review the matter afresh and see how far this tentative scheme can be so strengthened that people may find that there are real teeth in it as far as the purposes for which this particular scheme is being put forward.

13·10 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce a slight change in the order of business for the current week. It is now proposed that the Demands for Grants in respect of the Ministry of Defence be taken up for consideration immediately after the voting of demands relating to the Ministry of Food and Agriculture. Consequently, discussion on the demands under the control of the Ministry of Rehabilitation would take place after the discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Defence.

Shri Nagi Reddy (Anantapur): Why this change?

Mr. Speaker: The Minister of Defence has to be elsewhere.

Shri Satya Narayan Sinha: On the 10th there is an Investiture ceremony in Madras for military honours The Minister of Defence has to go there. This change has arisen because the House took more time than that indicated in the schedule.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Which is more important—Parliament work or some other work?

Mr. Speaker: Both are important.

Shri Satya Narayan Sinha: There is no difficulty in this.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): The notice is very short.

Shri Satya Narayan Sinha: The Rehabilitation Ministry have not much to say about it.

13·12 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE—*contd.*

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिये एक समाचार था कि हमारे ऐसे भी अच्छे अच्छे दोस्तों ने, जैसे कि श्री अशोक मेहता जी हैं, एक ओर तो सरकार को यह राय दी कि स्टेट ट्रेडिंग जारी की जाय, और उन्होंने बताया कि यह राय सितम्बर, १९५८ में दी गई थी, और दूसरी ओर मार्च, १९५९ में वे उस जत्थे में शरीक हुये जो कि इस चीज का विरोध करने के लिये किया गया था ।

Shri Asoka Mehta: May I correct my hon. friend? I did not sympathise with them. If the foodgrains merchants have any complaints against some suggestions I have made, I think democratic etiquette demands that one should go and listen to what they

have to say I do not understand how it is inconsistent.

I think it is very consistent.

Dr. Ram Subhag Singh: It may not be inconsistent that way, but it is inconsistent in the sense that the Government are also guided by the opinion of persons who go and advise Government to resort to certain action and also go to advise persons to resort to action to oppose those actions. Anyway, I accept his correction (*Interruption by Shri Hem Barua*) I know Shri Hem Barua He has gone only to listen to their advice. If somebody goes to Tibet to listen to the Chinese people, that will also be better .....

Shri Hem Barua (Gauhati)· You go and see the killing of the people there.

Dr Ram Subhag Singh: If you want to go there, you can go and see how the palace of the Dalai Lama is being shelled. I do not know whether it is being shelled or not. But if you want to advise them in one way and advise the Dalai Lama in another way, I think it won't be very consistent!

Shri Hem Barua: On a point of order. This is very cruel He did not mean it. He went there just to know the reaction of the people. Democratically, he has a right to do so. To interpret it like this is very unkind to him.

Mr. Speaker: The hon. Member (Dr. Ram Subhag Singh) will address the Chair.

Dr Ram Subhag Singh: In that way Shri M. R. Masani also sometimes advises Government. There I want to correct the Government also. The Government ought to be careful about persons who sometimes go to advise them on some action and on another occasion they go and advise others who are extremely critical of the actions of the Government.

अब मैं इस बात पर आ रहा हूं कि अभी तक जो बातें कही गईं उनमें ज्यादातर खाद्य समस्या के बारे में कही गईं। कैसे खाद्य का उत्पादन बढ़ाया जायेगा, इसके बारे में भी तजवीज दी गई लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी कि दी जानी चाहिये। आज हम लोगों की समस्या, और सरकार भी कहती है कि उन लोगों की समस्या, इसलिये विकट होती जाती है कि हमारी आबादी बढ़ती जाती है। इस बात को मैं भी मानता हूं कि आबादी बढ़ रही है और प्रति दस वर्ष करोड़ों की आबादी बढ़ रही है। सन् १९४१ से १९५१ तक इसमें १३ २ प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन यदि हम दूसरे देशों में जो आबादी की वृद्धि हुई है उसको देखें तो इससे हमें हिचकने की जरूरत नहीं है। सन् १८७१ से १९२१ तक, भारत में आबादी की वृद्धि हुई ५२ प्रतिशत, इसी समय के दौरान ब्रिटिश आइल्स में हुई ५७ प्रतिशत, जापान में हुई १२० प्रतिशत और अमरीका में हुई २३० प्रतिशत। यहां यह कहा जा सकता है, चाहे आप भूमि के उत्पादन करने की क्षमता के लें या हमारी अथवा सरकार की उत्पादन करने की क्षमता, कि हमारी उत्पादन को बढ़ाने की शक्ति सीमित है इसलिये उत्पादन जोरों से नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन यह भी मैं बहुत ज्यादा मानने को तैयार नहीं हूं। यदि हम आबादी के लिहाज से देखें तो जितनी हमारी बढ़ती हुई आबादी बढ़ती है उसको खिलाने के लिये हमको ७० मिलियन टन अनाज की जरूरत थी सन् १९५१ में और करीब ८५ मिलियन टन की जरूरत होगी सन् १९६०-६१ में।

२९ तारीख के स्टेट्समैन में निकला था कि एक्स्टेंशन कमिश्नर की रिपोर्ट जो है कि इस वर्ष हमारा उत्पादन ७० मिलियन टन होगा। यानी इस वर्ष जो उत्पादन होगा वह जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उससे

[डा० राम सुभग सिंह]

करीब ४ मिलियन टन कम होगा । हमारे लिये करीब ७३ या ७४ मिलियन टन अनाज होना चाहिये था जो कि करीब ४ मिलियन टन कम हुआ । और आगे यदि हम देखें तो हमको सन् १९६१ में ८५ मिलियन टन अनाज चाहिये और सन् १९७१–७२ में ९६ मिलियन टन अनाज चाहिये । अगर हम सन् १९७१ को छोड़ भी दें तो क्या हम इस लायक हैं कि हम एक या दो वर्षों में अपना उत्पादन बढ़ा कर ८५ मिलियन टन अनाज पैदा कर सकें । जब हम इस चीज की ओर ध्यान देते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमारी शक्ति ऐसी है ? हमारे मित्र ने अभी कहा था कि कोई आदमी इस सदन में है जो कांशिएन्शसली, ओपन हार्ट से कह सके We are having a clear vision about this. मैं तो समझता हूं कि

The people of India are quite competent and they are having a very clear vision, if they are only freed from the theoreticians of this country. By 'theoreticians' I do not mean anybody. I mean everybody.

Shri Hem Barua: It is a general statement.

Dr. Ram Subhag Singh: They may be on any side including that of Shri Barua.

Shri Hem Barua: I know that.

Shri Braj Raj Singh: (Firozabad): What about the Food Minister and his Deputies?

Dr. Ram Subhag Singh: Yes.

अब सवाल यह उठता है कि इस चीज को कैसे किया जा सकता है । जो रिपोर्ट २१ तारीख को निकली थी, उसमें दिया हुआ है :

"Reports of harvests from most of the nine States where the drive for higher production of Rabi foodgrains was launched in September indicate at least 20 per cent increase in production now coming to a close."

इसे पढ़ कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि रबी कैम्पेन के कारण यह वृद्धि हुई । अगर उसकी वजह से यह वृद्धि हुई तो मैं उसकी पूजा करूंगा और चाहूंगा कि इस कैम्पेन को ज्यादा से ज्यादा तरक्की दी जाय सरकार की ओर से और जनता की ओर से । लेकिन अगर इस कैम्पेन के कारण वृद्धि नहीं हुई तो क्या होगा ? क्योंकि जब सन् १९५३–५४ में अच्छे मानसून के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई तब भी सरकार या प्लैनिंग कमीशन यह दावा करने लगे थे कि यह वृद्धि हम लोगों के इरिगेशन को बढ़ाने से और अच्छे अच्छे उत्पादन के तरीकों को बढ़ाने से, अच्छे सीड्स के देने से हुई है । चाहे भगवान की कृपा से ही यह वृद्धि हुई हो लेकिन ऐसा दावा करने वाले बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं । ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स की छानबीन करा लिया करें क्योंकि जो बड़े बड़े उच्चाधिकारियों की ओर से स्टेटमेंट दिये जाते हैं उनमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं । और जो बात कही गई यदि वह सत्य है, यदि केवल इस कैम्पेन से ही २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो और किसी कैम्पेन की जरूरत नहीं है । इसके अलावा दूसरी कैम्पेन भी हम चला सकते हैं । बहरहाल इसे मैं यहीं पर छोड़ता हूं । मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा तरक्की हमारे उत्पादन में हो अगर उसमें सचमुच हमारी कैम्पेन सहायता पहुंचा सकती है ।

मेरी समझ से उत्पादन बढ़ाने के लिये स्टेट ट्रेडिंग में आज कोआपरेटिव इन्स्टिट्यूशनल चेन्जेज लाने की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है । लेकिन अगर कोई समझे कि वह किसी अफसर को नियुक्त कर दे और उससे प्रदेश या जिले या गांव में उत्पादन बढ़ जायेगा, तो वह असम्भव सी चीज है ।

यह ऐसी चीज है जिसे कोई किसान मान नहीं सकता। ऐसी हालत में यह चाहिये कि जो भी इन्स्टिट्यूशनल चेन्जेज हम करायें वह किसानो के मन के अनुकूल करायें। अगर उनके मन के अनुकूल होने की हम चिन्ता न करें और श्री तुलसीदास किलाचन्द ऐसे पूंजीपतियो के सुझावों को ही मानें, जैसे कि उन्होने कहा है कि खेतों को मेंड़ तोड़ दी जाये तो आसानी से ट्रैक्टर चलाये जा सकते हैं, तो उसमे काम नहीं चलेगा। मैं यह नहीं कहता कि यह सुझाव अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन इस चीज की आप देखिये कि चाहे वे कैपिटलिस्टों के सुझाव हों या बड़े से बड़े रेडिकल के, लेकिन वह किसानों की इच्छा के अनुकूल होने चाहियें। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि किसी के भी सुझाव हो, जो चीजें मदद के रूप में सरकार की ओर से या जनता की ओर से की जा सकती हैं, वे की जानी हैं। कुछ बड़े किसान भी सरकार से यह सहायता आसानी से ले सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे किसान जो हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक कोआपरेटिव फारमिंग करते हैं उनको यह सहायता नही मिल पाती। हम देखते है कि एक किसान जिसके पास एक बैल है वह दूसरे किसान के साथ मिल कर हल चलाता है या दो तीन चार किसान मिल कर हल चलाते हैं। ये लोग कोआपरेटिव ढंग से काम करते हैं, लेकिन कोई कोआप-रेटिव डिपार्टमेंट उनकी मदद करने नही आता। मदद तो दूर रही उनकी समस्याओ का अध्ययन भी नही किया जाता। अध्ययन किया जाता है बड़े बड़े लोगो की फार्म्स का, चाहे वह कोआपरेटिव हो या न हो। और उनके फेल्योर से किसान का फेल्योर नापा जाता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं हो सकता। तो मैं इन चीजों को गलत समझता हू। अगर सचमुच कोई चाहता है कि इन्स्टिटयूशनल चेन्जेज हो, और सबको यह चाहना चाहिये, तो आप सब-डिवटेंड होल्डिंग्स को बदलें और चाहे बड़े बड़े फार्म बनायें, लेकिन यह काम केवल हवाई कल्पना से नही हो सकता। कहीं भी धान का खेत मेंड़ तोड़ने से नहीं होगा। धान के खेत में मेंड़ की जरूरत हमेशा रहेगी क्योंकि पानी को घेरने की जरूरत होती है। हा गेहू की खेती उस तरह से हो सकती है। लेकिन उसमें भी जब आप ४० हार्स पावर का ट्रैक्टर चलायेंगे तो ४० जोड़ी बैल बेकार हो जायेंगे, ४० हल चलाने वाले बेकार हो जायेंगे पानी पिलाने वाले बेकार हो जायेंगे यह भी आपको सोचना चाहिये।

आज करीब ३०० मिलियन एकड़ जमीन हमारे जोत में है जिसमें से मुश्किल से २० परसेंट सिंचाई वाली जमीन है। इस २० प्रतिशत सिंचाई वाली भूमि मे भी यह सम्भव नही है कि एक हजार एकड़ का लेविल होल्डिंग बनाया जा सके जिसमें दो को तीन तीन इंच पानी बराबर रह सके। बहुत डेवेलप्ड देशो में शायद यह लेविल सम्भव हो सके लेकिन यहा तो असम्भव है। इस मामले में हम तुलसीदास किलाचन्द के दिमाग से काम नहीं कर सकते और न उन लोगो की राय से काम कर सकते हैं जो दूसरे देशो की बात कहते है। मान लीजिये कि नैनीताल में कोई खेती करना चाहे तो वहा बड़े खेत कैसे सम्भव हो सकते है। जहा मैदान में सिंचाई वाली भूमि है वहा मुमकिन है कि यह कुछ सम्भव हो सके। लेकिन धान के लिये यह तरीका ठीक नहीं हो सकता। गेहू के लिये किसी हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिये भी बहुत बड़े खेत बनाने में कठिनाई होगी।

मेरे विचार में जरूरत इस बात की है कि हमें छोटी छोटी मशीनो को ईजाद करनी चाहियें क्योंकि जब तक हमारे इम्प्लीमेंट नही सुधरेंगे तब तक हमारा उत्पादन नही बढ़ सकता। हमें कंसालिडेशन भी करना होगा हालांकि इसमें भी हम चकबंदी की बहुत चर्चा सुनते है। अभी तक २,३०

[डा० राम सुभग सिंह]

मिलियन जमीन में से जिस पर कि हमारे यहां खेती होती है, केवल १६ मिलियन जमीन का कंसालिडेशन किया गया है। हमको अपने यहां ४० और ६० हार्स पावर के ट्रैक्टर नहीं चाहिये हमको तो छोटे छोटे ट्रैक्टर बनाने चाहिये जैसे कि जापान में बनाये गये हैं। उनका खर्च थोड़ा होता है, एक आदमी उनको चला सकता है। फिर आप देखें कि हमारे यहां कितने ऐसे गांव हैं जिनमें कि एवरेज में एक हजार एकड़ खेती की जमीन हो। जब हमारे यहां इतने बड़े गांव ही नहीं है तो फिर एक हजार एकड़ के फार्म कैसे हो सकते हैं। अमरीका और कनाडा में यह सम्भव हो सकता है। कनाडा मे एवरेज होल्डिंग २३४ एकड़ का है। पर यहां पर तो ५ एकड़ से कम के करीब ५६·१ परसेंट होल्डिंग है। तो इसमें यह सारी बातें सोचनी समझनी होंगी।

फिर खाद का सवाल है। हमारे यहां धरती में से जो शक्ति हर साल निकल जाती है उसको पूरा करने के लिये हमें चार मिलियन टन खाद चाहिये। पर इस बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा है कि हम इतना रासायनिक खाद पैदा कर सकते हैं। तो फिर खाद कैसे दिया जा सकता है। हमारे यहां जो गोबर के रूप में खाद होता है उसका ४० प्रतिशत हम जला देते हैं। अगर इसके लिये कोयला सबस्टीट्यूट के तौर पर दिया जा सके तो वह खाद काम आ सकता है। फिर सिंचाई का सवाल है। मैं कहता हूं कि खेत की उपज बढ़ाना उस समय तक मुश्किल है जब तक कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंचाई आदि तमाम जरूरी चीजों को अपने सामने न रखे। जब खेती के लिये मुख्य जरूरी सारी चीजें किसान को दी जायेंगी तभी उसका उत्पादन बढ़ सकता है।

फिर हमारी कैटिल वैल्थ की भी बात है। हमको उनकी भी ठीक देख रेख करनी चाहिये।

हमारे यहां जमीन पर बहुत बड़ी संख्या में लोग निर्भर कर रहे हैं। हमारे यहां एक भी एकड़ पर डेढ़ सौ आदमी निर्भर करते हैं जब कि दूसरे देशों में दस, पांच या छः आदमी इतनी जमीन पर निर्भर करते हैं।

13.38 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जब हमको इतने आदमियों को खेती पर सपोर्ट करना है फिर भी हमारे यहां यह हालत है कि कही कोई कारखाना बनता है या कोई योजना बनती है, जैसे कि सिंदरी का कारखाना या भाखरा नंगल का बांध, तो उन गांवों से जो किसान हटाये जाते हैं उनको काम नही मिलता। मैं स्टेट एंटरप्राइज के मामले में किसी का नाम नही लेना चाहता लेकिन मैं देखता हूं कि स्टेट एंटरप्राइज में व्यापारियो की शक्ति बहुत बढ़ा दी गई है। आज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यापारी बाजार में गड़बड़ करता है तो उसको शान्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी को सारी स्टेट की ताकत मिल जायेगी तो उसको नियंत्रित करना असम्भव हो जायेगा। तो इस अवसर पर इसलिये मैं इस बात का बहुत मजबूती से समर्थन करता हूं कि गांव गांव में कोआपरेटिव का निर्माण हो जिसका प्रोडक्शन और मारकेटिंग दोनों से सीधा सम्बन्ध हो। लेकिन यह काम केवल अफसर बहाल कर देने से नही हो सकता। उस अवस्था में तो वैसा ही काम होगा जैसे कि मास्को को जो जूरी भेजे गये थे सारे के सारे ठीक नही थे और उस मामले की जांच भी नहीं हो पायी। तो व्यावहारिक रूप से हम उन चीजों की ओर कदम बढ़ाना चाहते और सब से ज्यादा जरूरत है जमीन की उर्वरा शक्ति

को बढ़ाने की और इसके लिये मुख्य रूप से सिंचाई की जरूरत है । अगर हम चार मिलियन केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दे सकते, ग्रीन मेन्योर काफी मात्रा में नहीं दे सकते तो हमको गोबर को बचाने के लिये जलाने का कोयला देना चाहिये ताकि गोबर को खाद के रूप में काम में लाया जा सके । पर यह काम आसानी से नहीं हो सकता । इस दिशा में ठोस काम करना होगा । हमारे किसान में पैदावार बढ़ाने की बहुत शक्ति है अगर उसकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा किया जाये और उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाये । कहा जाता है कि हमारे यहां सन् १९५०-५१ में १७ प्रतिशत खेती की जमीन में इरिगेशन होता था । उसको पहली योजना में बढ़ा कर १९·७ मिलियन कर दिया जायेगा और दूसरी पंच वर्षीय योजना में उसको ३० मिलियन कर दिया जायेगा । लेकिन आपने जहां नहरें या ट्यूब वैल लगाये हैं उनका उपयोग करने में आज किसान हिचकिचाता है हमारे पास इन लोगों की हजारों दरख्वास्तें आती हैं कि नहर के एरिया में नाजायज कार्रवाई हो रही है, ट्यूबवैल एरिया में समय पर पानी नहीं मिलता । कल मैं इरिगेशन मिनिस्टर से कह रहा था कि नहर के एरिया में ऐसा होता है कि एक किसान को १२ रुपया देना है पर उसके पास परचा आता है ५७ रुपये का । अब आप उसके हिसाब की उलझनता को समझ सकते हैं । जब तक उसका परचा ठीक नहीं हो जायेगा वह परेशान रहेगा और अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगा तो आप देखें कि इन बातों से कितनी कठिनाई एक छोटे किसान को हो सकती है ।

आज हमारी सरकार कहती है और प्लानिंग कमीशन भी कहती है कि हमने इतने ट्यूबवैल लगा दिये हैं, इतने बांध बना दिये हैं । लेकिन हालत यह है कि ट्यूबवैल चलाने के लिये बिजली नहीं मिल रही है और बांधों के पानी के लिये नहरें नहीं बन रही हैं ताकि उस पानी का सदुपयोग हो सके । और उत्पादन बढ़ सके । आज आप देखें कि रेहन्द बांध एक डेढ़ साल में बन कर तैयार होने वाला है और उसका पानी सोन में गिरेगा पर सोन पर अभी तक बांध नहीं बन रहा है जिसकी चर्चा प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही थी । इस कारण बाद में अनेकों बखेड़े उठ खड़े हो सकते हैं । उस की नहरें बन कर तैयार हैं । उन से आठ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ओर रिहंद डैम बना दिया, लेकिन दूसरी ओर सोन बांध नहीं बनाया, तो को-आर्डिनेटिड ढंग से काम नहीं होगा । हम देखते हैं कि लोगों के खाने की मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि अन्न उपलब्ध नहीं है । प्रति व्यक्ति एक औंस अधिक अन्न देने के लिये दो मिलियन टन अन्न की जरूरत है । एक हजार स्क्वायर माइल्ज में, रिहंद डैम के पानी का उपयोग सोन बान्ध को बना कर कर सकते हैं, इससे दो मिलियन टन उत्पादन बढ़ सकेगा । लेकिन कठिनाई यह है कि वैसे को-आर्डिनेटिड थिंकिंग का अभाव है । आज को-आर्डिनेटिड थिंकिंग की आवश्यकता है । वहां पर के रोड्ज पर पुल होने से कोयला इधर पहुंचाया जा सकता है, जो कि आज तक संभव नहीं हो रहा था ।

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, इस समय देश में जो स्थिति है, उस की दृष्टि से हमें मानना होगा कि अधिक अन्न-उत्पादन हमारे देश की सब से बड़ी समस्या है और जब तक इस समस्या का हम किसी न किसी प्रकार हल नहीं करते, तब तक हम चाहे कितनी ही पंच-वर्षीय योजनायें बनाते जायें, उन में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । जिस समय प्रथम पंच-वर्षीय योजना समाप्त हो कर द्वितीय पंच-वर्षीय योजना हमारे सामने आई, उसी समय मैंने एक बात कही थी कि द्वितीय पंच-वर्षीय

[सेठ गोविन्द दास]

योजना में अधिक अन्न-उत्पादन की तरफ और खेती की उन्नति की तरफ सब से पहले ध्यान न दे कर जो उद्योग-धंधों की प्रगति की तरफ़ ध्यान दिया गया है, यह ग़लत बात की गई है। मैंने यहां लोक सभा में भी कहा था और बाहर भी निवेदन किया था। मैं आशा करता हूं कि अब जैसे-जैसे तृतीय पंच-वर्षीय योजना बनने का समय आता जा रहा है, इस बात पर सब से अधिक ध्यान दिया जायेगा, हम फिर उस ग़लत रास्ते नहीं जायेंगे, जिस रास्ते हम द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के समय गये थे और तृतीय पंच-वर्षीय योजना में हम सब से अधिक ध्यान खेती और अधिक अन्न-उत्पादन की ओर देंगे।

जहां तक खेती और अन्न-उत्पादन का प्रश्न है, वहां तक अनेक बातें हैं, जिन की तरफ हम को ध्यान देना आवश्यक है। मैं अपने मित्र डा० राम सुभग सिंह से बिल्कुल सहमत हूं कि मोटे तौर से देखा जाये, तो अधिक अन्न-उत्पादन के प्रश्न पर हमें सब से ज्यादा सिंचाई की ओर ध्यान देना है। सिंचाई की हम ने बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई, करोड़ों रुपया उन पर खर्च किया, परन्तु सब से अधिक ध्यान देना होगा हम को छोटी सिंचाई की योजनाओं पर और अभी से इस तरफ हम को ध्यान दे कर अपनी तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सब से ज्यादा महत्व छोटी सिंचाई की योजनाओं को देना है।

दूसरा प्रश्न खाद का है। मैं वैज्ञानिक खाद के विरुद्ध नहीं हूं। कई लोगों का इस सम्बन्ध में मत-भेद है, परन्तु हमारे यहां भी थोड़ी बहुत खेती होती रही है— अभी भी होती है — और मैं उस मत से सहमत नहीं हूं, जो यह कहता है कि वैज्ञानिक खाद के सम्बे दौरान में उत्पादन घट जाता है। परन्तु उसी के साथ केवल वैज्ञानिक खाद से हमारा काम नहीं होने वाला है। हम को कम्पोस्ट खाद भी चाहिये और उस में गोबर का सब से अधिक महत्व है। अभी डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि गोबर का चालीस प्रतिशत जलाने के काम आता है। ठीक बात है। लेकिन हमारे यहां पर गोबर के कुछ गैस के प्लांट निकले हैं। एक जोड़ी बैल के गोबर के लिये जो प्लान्ट लगाया जाता है, उस पर सिर्फ ६० रुपये लगते हैं।

श्री अ० प्र० जैन : ३५० रुपये।

सेठ गोविन्द दास : हमारे यहां ६० रुपये में बना है और मैं कृषि मंत्री जी के बंगले पर उस प्लान्ट को लगा कर सिद्ध कर सकता हूं कि ६० रुपये में बन जाता है।

श्री० रणवीर सिंह (रोहतक) : हमारे बंगले पर भी लगवा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात की जानकारी कैसे हो कि मिनिस्टर साहब का बनाया हुआ प्लान्ट कैसा है और मेम्बर साहब का कैसा है ?

श्री अ० प्र० जैन : मैं तो कबूल करता हूं।

सेठ गोविन्द दास : इस प्रकार के प्लान्ट लगाने चाहिये, जिस से गोबर जलाने के काम भी आ सकता है और उससे खाद भी बन सकती है। उससे जो गैस निकलती है, उस से ईंधन का काम निकल सकता है और गोबर वैसे का वैसा बचा रहता है।

अधिक अन्न-उत्पादन के लिये छोटी सिंचाई, खाद और अच्छे बीजों की आवश्यकता है और जिस की सब से अधिक आवश्यकता है, मुझे इस बात का खेद है कि अभी तक भी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। वह प्रश्न है गाय का। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं और अब तक यह

प्रश्न हल नहीं हो जायगा और जब तक मैं जिन्दा रहूंगा, तब तक हमेशा इस बात को कहता रहूंगा। गाय के प्रश्न को अभी भी गौण दृष्टि से देखा जा रहा है। गाय का सवाल हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक सवाल तो है ही, इस में कोई सन्देह नहीं, परन्तु उसी के साथ आर्थिक दृष्टि से भी सब से महत्वपूर्ण यह सवाल हो गया है। स्वराज्य प्राप्त हुये हम को बारह वर्ष हो गये। बारह वर्ष का एक युग बीत गया और हम देखते हैं कि यह प्रश्न अब तक सुलझा नहीं है। इतना ही नहीं, वह अधिक से अधिक उलझता जाता है और जटिल होता जाता है।

पहले गोवध के सवाल को लीजिये। यह सर्वविदित है कि मैं सम्पूर्ण गोवध-बन्दी का पक्षपाती हूं, परन्तु यदि इस प्रश्न को एक ओर रख दिया जाये, तो भी प्रश्न यह है कि क्या उपयोगी पशुओं की भी रक्षा बिना गोवध-बन्दी के हो सकती है। मैं अनेक बार इस बात को सिद्ध कर चुका हूं कि उपयोगी पशुओं की रक्षा भी गोवध के कतई बन्द होने पर ही सम्भव है। कहा जाता है कि स्वराज्य के बाद जहां तक गोवध का सवाल है, वह कुछ कम होता जा रहा है। यह बात भी गलत है। पहली बात चमड़े के निर्यात के सम्बन्ध में लीजिये—१९४६-४७ में कुल ७,४५,००० चमड़ों का निर्यात हुआ था, जिसमें ६,२५,००० गायों का चमड़ा था और १,२०,००० बछड़ों का चमड़ा था। १९५१-५२ में यह संख्या ६४,००,००० तक पहुंच गई जिस में से १८,५३,००० बछड़ों का चमड़ा था और ४५,००,००० गायों का चमड़ा था। १९५५-५६ में यह संख्या करीब ८०,००,००० तक पहुंच गई, जिस में से २६,००,००० बछड़ों का चमड़ा था और ५३,९२,००० गायों का चमड़ा था। स्वराज्य-प्राप्ति के समय चमड़े का निर्यात ७,४५,००० था और नौ दस वर्ष के बाद १९५५-५६ में यह ८०,००,००० तक पहुंच गया और उसमें बछड़ों का चमड़ा २६,००,००० है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बछड़े अनुपयोगी कहे जा सकते हैं। इस के सिवा जिन गायों का चमड़ा जाता है, वे गायें अच्छी से अच्छी होती हैं। गोमांस का निर्यात यहां पर बन्द हो गया था। अभी गये २८ मार्च को ही एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कृषि मंत्री जी ने कहा —

"The export of beef was banned w th effect from 11th May, 1954 except as shipped stores. It was placed on O.G.L. from 8th July, 1952 in pursuance of the export drive initiated by the Government of India".

क्या यह हमारे लिये लज्जा की बात नहीं है कि स्वतन्त्र भारत से गोमांस आज भी बाहर जाता है और पाकिस्तान को जाता है? मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को इस देश से गोमांस जाना हमारे लिये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की चीज है।

श्री ब्रज राज सिंह : कौन-कौन डूबेगा इसमें ?

सेठ गोविन्द दास : आप बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि में कसाई खानों को देखें। वहां पर उपयोगी पशुओं का वध किया जा रहा है।

आप निरुपयोगी पशुओं की बात को ही लीजिये, उनकी बात को लीजिये जिन को बेकाम पशु कहा जाता है। विशेषज्ञों की राय है कि हमारे यहां पर जितने पशु हैं उनमें से केवल दो परसेंट ही बेकाम हैं। फिर इन बेकाम पशुओं को भी अगर गोसदनों में रखा जाये तो इन पर व्यय होगा वर्ष भर में केवल ३० रुपये और उनसे गोबर आदि हमको मिलेगा ४५ रुपये मूल्य का तथा चमड़ा मिलेगा वह अलग से है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : गोवध का इस विभाग से क्या सम्बन्ध है ?

सेठ गोविन्द दास : जब तक बैल न हों, गायें न हों और तब तक बैलों और

[सेठ गोविन्द दास]

गायों का खात न हो, तब तक आपके यहां पर फूड का मसला हल नहीं हो सकता, फूड पैदा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा भ्रम है कि अधिक अन्न उत्पादन से गोवध का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधिक अन्न उत्पादन से जिस चीज का सब से अधिक सम्बन्ध है, वह गोवध से है। इस वास्ते गोवध को रोकना एक दम अनिवार्य है।

इसके साथ ही साथ नसल-सुधार की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। आप कहते हैं कि नसल-सुधार हुआ है। मैं समझता हूं कि सुधार की बात तो दूर, बिगाड़ हुआ है। यह इसी से सिद्ध हो जाता है कि हमारे यहां दूध का उत्पादन घटा है। १९५० में करीब ५२ करोड़ मन दूध होता था। १९५५-५६ में वह ४७ करोड़ मन रह गया। १९५१ में एक गाय प्रतिवर्ष ४१३ पाउंड दूध देती थी, अब देती है ३६१ पाउंड। यह सब क्यों हुआ है? इसमें विशेषज्ञों की सब से बड़ी गलती है। हमारे ये विशेषज्ञ कोई अपनी विशेष राय नहीं रखते। एक समय इनकी एक राय होती है, दूसरे समय इनकी दूसरी राय हो जाती है। ऐसे विशेषज्ञों को जब इस प्रकार के प्रश्न सौंपे जाते हैं तब उनमें सुधार न हो कर बिगाड़ होता है। मैं एक बहुत बड़े विशेषज्ञ का नाम ले रहा हूं, श्रीमान् नंदा जी। श्री गुलजारी लाल नन्दा से मेरा मतलब नहीं है, यह एक दूसरे नंदा जी हैं जिन का नाम प्राण नाथ नंदा है। ये सरकार के एक बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। १९४७-४८ में जब एक फैटल डिवेलेपमेंट कमेटी बनी, जिसका मैं भी एक सदस्य था और मेरे मित्र ठाकुर दास भार्गव जी भी उसमें थे और नंदा जी भी थे...

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी बतौर विशेषज्ञ के उसमें थे?

सेठ गोविन्द दास : जी नहीं, मैं अपने आप को विशेषज्ञ नहीं मानता हूं। नंदा जी विशेषज्ञ के रूप में थे और मैं एक साधारण सदस्य के रूप में था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : मैं उस कमेटी में नहीं था।

सेठ गोविन्द दास : आप न होंगे।

१९४७-४८ में इन नंदा जी ने उसके एक विशेषज्ञ मैम्बर की हैसियत से इस बात पर हस्ताक्षर किये थे कि इस देश में गाय का प्रश्न हल होने के लिये हमें गोवध कतई बन्द करना चाहिये। १९५५-५६ में जब एक दूसरी कमेटी बनी श्री नंदा जी के ही सभापतित्व में, तो उन विशेषज्ञ महोदय की विशेष राय बदल गई और यद्यपि उस कमेटी के टर्म्स आफ रेफ्रेंस में गोवध का विषय नहीं था, लेकिन खींच तान कर इस विषय को लाया गया और १९४७-४८ की राय के ठीक खिलाफ उन्होंने यह राय दी कि इस देश में गोवध होना चाहिये। इस देश को.....

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : आप मैम्बर थे, आपने उन से इस बारे में पूछा नहीं कि क्यों वह दूसरी राय दे रहे हैं?

सेठ गोविन्ददास : मैं इस कमेटी का मैम्बर नहीं था, पहली कमेटी का मैम्बर था। ऐसे विशेषज्ञों से भगवान हमारी सरकार और इस देश को बचाये और इस प्रकार के विशेषज्ञों की राय पर अगर हमारी सरकार और हमारा देश चलता है तो इससे अधिक और कौन सी खेद की बात हो सकती है, कोई नहीं हो सकती।

अन्त में संक्षेप में मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की इस विषय में स्पष्ट नीति होनी चाहिये।

इतने वर्ष बीत जाने पर भी सरकार की कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं हुई है। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि सम्पूर्ण गोवध, मेरे मतानुसार बन्द होना चाहिये। इसके सम्बन्ध में अगर केन्द्र का कोई कानून नहीं बन सकता है तो संविधान की धारा ४७ और ४८ के सम्बन्ध में जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अनुसार हर राज्य में कानून बनने चाहियें। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि खादी और ग्रामोद्योग के सदृश ही गोसंवर्द्धन एक स्टेच्युटरी बाडी हो जानी चाहिये। चौथा सुझाव यह है कि गोचर भूमि की रक्षा और सिंचाई से बरसीम, रिजका, मैंगोलु, गिनी आदि चारे की उत्पत्ति होनी चाहिये और साइलेज आदि का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये। पांचवा सुझाव मैं यह देना चाहता हू कि गो सदनों की स्थापना होनी चाहिये और उनको ठीक ढग से चलाने का प्रबन्ध होना चाहिये। छठा सुझाव यह कि जो अच्छे पिंजरापोल हैं उनको सहायता दी जानी चाहिये। सातवां सुझाव येह देता हू कि स्थानीय नसलो की उन्नति होनी चाहिये और एसी नसलें तैयार होनी चाहियें जिन को ड्यूअल परपज की नसल कहते हैं जिसमें अच्छा दूध देने वाली गायें हो और अच्छे ही खेती करने के लिये अच्छे बैल हो। मेरा आठवां सुझाव है कि गवार आदि जो पशुओ के खाद्य पदार्थ हैं, उनका निर्यात बन्द होना चाहिये। साथ ही चारे के यातायात में रेल के किराये में कमी होनी चाहिये। मेरा अन्तिम सुझाव है कि १९५५ की जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट और उसके साथ उन विशेषज्ञों को गहरी से गहरी खदक खोद करके उसमें..

एक माननीय सदस्य : उन विशेषज्ञों को ?

सेठ गोविन्द दास : उनके लिये मैं न ीं कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट के बारे में और उनकी राय के बारे में कह रहा हूं..

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : आप तो अहिंसावादी हैं।

सेठ गोविन्द दास : मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय को गाडा जा सकता है। मैं गलती कर गया अगर मैं उनको ही कह गया। और १९४७-४८ की हमारी जो समिति थी, उसकी जो राय थी, उसके अनुसार काम होना चाहिये।

इन सब बातों के साथ ही साथ गो चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये।

अन्त में मैं कहूंगा कि गांधी जी, राष्ट्रपति जी, विनोबा जी, दयानन्द जी, मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, आदि के गाय के सम्बन्ध में जो विचार हैं उनको सभी जानते हैं। पर मैं यहां अपने भाषण का अन्त करूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी की ज बनो के उद्धरण पढ़ कर मालूम होगा कि उन्होंने गाय के बारे में क्या कहा है और उसे क्या माना है :—

> "भिन्न भिन्न देश वालों ने भिन्न पशु-पक्षियों को अपनी महत्वाकांक्षा या अपने चारित्र्य का प्रतीक बनाया है। उकाब संयुक्त राज्य अमरीका का, सिंह जर्मनी का, बुलडाग इंग्लैंड का, लड़ाकू मुर्ग फ्रांस का और भालू पुराने रूस का प्रतीक है। सवाल यह है कि ये संरक्षक पशु-पक्षी राष्ट्रीय चारित्र्य को किस तरफ ले जायेंगे। इनमें से ज्यादातर तो आक्रमणकारी, लड़ाकू और शिकारी जानवर हैं। ऐसी दशा में यह कोई ताज्जुब की बात नही है कि जो लोग इन नमूनों को अपने सामने रख

[सेठ गोविन्द दास]

कर अपना जीवन निर्माण करते हैं वे जान बूझ कर अपना स्वभाव वैसा ही बनाते हैं, आक्रामक रूप अख्तियार करते हैं, दूसरों पर गुर्राते हैं, गरजते हैं और झपट पड़ते हैं। और यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हिन्दू नरम अहिंसक है, क्योंकि उनका आदर्श पशु है गाय।"

मैं कहना चाहता हूं कि गाय पंचशील के जो सिद्धान्त हैं उनका भी एक प्रतीक है। जहां पर पंडित जी ने गाय के सम्बन्ध में . . .

उपाध्यक्ष महोदय : पंचशील में कोआपरेशन पहला है। मैं चार बार घंटी बजा चुका हूं और आप परवा ही नहीं कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : मैं अभी खत्म कर रहा हूं।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर समुचित रूप से ध्यान देगी क्योंकि जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया है कि अधिक अन्न उत्पादन और खेती के प्रश्न से हमारी गाय का बहुत निकट का सम्बन्ध है।

Mr. Deputy-Speaker: I would request hon. Members not to exceed the limit of 15 minutes. They come and whisper into my ears that they would not exceed 10 minutes, but when they are called, they would not stop even after 20 minutes.

श्रीमती रुक्मिणी देवी राय (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): हमें भी मौका दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो अभी बहुत दूर हैं।

Shrimati Renuka Ray (Malda): I shall try to be as brief as possible. You have asked me to keep to 15 minutes limit, I shall try to do so. We are discussing a subject which is more urgent, more immediate and more demanding than any other in the country, *viz.*, the quest on of self-sufficiency in food for our people. It is something about which Government, the Planning Commission and all of us are aware and measures were taken so that increase of food production and agriculture were given the first priority. Those who say that nothing has been done are wrong. But all the same, in spite of whatever has been done, I think the Government is the first to be aware of the fact that our situation is very critical. Last year, the over-all deficit in foodgrains was 6·7 million tons according to the Government's report. Mr. Naga Reddy has been pleased to be very amusing at the expense of . . .

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): His name is Nagi Reddy and not Naga Reddy.

Shrimati Renuka Ray: I am sorry. Mr. Nagi Reddy said that they have shown a spirit of self-justification and complacency throughout. It all depends on the angle of vision from which you look upon a report or upon any work. I was glad that in spite of the very critical situation, the angle of vision of this report is that we will not succumb to a policy of suicide, but we shall try to do something. That is one way and the other one which he adopted was that since there are difficulties, you should commit suicide; probably he wants us to. That was his outlook. Certainly, we have a very critical situation. The Ministry has given food statistics which are very revealing, *viz.*, that while our agricultural production has gone up by about 7·3 per cent, the population has gone up by 12·67 per cent, from 1951. This is very revealing. Obviously, we have to revolutionise our thinking, not only our thinking, but our activity also, if we

are to meet the situation before us. But this is not the immediate need, because howsoever we may revolutionise our activity and thinking, it will take some time.

I would like to deal firstly with the immediate need of today which the consumers and the primary producers in this country are facing. I have said it before and I want to repeat that I do not wish to minimise in any way the difficulties that face the Food Ministry I think the Food Minister at the Centre and his colleagues in the States have a very unenviable task to perform; I do not want to minimise their difficulties in the least. But nonetheless, there are certain points I wish to bring forward.

The first point is in regard to State-trading in foodgrains This has been spoken of for some time and the objective, which the Food Minister mentioned in his statement, is very commendable. He says:

> "The objective of State-trading is to maintain price levels which are fair to the producer and to the consumer and to reduce to the minimum the spread between price received by the farmer and the price paid by the consumer.. ."

What can be a better objective? But how has he armed himself to bring this about? Here I have to confess very frankly that I feel this is the case of the mountain of labour bringing forth the proverbial mouse Are the interim measures going to bring about any results that can possibly be successful? Why has the Food Minister crippled himself to this extent? The seeds of failure are written in these very interim measures I feel that this country must arm the Food Minister and his Ministry better if they are going to give the results of State-trading in this country.

Mr. Nagi Reddy said many things, but he would not face up to the very implications of what this means, because if State-trading is to be brought in, inevitably the corollary of that must be and is, monopoly procurement by Government It means distribution. Howsoever we may have surplus and deficit areas, the over-all picture is one of deficit in this country We must recognise it If we recognise it, we must know that distribution also has to be effective through a system of priorities and rationale. If this is not done, we are really not bringing in State-trading in foodgrains; not only that, we are not really facing upto the issue as we should

The Food Minister has pointed out the administrative difficulties I do not doubt there are tremendous administrative difficulties Shri Asoka Mehta went into the question of warehousing, how it should be increased, etc There are so many difficulties. I want to ask this House—because it is this House which must ultimately give the power to the Food Ministry —when it comes to the question of law and order, do we say, because there are difficulties, because sometimes things go wrong, that there should be no law and order and that Government should divest itself of its powers and that we should allow the law of the jungle to prevail? It is for the people of the country to face up to this. We have not got the mind to do it The hesitant and haulting policy that we see is the result of the fact that we ourselves are confused in our minds in this respect. One of the reasons why we do not like it is because of the light of our past experience Now what was one of the basic differences in the approach then and today? One of the basic differences was that in those days the producer was not, his needs were not, emphasised; it was only the consumer's angle that was emphasised. Today we have an objective that is quite different; the objective is the price support to the producer, fair price to the consumer and elimination of the intermediaries. The object is

[Shrimati Renuka Ray]

clear. If that is so, then let us really empower Government and let the Government come out with such measures as they can carry out to achieve the objectives.

14 hrs.

One of the ultimate measures suggested is the organisation and development of co-operatives of the various types that are required. Then it will be easier for the Government and the people as a whole to be able to carry out this policy properly. But until such time the Government machinery has to function. And if it fails to function, will the Government say: we shall retire because there are certain failures in Government itself?

Therefore, I plead with the Food Minister to look into this matter again, and I ask him to look into this matter again in the light of the experience that we have recently had in a State which has been deficit, in a State which faced a very critical position last year, West Bengal. What happened in West Bengal? And what are the interim measures? Licensing dealers, statutory control of wholesalers and lukewarm support—Lukewarm support, mind you—by retail price control measure, fair price shops and concessions to some States which have certain difficulties, and some annual levy system. These are the interim measures. All these interim measures have failed in West Bengal, and the West Bengal Government have brought in retail price control. They have brought in a levy of 25 per cent. on all rice mills; they have brought in direct procurement through co-operatives for purchasihg paddy at minimum price. They have gone a step further. As the Food Minister has himself stated West Bengal has gone a step further in the matter of State trading than any other State in India. They have done so compelled by the circumstances. But they realise also that there are certain difficulties. One of the difficulties is that just as statutory fixation of wholesale price, if retail prices are controlled only in one State there is difficulty. Therefore, such a measure cannot be effective. So, you have to go further. We want interim measures which will go further. But these interim measures are the ones that have failed in West Bengal, which, as the West Bengal Government pointed out, failed to bring about the expected result. Therefore, the West Bengal Government, after facing for months this tremendous crisis, taking advantage of the circumstances, rose up to the position with the result that now in the month of March this year the price was lower than that of last year by some points. I do not know the exact amount of price but in March this year the price of cereals is lower by 2·59 per cent. And that is due to those other measures brought in from January this year. But that is not the only thing. The Central Government has come to the aid of the State Government, because it is a zone that has always been deficit. The Government there in the past used to buy from the country outside as well as from other areas in the State. The Central Government has come to their aid to the extent of 8 lakh tons from the Central reserves in 1959. They come to our aid in the first few months. Then, about giving help to the State Government people often make a mistake. Help does not mean that the State has not to purchase it. They have to purchase it. Here I would submit that unless most stringent measures are taken the result will not be very satisfactory.

Then I will come to another point. Many people think that West Bengal is getting more of assistance from the Centre than the other States. I wonder how many are aware that after the zonal system was introduced West Bengal is one of the States which was not included along with any surplus area from which it could get something. I heard a great deal—I think it was from Shri Nagi Reddy

—on the question of Kerala Kerala has rice to buy from Andhra Pradesh The Centre also goes to its help. The Centre has realised the difficulties of West Bengal Because, West Bengal has not been linked to any surplus zone. So, naturally it is not possible for West Bengal to do anything but to go to the Centre for help And the Centre, I must own, has come forward in these last months to help West Bengal with the result that that State is now able to face the position The Centre has met the deficit of West Bengal and it has to continue to meet it if the price fixation continues This is the position

Therefore, I would ask the Food Minister that he should take full powers in his hands to deal with the situation Why should he take so little power in this matter that he cannot bring in State trading in foodgrains? I could understand if the position were not one of short supply If there is abundant supply then we could have the normal laws of supply and demand That is not the position now When we are faced with such an urgent situation, will he not empower himself with the necessary powers? His lot, as I said, is an intolerable one and his sincerity of purpose is above question But he will be able to carry out what he wants only by having enough powers to do so

I will turn now to the other side of the picture for a few minutes and that is the question of increase of food production so that there may come a day when we in this country, a predominantly agricultural country can overcome our greatest tragedy and have enough food for our people Now, as I said at the outset, the position is a very difficult one and unless we have a revolutionary change not only in thinking but in our entire activity we canot go ahead Though some suggestions have been made on this matter, I am rather inclined to agree with Dr. Ram Subhag Singh that we continually think theoretically about certain things without going into the details For example, take the details of co-operatives If the co-operatives of today could get over the impediments that they face then only service co-operatives can be successful Then collective farming is not something very far Now sitting in Delhi or Calcutta we think about the farmers and the cultivators Here I want to give one or two examples on our policy Take for instance, the tribals who have shifting cultivation The practice there is cultivating in common They do not have big words such as co-operatives But they do it

Mr Deputy-Speaker: The hon Member should conclude

Shrimati Renuka Ray. I will finish in a few minutes

Now instead of allowing them to do so, they have taken them away from shifting cultivation and settled them on Land We want them to act independently They have a custom We break that Then we talk of co-operatives in other spheres I think it is necessary to bring all these things together and to really follow a pattern that is uniform that goes into the details of these matters, so that we can, in fact be successful

Lack of time makes it impossible for me to go into other matters that I wanted to say, except to say two things I would like the Minister to look into the fact that last year, during the discussion of the Demands for Grants, he made a statement which he made because the Planning Commission had laid it down that outside the Plan provision, minor irrigation schemes would be sanctioned and money allotted He made this statement and I think he did it because he was in the full understanding that this would be done Not only in West Bengal, it may be the same else where Six schemes were sent up and they have been sanctioned They have been asked to find money for them from their present allotments either from Community projects or from agriculture The whole point that

[Shrimati Renuka Ray]

outside the Plan provision, minor irrigation schemes were considered, has not been carried out. I do not think it is the Minister's fault. I would ask him to look into it. It may be that the Planning Commission has not done it. It may be that the directive has not been carried out. Somehow or other it has happened.

Similarly, the State Governments do a similar thing. We have minor irrigation schemes Plans go on from year to year. They do not come to fruition. Yet, in the meantime, we find that lakhs of money gets spent in relief. Because, floods and drought come in an area and relief comes up costing about Rs. 18 lakhs. Fertilisers, manures, seeds are given in much more profusion than before What happens down in the field? The co-operatives wait and wait. They do not come in time. I do not say everywhere. I am not making a sweeping statement. But, the point that a sufficient amount is not put in is something we should take note of

Similarly in regard to fertilisers and seeds, surely, when we have this experience, we can do one thing. This is very important during certain months in the year. Could we not mobilise our resources on this side to see that they reach in time? That at least would certainly improve the food production to a certain extent. It may be that we cannot meet the whole requirement But, it is one of the things that needs particular attention. I do not say that the Central Food Minister can work wonders. But, surely he can try to mobilise and ask each State during a particular period to mobilise many more persons into this work of seeing that distribution takes place in time.

Before I conclude, I have one more appeal to make to the Food Minister, that is, in regard to milk for children. We are short in milk supply. In wartime England, although they faced many privations, there was one thing that they did and that was, priority was given for milk for the children and nursing mothers and the aged. Surely the time has come after a decade when in this country we can bring in such a system. I know there may be difficulties in setting up an administrative system. Surely it can be done. Surely those who buy sweetmeats and luxury goods can give that up for the time being for the health of the country, so that we may have a future generation that would be healthier than they are likely to be today

Before I conclude, I would plead with the Food Minister again to arm himself with powers so that he can really enforce prices in the interests of both the consumer and the producer.

Shri D. R. Chavan (Karad): Mr. Deputy-Speaker, I have heard the debate with rapt attention and considered the crises that are facing our country for the last ten years. What are the basic needs of the country today? Enough food, enough work to buy food The question is whether the Government has been able to rolve this problem

In spite of the fact that serious efforts are being made to increase the country's food production, our country is deficient in food both qualitatively as well as quantitatively, though agriculture is the main and basic industry of the country. What are our difficulties? There cannot be any doubt, it is no use to have a controversy over the point that this country has landed into difficulties. Our difficulties are both internal as well as external Internally we have production shortage, especially of food. Then, there is the problem of rising population; there is the problem of increasing unemployment, constant threat of inflation, lack of people's co-operation, lack of Government efficiency, lack of co-ordination and integrated planning and there is the problem of corruption There are external difficulties too But, the external difficulties I am not

placing just now, because they are irrelevant for today's discussions Let us analyse all these factors and see what they really are

In an agricultural country like India, scarcity of food cannot be a problem But, it is today Some of the factors that have been put forward by the Government in defence of shortage of food production are rapid growth of population, hoarding and inefficient production We have to consider whether rapid growth of population is responsible for food shortage It is no use denying the fact that there is rapid growth of population The Census report of 1951 predicts that our population in 1961 would be 41 crores Considering the rate of growth of population according to the Census of 1951, let us take it for granted that India today is inhabited by 40 crores of people I have read all the reports Nowhere have I found out any calculation made by the Government concerning the country's total food requirements Nowhere have I found any statistics concerning the country's requirements with regard to food I found that the total requirements of the country today are, according to certain calculations made by certain experts, 582 crores oz per day or 611 lakh tons per year I do not know whether this calculation that has been made by some experts, is correct or not But one thing is certain Nowhere do I find this calculation made on the basis of the population by the Government.

As against this, production of foodgrains according to the revised estimate comes to 687 lakh tons during the year 1956-57 and 620 lakh tons in the year 1957-58 What does it indicate? There is a surplus of 76 lakh tons in the year 1956-57 and about 10 lakh tons in 1957-58 The argument will be, there is more than enough food to feed the increasing population and the increasing population cannot be considered responsible for the food shortage The question is, who is responsible for this shortage? This shortage is due to what reasons? Why is this causing considerable difficulties in the economy of the country? How is hoarding responsible? One of the arguments advanced is that the farmers keep some marketable surplus with them Let us see the validity of this argument Let us analyse who is responsible for this shortage, which is causing considerable stresses and strains in the country's economy today. The poor small farmers as well as the masses in general are unable to hoard foodgrains due to want of money To know the real position, it will be necessary for us to analyse the national income Details of the national income tell us about the dependence of the country on different economic pursuits and, as such invite attention to any imbalance that might be there Such studies also bring to light the economically weak spots within the nation Such studies throw light on the distribution of wealth

It has been stated that our national income is to increase from Rs 10,800 crores in 1956-57 to Rs 13,480 crores at the end of the Second Plan and the *per capita* income from Rs 281 to Rs 331 The *per capita* income is no dependable index of the economic conditions of the masses A very large section of the Indian people have income much below the *per capita* figure

According to Professors Shah and Khambata, five per cent of the people constituting the richer classes enjoy more than one-third, that is, nearly thirty-six per cent of the national income Thirty per cent of the people comprising the middle classes enjoy another thirty-three per cent of the national income and the remaining sixty-five per cent of the people are left with almost thirty-one per cent of the national income

On this basis, the *per capita* income of the poorer classes constituting sixty-five per cent of the total population, mostly inhabiting rural India, does not exceed six annas a day This is not his real income The real *per*

[Shri D. R. Chavan]

capita income continues to be very nearly constant in spite of developmental activities Even when considered with respect to the per capita figure of 1959-60, no real change is discernible

From this, it will be clear that more than half of India's total population, that is, twenty-five crores of people, who have hardly thirteen rupees per month to spend on consumer goods and who are mostly unemployed, under-employed, under-nourished and are sunk in indebtedness and who live on a diet inviting all kinds of diseases —comprising the poor farm labourers, small farmers as well as the masses in general inhabiting the rural India— cannot afford to hoard foodgrains

So, the conclusion is The poor farmer is not hoarding Then, who is hoarding? That has got to be seen The All India Rural Credit Survey has brought new evidence about the meagre earnings of the Indian farmers They say

> "About one-third of the cultivating families were found to have a gross produce of the value of less than Rupees two hundred per year and about half of them a gross produce of the value of Rs 400 per year The farm expenses of the farmer exceeded the value of the gross produce by twenty-five per cent All the farmers have to supplement their farm income with other income, the most important source of which is wage employment"

It follows, therefore, that either the statistics supplied by the Government concerning the country's food production are wrong and misleading and that there is general shortage of foodgrains. demand outstripping the supply, or that the statistics are correct and the hoarders, profiteers, and black-marketers are cornering food and creating an artificial scarcity and therefore fully responsible for this.

The root of the evil, Sir, lies in the economic policies pursued by the Government In the statement circulated by the hon Minister and also laid on the Table of the House. we have been told that the primary object of the State trading in foodgrains is to maintain fair price for the producer and the consumer. I want to ask the hon Minister whether this price will take into consideration the cost of cultivation plus a margin of profit I have been hearing terms like, reasonable price, fair price, etc. What is meant by 'fair price'? Does it include cost of cultivation as well as a fair margin of profit That also has to be considered

Shri A P Jain: If it does not include the cost of production and a reasonable profit, it would not be a fair price

Shri Ranga (Tenali) Does it include both?

Shri A. P. Jain: Yes

Shri Ranga: I am glad you gave that assurance

Shri D. R Chavan: I cannot follow what the hon Minister said.

Mr Deputy-Speaker: He said, 't includes both these things

Shri Ranga. Cost of production and a fair margin of profit

Shri D R. Chavan: I want that there should be a categorical assurance that it will include the cost of production and the fair margin of profit. It is no use giving us some misleading ideas. All these talks about stabilisation of prices, fixing reasonable prices etc have led to confusion. If the hon Minister says that it includes cost of production plus margin of profit, I have nothing to say against that. I take it that he has given this assurance to the House.

Coming to the economic policies pursued by the Government, we all know that, in order to cope with the Second Five Year Plan, Government had to depend to a considerable extent on deficit finance more than what they should.

With the rise in the amount of deficit finance, the total money supply has gone up tremendously. It has created a vicious circle of increase in credits and advances and so on. As against this, there is no considerable rise in the prices of national output. It cannot keep pace with the money supply. This paves the way for inflationary forces, which ultimately create temptation to hoarding and blackmarketing.

What is the remedy for this state of affairs? The remedy, to my mind, Sir, lies in increased production Increased production is the most powerful weapon against inflation, unemployment, and increasing cost of the Plan, and it makes for high incomes and standards of living.

The most striking feature of national income estimates is our great dependance on agriculture. According to the National Income Committee of 1954 agriculture provided 51·3 per cent of the national income in 1950-51 According to the Central Statistical Organisation, this contribution was 50·9 per cent in 1953-54 As against this, for the year 1950-51, mining manufacturing and handtrades provided 16·1 per cent. Commerce, Transport and Communications provided 16·9 per cent. Other services provided 14·4 per cent. In the United Kingdom industrial production provides nearly fifty-five per cent of the national income.

The analysis of the national income clearly brings out that agriculture production is of the most vital importance in the country's economy. Agriculture is the soul and the very base of the Plan. The hon. Prime Minister, having realised this, has said:

> "We shall have to work with our sweat and blood to increase our agricultural production, and if we don't, we just don't get on with the Plan".

But, our Food Minister appears to think that food shortage is inevitable, that more food cannot be produced in the country on a large scale without chemical fertilizers and without completing major irrigation projects or utilising fully the irrigation potential already created.

Last year, in the course of his reply in connection with the debate in Lok Sabha, he propounded a novel economic theory. He said:

> "I would say that in a developing economy, self-sufficiency becomes an ever receding ideal, because the demand for food depends upon the tempo of the development and if we are to increase the tempo of development there is likely to be a lag between our production and our demands."

This is the thing that he advocated while replying during last year's debate. What is the conclusion, Sir? The conclusion is that the hon. Minister is difident about the country's capacity to produce more. It is very surprising that such a Minister has been charged with the responsibility of increasing the country's food production As regards the possibilities of increased agricultural output in India, the report of the World Bank Mission to India, which was made in August, 1956 says:

> "Proper application of known techniques, in conjunction with the possible expansion of irrigation and cultivated area, could increase India's agricultural output four or five fold."

It further says:

> "Results of the crop competitions organised for the Grow More

[Shri D. R. Chavan]

Food campaign show yields about seven times higher than the local average. India's yields are at present among the lowest in the world; with the labour force available they could be among the highest. There is thus a great deal of scope for progress that is technically easy but is retarded by poverty and ignorance.".

I only hope that the hon. Minister should have read this report very carefully before propounding his novel economic theory of 'an over-receding ideal in a developing economy'.

Only a bold and well directed agricultural policy backed by enthusiastic drive, and not the policy of apathy and drift can hope to bring about reorganisation of agriculture on the right lines.

During the last ten years, we are nowhere nearer the sight of self-sufficiency as pronounced by Government from time to time. On the contrary, we are feeding our people on the imports from foreign countries

More than 2,87,40,000 tons of foodgrains were imported since 1948-49 up to 1957-58 December. And, for that, we have paid more than Rs. 1300 crores to America, Canada, Australia, Burma and Malaya etc.

In 1945-46 sterling balances of India were of the order of Rs. 1733 crores. These sterling balances were, in fact, the painfully accumulated savings of the Indian people. They represented our sacrifices, sufferings and our blood and tears. These assets which could have been profitably and more fruitfully utilised for purchasing capital goods have all been spent in purchase of foodgrains. And this single item, namely foodgrains, continues to be a very great drain on the country's foreign exchange resources.

To remedy all the ills that have beset our economy, agricultural production is the only hope. Agriculture is the soul of the Indian economy and improvement in agriculture only will enable us to bear the costs of the present and the future plants. It will contribute to the national output, check inflation, earn foreign exchange, augment exports which have been static for the last so many years, and enable us to reduce the inequalities of income to some extent at least, which is one of the principal objectives of the Second Five Year Plan.

I am sorry that this most important sector of our economy has been badly neglected in the Second Five Year Plan. Planning is not simply a balancing of physical and financial resources and outlays, but essentially an ordering of priorities. It is in this respect that the planners of the Second Plan have shown neither wisdom nor realism. The First Five Year Plan assigned a top priority to programmes of agricultural development, but the Second Plan shifted its emphasis to industrial projects.

The outlay on agriculture and community development programmes was reduced from 15·1 per cent. in the First Plan to 11·8 per cent. in the Second Plan. The total financial provision proposed under this head is Rs. 568 crores of which only Rs. 341 crores is assigned for agricultural development. And even under this head, out of Rs. 341 crores, only Rs. 170 crores are to be spent on purely agricultural programmes. If the programmes for which a provision of Rs. 170 crores has been made are further analysed, a sum of Rs. 120 crores is expected to be spent on food production schemes. Sir, it was bad economics, poor statistics and complete lack of prescience that must have guided the Commission to so badly neglect this important sector of our economy. Due to a number of causes, planned and unplanned, there were good crops for successive years. The Commission could not distinguish between real and fortuitous causes and grew complacent about food production. It, therefore, revised its priorities, relegating agriculture to a lower

position. The failure of the Commission in this respect has upset the whole of the Plan.

The Second Plan originally provided for an increase in production of foodgrains, of the order of 15 per cent, or 10 million tons, over the estimated production of 65 million tons in 1955-56. The targets were considered low by the National Development Council and were, therefore, increased to 15·5 million tons of additional foodgrains. These targets have been arbitrarily fixed, and although the National Development Council raised the physical targets, financial allocation for the attainment of the additional target figures was not made

The present policy pursued by the hon. Minister of Food and Agriculture is a policy of apathy and drift, lacking confidence and enthusiasm. It is confined only to three things, namely procurement, distribution and import It, therefore, needs a radical change

The policy should be production-oriented, and the various targets should have corresponding official organisations and Ministers directly responsible for their fulfilment. The allocation of responsibility should extend to every grade of administrative unit. All these responsibilities and services should be co-ordinated and brought to a focus at specific short-term and long-term targets of production.

Now, the question is what should be done immediately to increase food production, so that we should be not only self-sufficient but should have a surplus production for the purpose of building our exports. I have to mention three suggestions in this connection. But since you have rung the bell already, and my time is up, I shall just refer to them in passing.

The first would be about the price policy. There is no price policy for this Government. I have been hearing speeches from this side as well as the other side, but so far as the cultivators' interests are concerned, nobody has represented their cases, as I have just submitted. The All India Rural Credit Survey has stated that the cost of production exceeds by 25 per cent, the value of gross produce, but nobody considers the price that has to be paid to the cultivator. Whenever the price increases, the people all of a sudden kick up a row and say that the prices have increased, and they must be brought down. But nobody considers what the cost of cultivation is and how much the cultivator has to be paid. It is very necessary, therefore, that those persons who are interested in the welfare of the cultivators should immediately be on their legs to defend their legitimate rights What happens is that people talk of stabilisation of prices, fair prices, this price and that price, but nowhere have Government come forward with a categorical statement that the cultivator of the country would be paid such and such a price which will include the cost of production as well as some resonable margin of profit

Shri Ranga: He has made the statement today

Shri D. R. Chavan: Unless Government come forward with such a categorical statement, there is no hope of getting increased production in the country

Shri Ranga: That is right

Shri D. R. Chavan: You may have irrigation projects, minor, medium and major, and you may have other projects also, but unless the cultivators of the country are given an assured price, a price which would be announced by Government much earlier, and the cultivators of the country are told, well, look here, if you produce so much so much price would be given and if nobody is prepared to purchase, then all the purchases will be made by Government and this price would be given, there is no hope of increased production

[Shri D. R. Chavan]

Only if this is done is there a possibility of getting an increase not only of 10 per cent but an increase of even 15 per cent. That is one aspect of the matter.

Mr Deputy-Speaker: If that is one aspect, and the other two are to be mentioned now, then I am afraid I shall have to ask the hon. Member to conclude now.

Shri D. R. Chavan: I shall just touch the other suggestions and finish

Concerning agricultural finance, the All India Rural Credit Survey has said that 70 per cent. of the contribution to agricultural finance comes from the money-lenders, and the rate of interest varies from 17 to 40 per cent Even with regard to the advances that are made by Government and the co-operative credit societies, what is the position? The position is that the co-perative credit societies get loan from the Reserve Bank of India at the rate of 1½ per cent. which is 2 per cent below the bank rate; and the rate of interest at which they advance the money to the cultivators varies from 7 to 12 per cent.

Shri Ranga: New money-lenders.

Shri D. R. Chavan: When Government advance loan to the Tatas, they advanced to Tatas Rs. 10 crores without any interest. I cannot understand why Government are not prepared to come forward to finance the agriculturists of the country.

Again, what happens with regard to the loans? If a small cultivator has to get a taccavi loan from Government, he has to approach through so many channels, and there is a lot of red-tapism, corruption and all that, and the loan is never given in time. That is the position. So, this aspect also has got to be taken into consideration, if food production is to be increased. Unless that is done, there is no hope. The Government may have trading in foodgrains and so many other things, but that will never be achieved.

Then, again, Sir....one point and I finish.

Mr. Deputy-Speaker: Then again, I am not helpless. I am calling Pandit Munishwar Dutt Upadhyay.

Shri D. R. Chavan: Concerning....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. His speech shall be deemed to have been concluded.

श्रीमती लक्ष्मी बाई : विकाराबाद : मैं प्रार्थना करती हूं कि बहिनों को भी बोलने का अवसर दिया जावे ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I have called Pandit Munishwar Dutt Upadhyay.

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब तक अपने मित्रों की बातें सुनता रहा । जिस विषय पर चर्चा चल रही है वह एक ऐसा विषय नहीं है जैसे कि वे विषय जिन पर हम रोज रोज चर्चा किया करते हैं । यह एक ऐसा विषय है कि जिस का इस देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । और इत्तिफाक से यह विषय कई वर्षों से ऐसा संकटमय रहता आया है कि इस पर विचार करते समय यह कह देना काफी नहीं होगा कि फलों ने यह कह दिया और फला ने यह विरोध किया, बल्कि हम सब को मिल कर यह विचार करना चाहिये कि इस संकट से कैसे बाहर हो । जब तक हम इस उद्देश्य से इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम किसी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे । मैं ने देखा कि जो हमारी पार्लियामेंट में इस विषय पर बड़ी बड़ी बहसें होती रही हैं उन का नतीजा यह होता रहा है कि बाजारों में चीजों की कीमतें बढ़ती रही हैं । हमारी अन्न की स्थिति ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन बार बार की इस चर्चा से लोग घबरा गये

और समझने लगे कि बड़ा संकट आने वाला है, खाने वाला मिलेगा या नहीं, और जिस के पास गल्ला था वह उस गल्ले को ले बैठा जिस का नतीजा यह हुआ कि कीमतें बढ़ती गयीं तो हमें इस विषय पर व्यवहारिक तरीके से विचार करना चाहिये और ऐसी युक्ति करनी चाहिये कि हम इस संकट से बाहर आ सकें ।

तो जब मैं इस उद्देश्य से इस विषय को देखता हूं तो पाता हू कि यहां ज्यादातर बातें कीमतों के बारे में हुई हैं । इस में सन्देह नहीं कि इस वक्त कीमतों का प्रश्न महत्व रखता है और आज कीमतों का हमारे जीवन पर एक संगीन हमला हो रहा है और इस-लिये हम इस को छोड़ नही सकते, और ख्वामख्वाह हमारा दिमाग आ कर इस पर अटकता है । लेकिन जब हम इस की चर्चा करते हैं तो हमें यह भी देख लेना चाहिये कि जो कुछ इन्सान कर सकता है क्या वह सब किया गया है या नही, जो करना सम्भव है वह हो रहा है या नही । अगर जो हो सकता है उस को सरकार नही कर रही है तब तो कोई दूसरा सुझाव दे सकता है जो इस से बेहतर हो, और तब उस के बारे में वह बताये कि किस तरह से उस सुझाव को अमल में लाया जा सकता है । पर यदि ऐसा नही है तो जो भी कहा जाता है वह केवल वहम की बातें हैं । यह कहने से कि मेरी बात ठीक है या उस की बात गलत है, इससे तो कुछ बनने वाला नही है ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मित्रोंने यहा बातें कही है यदि उन्होंने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लिया होता तो उन को बहुत सी बातें कहने की आवश्यकता ही न रह जाती और उन्होंने इतनी बातों पर इतना जोर न दिया होता, जिस से बहुत समय बच जाता । लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब हमारे अशोक जी ने कुछ बातें कहीं । वह तो इस विषय के बड़े जानकार हैं, और जिस विषय की आज चर्चा हो रही है उस के बारे में जो कमेटी बनी थी उस के तो वह अध्यक्ष थे और उन्हों ने अपनी बड़ी रायें दी हैं । एक आध चीज के बारे में तो मुझे लगा कि उन की राय बहुत ठीक है । उन्हों ने बताया कि अगर एक साल फूड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उस को बहुत अच्छा समझ लेना या अगर दूसरी माल प्रोडक्शन कम हुआ तो यह समझना कि बहुत खराबी हुई उचित नही होगा । उन्होंने कहा कि हमे इस मे गाइड नही होना चाहिये क्योंकि यह ऐसा विषय है जिस में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है । इस में केवल मनुष्य का ही हाथ नही है । मनुष्य थोड़ा बहुत कर सकता है लेकिन प्रकृति अनुकूल न हो तो हमारा सारा करा धरा मिट्टी में मिल जाता है । तो मै समझता हूं कि इस बारे में उन की राय ठीक है । पर उन्हो ने अपनी रिपोर्ट मे जो फिगर दिये हैं उन को अगर वह देखे तो मालूम होगा कि जो पैदावार पांच सात आठ साल पहले ५८ मिलियन टन थी वह गत वर्ष कम से कम ६८ मिलियन टन हो गयी और इस वर्ष वह ७० मिलियन टन पहुच जायेगी ऐसी आशा की जाती है । कुछ मित्रो ने यह कहा है कि जितनी हमारी पैदावार बढ़ती है उस से ज्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है । मै समझता हू कि यह ख्याल सही नही है । जो आंकड़े दिये गये है अगर वह सही है तो उन को देखने से हम को पता चलता है कि हमारी आबादी के बढ़ने का जो इंडेक्स है उस मे हमारी पैदावार का इंडेक्स ज्यादा है । मै इस चीज को आंकड़े दे कर साबित कर सकता हू लेकिन समय कम है इसलिये मै आगे बढ़ता हू । तो जो हमारी पैदावार बढ़ रही है वह आबादी के बढ़ने से ज्यादा है । लेकिन वह अकेला ही फैक्टर तो नही है कि जिस से कीमते बढ़ती हैं । न जाने कितने और फैक्टर हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं । हम बराबर यह कोशिश कर रहे है कि हमारा जीवन का स्तर ऊंचा हो और हमारी आमदनी कुछ

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

बढ़ी भी है । उस का असर क्या होगा ? जिस की आमदनी बढ़ेगी, वह बाजार में जायेगा और चीजें खरीदेगा । वह आमदनी जायेगी कहां ? तो जो जीवन का स्तर बढता है उस से भी भाव बढ़ते हैं । आप इतना बड़ा प्लान लिये बैठे है जिस पर ४८०० करोड रुपया खर्च कर रहे है । इस मे से कुछ जरूर बाहर मशीनरी आदि खरीदने के लिये जायेगा, लेकिन बाकी तो देश मे ही खर्च होगा । जिस के हाथ में पैसा आवेगा वह बाजार में जायेगा और चीजे खरीदेगा और भाव बढ़ेंगे । और भी कई फैक्टर्स है जिन को मैं गिना सकता हू जिन की वजह से भाव बढ़ते हैं । बाजार मे माल की सप्लाई का भी सवाल है । जो लोग बाजार में माल लाते थे उन की हालत सुधरने से उन की रिटेंशन पावर बढ गई है । इसलिये वे जब ठीक समझते है तब गल्ला बाजार में लाते हैं । इसलिये जो हमारा मारकेटेबिल सरप्लस था वह घट गया है ।

दूसरे कहा गया कि प्राइसेस का कट्रोल नही हो रहा है । इस का स्टेबिलाइजेशन होना चाहिये । यह अशोक मेहता जी की रिपोर्ट में भी दिया गया है । गवर्नमेंट ने भी इस को मुनासिब समझा और स्टेबिलाइजेशन करने का प्रयास किया । सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम सामने रखी । उस स्कीम के सामने आते ही सारे देश मे बावैला मच गया । जितने लोगो पर इस का असर पड सकता था उन सब ने मिल कर इस स्कीम को फेल करने की कोशिश की । उन्हों ने कोशिश की कि न गांव से गल्ला आने पावे और न दूसरी जगह से आने पावे ताकि यह साबित किया जा सके कि यह स्कीम काम नही कर सकती । उन सारे लोगो ने मिल कर जोर लगाया । नतीजा यह हुआ कि बाजार मे गल्ला कम आने लगा और भाव बढ़ने लगे । ऐसी हालत हो गई कि जैसी कभी इस से पहले हिन्दुस्तान की तवारीख मे सुनने में नही आई । जो भाव आजकल हो रहा है वह आप इस देश के इतिहास में नही पायेंगे । ऐसी हालत होते हुए भी, इतनी कमी होते हुए भी आप देखे कि स्टारवेशन से लोग नही मरे । आज हालत अकाल से भी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी आप देखें कि जो इन्सान कर सकता है वह किया गया है या नही । आखिर एडमिनिस्ट्रेशन मे आदमी ही है, जादूगर या देवता नही है । जो इन्सान कर सकता है वह किया जा रहा है । जो मसाला हमारे पास है वह देश के हर कोने मे पहुचाया जा रहा है ताकि कोई शख्स भूख से न मरने पावे । यह खूबी तो हम ने देखी । मैं नही समझता कि इस मे कोई बडी शिकायत हो सकती है । कोई इधर उधर मे नाम पेश कर दे, वर्ना आम तौर पर यह नौबत आने नही पाई है । इन्सान जो कुछ कर सकता है ह्यमैन बीइंग के हाथ मे जो है, वह तो हुआ जहा तक पैदावार बढ़ाने का प्रयास है, उस में सब जुटे हुए है । जब अशोक जी ने डायार्की की बात कही, तो मुझे ताज्जुब हुआ—इसलिये कि जब मैं उन की रिपोर्ट पढ रहा था, तो पढ़ते-पढ़ते उन की रिपोर्ट मे ही मुझ यह आइडिया स्ट्राइक होने लगा कि यह कहते तो है, लेकिन इस का नतीजा क्या गुजरेगा । अभी उन्हो ने कहा कि यह डायार्की नही चलेगी । मैं चाहता हू कि वह ध्यान दे कि यह उन्ही को दिया हुआ आइडिया है । इस मे क्या चीज बदल गई है ? उन्हो ने किसी जमाने की पोलीटिकल डायार्की की मिसाल दी । मैं कहना चाहता हू कि उन मिसालो से काम नही चल सकता है । यह बात इतनी साफ है । गवर्नमेंट ने जो रास्ता एडाप्ट किया है, वह उन्ही का सुझाया हुआ है । मैं दो तीन लाइनें पढ कर सुनाना चाहता हूं, जिस से जाहिर होगा कि वह उन के बयान से—इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से बहुत हल्की

चीज है । स्टेट ट्रेडिंग की योजना मे कहा गया है :—

"The question whether the Government should undertake as an experimental measure the purchase of the entire marketable surplus of particular foodgrains in certain selected areas will be examined in consultation with the State Governments concerned."

यही है जो उन्हों ने इस पैरा में डेवेलप किया । मैं उन की रिपोर्ट से दो चार लाईन पढ कर सुनाना चाहता हूं । उन्हो ने ही इस को एडवोकेट किया था । उन्हो ने पृष्ठ ८६ पर फरमाया है—

"In the initial stages, this organisation may face stiff competition from traders."

यानी इस का आभास उन को था या उन के विचार मे सब बातें थी । फिर उन्हो ने कहा है—

"But since it will be a government-sponsored organisation with large capital and a net-work of agencies, it should be able soon to acquire for itself a position to strengthen and dominate the market."

यह पैरा जरा लम्बा सा है, लेकिन फिर भी मैं इस को पढ देना चाहता हू । इस मे एक मिनट लगेगा । इस में कहा गया है —

"Government, in our view, should also take special measures to build up a position of strength for this organisation in the early stages by way of credit and transport facilities. We should, of course, proceed gradually and not take any action which may unduly upset the market in the near future, but we feel that step by step conditions should be created so that in the course of the next three or four years, the Foodgrains Stabilisation Organisation may be in a position to control a substantial proportion of the wholesale trade in this country .. Our policy should, therefore, be of a progressive and planned socialisation of the wholesale trade in foodgrains."

उन्हो ने यह फरमाया था, लेकिन मैं जानता हू कि उस डायार्की पर उन को क्या एतराज है । मैं यह निवेदन करूंगा कि

Shri Asoka Mehta: If the hon. Member will yield for a minute, I will explain.

The difference is this—I am very anxious to hear his criticism, but it seems I have not made myself clear to him—that in the scheme that the Government have suggested, the same traders will be buying for the Government as well as for himself The trader is not going to be even the agent of the Government. He will be buying, and Government will take over a portion of it; the trader can dispose of the rest of it, of course, at controlled prices. Here what was suggested was that there should be a separate organisation of the Government which would be handling the thing In both the schemes, as far as the total trade is concerned, a portion of it would be handled by the Government and a portion by the trade. But here the same trader will be performing a dual function, the function of being representative of the Government and the function of acting on himself. That is the distinction on which he may say whatever he likes to say.

Pandit Munishwar Dutt Upadhyay: He is of course the agent of the Government. He shall be acting in that manner. But what difference does it make at all?

Shri Asoka Mehta: I leave it to him to say whether it makes a difference or not.

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय चूंकि मेरे पास समय लिमिटिड है, इसलिये इस में न पड कर मैं निवेदन करूंगा कि जहा तक स्टेट ट्रेडिंग का ताल्लुक है, प्राइसिज को स्टैबिलाइज करने का एक तरीका निकाला,

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

जिस का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं । वह सम्भव नहीं हो सकता था जब तक कि होलसेल ट्रेड होलसेल डीलर्ज के हाथ में रहता । यह सब लोगों को स्पष्ट हो गया और हम ने यह समझा कि ये लोग प्राइसिज और मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और किसी तरह काबू में नहीं आ रहे हैं, जो कुछ अन्न हमारे देश में है, वह भी बाजार में नहीं आने पाता है और लोगों को नहीं मिलता है । इस का एक ही तरीका दिखाई पड़ा कि हम स्टेट ट्रेडिंग जारी करें, जिस में होलसेल ट्रेड को ले लें । इसलिये होलसेल ट्रेड लिया गया । उस पर अन्तिम विचार होने को है । मेरा ख्याल है कि संभवतः अशोक जी को भी इस बारे में परामर्श किया जायेगा, जैसा-कि मुझे अभी जैन साहब से मालूम हुआ है । मैं आशा करता हूं कि फ़ाइनलाइज करने में उस में ऐसी कोई शक्ल नहीं रह जायेगी, जो कि काबिले-एतराज हो ।

हमारे सामने मुख्य बात यह है कि हमारा संकट कैसे मिटे । वह मिट नहीं सकता है, जब तक कि हम इम्पोर्ट के जरिये से जिन्दा रहें । करोड़ों रुपया हमारा जा रहा है, जिस से न तो हमारी विकास की योजनायें चलने वाली हैं और न देश आगे जाने वाला है । हम एक खेतिहर देश हैं । अगर हम अपने खाने को भी पैदा नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे ? कुछ और पैदा करने की शक्ति और साधन हमारे पास क्या है ? दरअस्ल हम को इतना पैदा करना चाहिये कि हम अपने खाने का सामान भी पैदा कर सकें और उस के अलावा इंडस्ट्रीज को भी कच्चा माल दे सकें और उस के साथ ही फ़ारेन एक्सचेंज भी उस के जरिये पैदा कर सकें—इसलिये कि कोई और जरिया नहीं है, जिस से हम फ़ारेन एक्सचेंज पा सकें—हम फ़ारेन एक्सचेंज कैसे पायेंगे, जब तक कि दूसरे देशों को देने के लिये हमारे पास सामान न हो । इतना पैदा करना चाहिये, लेकिन हमारी हालत यह है कि उस पैदावार की तरफ़ ध्यान न दे कर हम बहस कर रहे हैं कि यह है, यह है, उन्हों ने यह कह दिया और इन्हों ने यह कह दिया, वगैरह । वास्तव में हम को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्कीम पर ध्यान देना चाहिये और अगर कोई उस पर ध्यान दे, तो आंख खुल जाती है । मेरे मित्र यह कहेंगे कि उन्हों ने एपरेजल और री-एपरेजल की रिपोर्ट्स देखी । उस में कमियां भी हैं । बहुत सी चीजें नहीं हो सकीं । आप ने कहा कि सैकंड प्लान में टारगेट को बढ़ाइये और टारगेट को ड्योढ़ा कर दिया—दस मिलियन से १५.५ टन कर दिया और जब रिसोर्सेज बढ़ाने का सवाल आया, तो एक टका भी नहीं बढ़ा । मतलब यह कि रिसोर्सिज ज्यों के त्यों हों और पैदावार ड्योढ़ी कर दी जाये । इस में मिनिस्ट्री आफ़ एग्रीकल्चर क्या कर सकती है, जब आप रिसोर्सिज देने वाले नहीं हैं और आप कहें कि पैदावार बढ़ा दीजिये । इस तरह पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है ? जब स्टेट्स ने डिमांड की, तब भी नहीं हो सका । और प्लानिंग कमीशन कहां से लाता ? उस के रिसोर्सिज जो हैं, वे सब जानते हैं—इस मुल्क से कर्ज ले रहे हैं, उस मुल्क से उधार ले रहे हैं । जब तक हम एग्रीकल्चरल पैदावार को बढ़ायें नहीं, १५.५ मिलियन टन तक बढ़ायें नहीं, तब तक हमारी हालत सम्हलने वाली नहीं है । हमारी डिमाण्ड्ज बढ़ती जा रही है । इस सब को देख कर उन्हों ने यह तय किया कि हम ने बढ़ाना है ही, लेकिन रिसोर्सिज नहीं दे सकते । उस का नतीजा यह है कि सारी स्कीम्ज में कमियां हैं । इस देश को फ़र्टीलाइजर्ज की जरूरत है, लेकिन उस के लिये फ़ारेन एक्सचेंज नहीं है । उस की मांग कई गुना बढ़ गई है । इस मिनिस्ट्री का या इस गवर्नमेंट का या ह्यूमेन बीइंग का काम यही हो सकता था कि फ़र्टीलाइजर्ज को पापुलराइज किया जाये, कल्टीवेटर्ज के पास पहुंचाया जाये । वास्तव में एग्रीकल्चर का सारा सैक्टर प्राइवेट सैक्टर है । उस में पब्लिक सैक्टर क्या है ? सब पैदा करने वाले

गांवों में किसान बसे हुए हैं। वे किस संगठन में हैं, कहां हैं, क्या सोचते हैं, यह अलग बात है। मैं तो कहूंगा कि यह तो प्राइवेट सैक्टर भी नहीं है—यह तो प्राकृतिक सैक्टर है। किसान बेचारा क्या करे? उस को तो बीस परसेंट पर कनाल करना है और अस्सी परसेंट उस के काबू में नहीं है। उस के पास पानी नहीं पहुंचता है, कोई सामान नहीं पहुंचता है। वह क्या करे? अगर हम पैदावार बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जिस के भरोसे हम को संकट के बाहर होना है, तो हम पहुंच जाते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज पर। हम किसानों पर यह छोड़ देते हैं कि वे नालिया और चैनल बनाये। किसानों के पास इतने साधन कहां हैं? इसलिये वे नहीं बना सकते हैं। गवर्नमेंट के पास भी साधन कहां हैं? मैं ने सुना है कि अब गवर्नमेंट ने २६ करोड़ रुपया दिया है, जिस की वजह से उस का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। माइनर इरिगेशन में थोड़ी बहुत गुंजायश है। उस के प्रयास पर सब जुटे हुए हैं। जहां तक बीज उपलब्ध करने का सवाल है, उस में सीड रेप्लीकेशन की दिक्कत थी। उस के दूर होने पर कुछ प्रगति हुई है। इस के बाद इन्सैक्टीसाइड्स, खरीफ कैम्पेयन, रबी कैम्पेयन को देखिये। मैं बड़ा क्रिटिकल था। मैं कभी उस पर बोला था, तो मैं ने बहुत साफ त्रुटियां बताया था। लेकिन उस के बाद मैं ने देखा कि जितना प्रयास सम्भव है, जितना प्रयास कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है जितना गवर्नमेंट प्रयास हो सकता है, वह सारा प्रयास जुट कर के किया जा रहा है। जब मैं स्टेट्स में गया और अफसरों को जुट कर के काम करते हुए देखा तो यह चीज देख कर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक कम्पीटीशन सा, एक होड़ ही उन में लगी दिखाई देती थी। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कि कुदरती हैं, स्वाभाविक है, नैचरल है और उन को हमें हमेशा अपने सामने रखना होगा। उन लिमिटेशंस के होते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह हमें देखना होगा।

अन्त में मैं कुछ सुझाव दे कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने का जो दूसरा एक रास्ता हो सकता है वह बंडल क्रापिंग का है और उस पर मैं जोर देना चाहता हूं। हमारे पास जो एरिया है, वह लिमिटेड है, इस वास्ते हमें डबल क्रापिंग पर जोर देना चाहिये। अगर हम कोई ४० परसेंट बोई हुई जमीन में डबल क्रापिंग कर सकें, ज्यादा जमीन में नहीं तो बहुत कुछ पैदावार बढ़ सकती है। इस के सिवाय मुझे और कोई तरीका जान नहीं पड़ता है जिस से कि पैदावार बढ़ सके।

दूसरा सजैशन मैं यह देना चाहता हूं कि जो अनइकौनोमिक होल्डिंग्स हैं इस पर हमारी जो कोआप्रेटिव की योजना है, इस को हम चलायें। मैं ने अपने कुछ भाइयों को कहते हुए सुना है कि यह कैसे होगा और कब होगा। मैं इस के बारे में अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि यह होगा जरूर। जिन मेरे मित्रों को कोई शुभा है, मैं चाहता हूं कि वे उस शुभे को अपने दिमाग में से निकाल दें। लेकिन अगर वे ऐसा ही करते रहे कि हमें कुछ राय देते रहें और दूसरों को कुछ और ही तो कठिनाई अवश्य सामने आयेगी। इस वास्ते अनइकौनोमिक होल्डिंग्ज कोआप्रेशन के तहत होने चाहियें। इस से हमारी जो पैदावार है वह बढ़ सकती है।

तीसरी तजवीज मैं यह देना चाहता हूं कि माइनर इरिगेशन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। यही एक रास्ता है जिसमें विदेशी मुद्रा और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा नहीं लगेंगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। लोकल मैन्योर और कम्पोस्ट, ग्रीन मैन्योर पर हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिये। फर्टिलाइजर्स की जो डिमांड है, उसको आप

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

पूरा नहीं कर सकते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। मैं मानता हूं कि उस डिमांड को मीट करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, फारेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है और आप फारेन एक्सचेंज इस वक्त दे नहीं सकते है। मैं यह नहीं कहता कि आपकी देने की मंशा नहीं है या इच्छा नहीं है लेकिन आप मजबूर है। आपने इसकी डिमाड को प्रापेगंडा करके बहुत बढ़ा दिया है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि लोकल मैन्योर पर, ग्रीन मैन्योर पर हम ज्यादा ध्यान दें।

अब मैं सीड के बारे में कुछ कहना चाहता हू। सीड इत्यादि को निरोग करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए भी आपको प्रापेगंडा करना चाहिये। गर्मी में ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो पैदावार को बढ़ाया जा सकता है।

क्रैडिट के बारे में मैं यह कहना चाहता हू कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और स्टेट्स में बहुत कठिनाई होती है। सिक्योरिटी आवश्यक होती है। मैं मानता हूं कि बिना सिक्योरिटी के रुपया डूब भी जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हू कि कोई न कोई तरीक़ा निकाला जाना चाहिये जिसमे क्रैडिट ठीक वक्त पर मिल सके। जब ऐसा होगा तभी हमारी जो पैदावार है, उसको बढ़ाया जा सकता है और जो संकट है, उसमें से निकला जा सकता है। इसी तरह से वेस्टेज की बात है। पैस्ट्स और वाइल्ड एनिमल्स वगैरह की वजह से जो साढ़े बारह परसेंट हानि का रूल बना हुआ है कि इतना वेस्टेज में काट दिया जाए, इसको बचाया जाना चाहिये और देखा जाना चाहिये कि वेस्टेज न हो और इसको बचाने के उपाय किये जाने चाहियें।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर डबल क्रापिंग किया गया क्रैडिट वगैरह सब साधन ठीक समय पर मुहैया करने का प्रबन्ध किया गया तो जो संकट है, उससे निकलने की आशा की जा सकती है वर्ना ये जो जबानी नुक्ता चीनी है, ये हमारी कोई मदद करने वाले नहीं है।

Shri Thirumala Rao (Kakinada): Mr. Deputy-Speaker, looking at the demands for food and agriculture, we find that it comes to a total of Rs. 274·69 crores. The ramifications of this department are cotterminous with the whole country and the activities seem to be appalling and it takes all your energy and ingenuity to understand them. An expenditure of Rs. 186 crores is set apart for the import of foodgrains while Rs. 88 crores is to be spent by way of expenditure which could not be counted in terms of rupees, annas and pies by way of return to the department. That is, as it should be. It is expected that all this money will be spent in developmental schemes, in investigations and in scientific researches. This department has also got a primary department in every State of its own and I think those departments should have a fairly large budget allocation from the State revenues. I do not want to go into the details of all these things. In the brief time at my disposal I want to refer only to two or three points.

In 1958, we have imported Rs. 120 crores worth of foodgrains. We have made provision in 1959-60 for Rs. 186 crores

Shri A. P. Jain: That includes internal procurement also.

Shri Thirumala Rao: Internal procurement does not come to more than 10—12 lakh tons and judging by the past experience I think you must have made a provision of about Rs. 30 crores for internal procurement.

Shri A. P. Jain: We have already purchased foodgrains worth Rs. 40 crores.

Shri Thirumala Rao: We are told that this year we are going to have a good crop

Shri M V Krishnappa: We have had a good crop.

Shri Thirumala Rao: We expect a production of about 70 million tons of foodgrains in 1959-60 or in 1958-59 Your calculations are not quite clear whether these figures relate to the period January to December or from the middle of August to the next August. But one thing is certain We have estimated an extra production of 10·5 million tons Perhaps the Planning Commission puts it at 15·5 million tons which is to be achieved by the end of the Second Plan period Our food production is not keeping pace with the growth of population When we find an all-round increase in production, we do not find a corresponding progress or increase in foodgrains production From the statistics supplied by the department, one could see the figures about the extra food production in States and we find a sorry tale in many States in respect of their efforts. The rice production in Bihar was 38·52 lakhs tons in 1953-54 and it is 37·00 lakhs tons in 1956-57. It was particularly a bad year last year when it was only 27·81 lakhs of tons. In the case of wheat also from 3·90 lakhs of tons in 1953-54 it has come down to 1·82 lakh tons in 1956-57 and last year it was 2·43 lakh tons. In the case of Bombay also, the rice production has come down from 14·11 lakh tons in 1954-55 to 13·78 lakh tons in 1957-58. Of course Kerala has always been a deficit State and it has not improved much in its production Its production was eight lakhs and odd tons in 1956-57 and in 1957-58 it is eight lakh tons. Madras has shown a little improvement in its figures and Mysore also has improved in its cereals, and rice also. Punjab has shown a little improvement in its rice as well as wheat. Coming to Uttar Pradesh, that is a problem State again as Bihar ...

An Hon. Member: What about Orissa?

Shri Thirumala Rao: I will come to that In 1953-54 the total rice production was 25·96 lakh tons and it went up to 26 32 lakh tons in 1956-57 but it has come down to 21 lakh tons in 1957-58. In U.P. the wheat production in 1953-54 was 31·06 lakh tons and rice production was 22·55 lakh tons In 1957-58, it has slightly gone up in its production but has fallen in its wheat production by about four lakh tons. The total production of U P. in 1953-54 was 12,381,000 tons and in 1957-58 it was 11,136,000 tons It is showing a downward trend Similar is the case in West Bengal Rice production there in 1953-54 was 55,56,000 tons In 1956-57 it was 45,03,000 tons Last year it was 41,85,000 tons When we see the figures we find that except in Madras and Andhra, Punjab and Madhya Pradesh, many of the States have been showing a downward trend in their total production during the last five years. That is a matter which has to be given some serious attention

There is no point in the Central Government assuming responsibility for the whole country, whatever the attitude and whatever the behaviour of the States might be. There should be an amount of decentralisation in responsibility and powers, which is claimed for in every other matter, with regard to food also, and the States should be saddled with this duty of trying to become self-sufficient in foodgrains. It is not only a drain on our foreign exchange resources, the foreign import is so great that it is a constant source of worry to the Central Government to see that they make both ends meet with regard to the food situation.

[Shri Thirumala Rao]

I now come to the question of State trading about which there seems to be some controversy. If you read the report of the Mehta Committee, it is clearly envisaged there that the state of affairs has already arisen in the country when Government must enter into this trade with some effectiveness and foresight. When the Committee with regard to procurement and distribution was set up in 1950, the situation was one of the worst in the whole of India with regard to food production and distribution. Even then it was sought that a half-hearted measure will not suffice to deal with the situation.

When this Mehta Committee has toured the whole country in 1957 and seen things for itself, how the intermedaries, the large-scale businessmen, the mill-owners and the millers are playing with the fortunes of the people and the food situation in the country there should be no half hoartied measure about these things

The only point is, the Government should have given greater attention to this, because it requires a careful handling. There are a large number of vested interests, huge cartels that are entrenched behind this rice and wheat trade in big cities like Bombay, Calcutta, Kanpur and Delhi. They will be the last persons to yield to the huge scheme which the Government want to bring into existence without giving the bitterest fight. Very eminent and influential Members of Parliament are also behind them to help them in seeing that this scheme does not come into force

What is the alternative? Have they behaved fairly by the country? As I have already said, in 1949 we imported 37 lakh tons of foodgrains. In 1951 we imported 41 lakh tons of foodgrains. Last year was one of the worst years and we had to import 36 lakh tons of foodgrains. When there is so much scarcity in the country, when prices are rising sky high, do these middle men, these big businessmen who cordon large stocks in their godowns co-operate with the Government? Do they come to the rescue of the people in maintaining prices at a reasonable level? I will give the example of Andhra itself, which is considered to have 5 lakh tons to 6 lakh tons of extra rice to be supplied to other States. Even there the prices have shot up as high as in places where rice is scarce or in short supply. This artificial scarcity, this artificial rise in prices is created by a large number of people whom we know very well. For instance, in places where the production is good, the land holder has become the hoarder, as well as the miller. In a family owning 50 to 60 acres of land, one brother is an agriculturist and another brother is a miller. Both of them go to the bank, get credit and buy another 500 bags from a lean neighbour and then store them up. That is how they artificially make the prices go up. They do not release the stocks until the Reserve Bank comes down upon them freezing their credit. If really the big business and the medium-size businessmen, who claim to be serving the society in their own way, come to the rescue of the ordinary man, the Government need not have come into the picture at all.

What I say is, Government have been talking about this even before they have got any plan about it. That has created a difficult situation. This does not require any propaganda on the part of the leaders of Government to make the people ready for it, because with the majority of the people food is a problem. The majority of the people are 'have-nots', the ordinary lower class people who are affected by the rise in prices even by one anna.

We say that the production in 1956-57 was 68 million tons. In 1957-58 it came down to 62 million tons. We expect this to go up to 70 million tons. If we organise State trading effectively even in a rather half-hearted

way, which is sought to be promulgated through the statement given by the Minister yesterday, we will be able to buy up about 10 per cent of the market arrivals. Let us hope that about 40 per cent, or nearly, out of 70 million tons, 20 to 25 million tons will come into the market If we are able to buy in the next season 8 to 9 million tons of foodgrains through the agents or through the millers that will be a sufficient buffer stock for lean years to come I do not know how far we will be able to do this. We require at least Rs 300 crores to Rs 400 crores capital We do not have any blueprint of the scheme that the Government are contemplating, but from the bare statement given by the hon Minister yesterday we understand that they have to largely depend on these millers both for finance and operations It requires a lot of energy and organisation to control these millers We have got the experience of these millers There is a system working in Madhya Pradesh for a long time whereby the millers will have to surrender a certain proportion of their market purchases to Government. That also has been tried in certain other places like Madras The rest of the foodgrains, after surrendering the quota to Government, is allowed to be sold in the free market

I think that is a danger which should be effectively controlled by the Government. If you take even 50 per cent of the millers' procurement at controlled rates and leave 50 per cent to the millers, your purpose may be very successfully defeated. They will withhold their stocks till such time as the Government stocks are exhausted. Then they will release their stocks and demand their own prices There must be effective control, there must be a device to control prices from the beginning to end. How the Government will be able to achieve that purpose is a difficult matter for me to guess unless we understand all the details of the schemes.

With regard to co-operatives, they depend largely on the co-operative machinery to help Government with regard to procurement and distribution of foodgrains The co-operative machinery, we know, is working in all the States, and, probably, Andhra, Madras, Punjab and Bombay are the States where the co-operative movement is working with some efficiency compared to the rest of India It requires a large manpower For instance, in Andhra there are about 20,000 to 25,000 societies, each having at least a President and a Secretary Besides, there are the *panchayatdhars* That means there are about 50,000 people trained to keep accounts, to run societies, to bring loans and disburse them You require at least half-trained personnel to run these co-operative institutions before they can be expected to handle all these things It is a large order that we are giving to ourselves It requires to be carefully looked into before this trade is entrusted to co-operative movement But I would suggest that if you entrust it to certain State Governments and ask them to experiment on these lines, ask them to organise distribution of foodgrains in an effective way, I think they will work as models and they will be able to give sufficient experience to the rest of the country in both buying and storing and also distributing foodgrains on a large scale

Coming to land reforms, I want to say a few words about it The question has been agitating the minds of the people very much Co-operative farming is another thing that is creating a sort of scare among certain people, but before we come to co-operative farming I think the Government of India have decided to think first of organising co-operative service to the agriculturists This co-operative service is seen in so many places The pattern of society is changing fast and with the increase of population, the problem of unemployment is also assuming greater proportions Many educated young men are leaving the villages and are

[Shri Thirumala Rao]

going far and wide into the country to seek employment, leaving their people behind. So, there is not much of efficient man-power even for agricultural operations in the villages, and we cannot depend for long on the age-old system of agricultural production. If you want to minimise overhead charges and utilise all the facilities offered by Government by way of irrigation, fertilisers, seeds, tractors and such other conveniences, co-operative servicing is the only method by which you can circumvent the handicaps that are prevailing in the villages. By three years' time, if people gather the advantages of organising service co-operatives and reap the benefit of these co-operatives, then by themselves they will organise co-operative farming for greater production and realise the fruits of mutual help, mutual assistance and co-operation. That is the basic principle of co-operative service.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ने पिछले ५०-६० सालों में कभी भी ऐसा वक्त नहीं देखा जैसा कि इस साल देखने को नसीब हुआ है। गेहूं और चने की कीमत पिछले ५०-६० सालों में कभी इस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से अब बढ़ी है। नतीजा यह हुआ कि लाखों आदमी बेचारे भूख के मारे तड़पते रहे। कुनबों को खाना नहीं मिला। यह शायद ठीक हो कि स्टारवेशन डैथ्स नहीं हुई लेकिन जितना डिस्ट्रेस हुआ है उसका अन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कितने ही गावों और शहरों में लोगों के अन्दर इतना डिसैटिसफैक्शन और अनरेस्ट पैदा हुआ कि जिसका ठिकाना नहीं। इत्तिफाक से इन्हीं दिनों में हिसार की एक छोटी सी जगह में एक म्युनिसिपलटी के अन्दर चुनाव हुआ था। जिस वक्त चुनाव हो रहा था उसी वक्त बराबर की केयर प्राइस शाप पर खरीदारों का क्यू लगा हुआ था। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ थे वह वोटरों से यह कहते थे कि देखो इस कांग्रेस हुकूमत की करतूत। तुम किसको वोट देते हो। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में हार गये। यह छोटी सी बात है। लेकिन मैं बहुत अदब से अर्ज करता हूं कि हमें इस पर बहुत गौर से सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि देश के अन्दर अनाज की ऐसी कमी भी न हो और फिर भी ऐसी आफत आ जाये कि मामूली आदमी को अपने रोजमर्रा के गुजारे के वास्ते गल्ला न मिले। इससे ज्यादा मैं कोई इनएफीशेंसी गवर्नमेंट की नहीं देख सकता। इस इनएफीशेंसी के बहुत सारे वजहात हैं। वे वजूहात ऐसे हैं कि अगर हम उनकी तरफ तवज्जह नहीं देंगे तो चाहे देश में कितनी भी पैदावार बढ़ा लें, लेकिन देश के अन्दर आराम और तमल्ली नहीं हो सकेगी।

मैं ने यह पिछली बार अर्ज किया था और आज मैं इसको फिर दुहराना चाहता हूं कि जब तक हम अपने इस कांस्टीट्यूशन को तबदील नहीं करेंगे तब तक यह गैरमुमकिन है कि हम कभी भी अपने फूड प्राबलम को साल्व कर सकें। आज श्री अजित प्रसाद जैन के सिर पर इस हालत के बारे में सारे इल्जामात थोपे जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी वजह से ही सारी तकलीफ हुई। लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या फिलहाल के उनको ऐसे हुकूक हासिल हैं कि वह अहकाम जारी करके स्टेट गवर्नमेंट्स को फूड प्रोडक्शन के बारे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह सही है कि स्टेट्स के अन्दर फूड प्राबलम की अरजेंसी को उतना महसूस नहीं किया जाता जैसा कि इस हाल के अन्दर हम लोग महसूस कर रहे हैं। अगर स्टेट्स में जिलों के अफसर और दूसरे लोग इस की अरजेंसी को इसी तरह महसूस करें तो हमारा फूड प्राबलम जल्द हल हो सकता है। आप देखें कि आज हालत यह है कि फूड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी तो स्टेटस पर है और फूड के डिस्ट्रीब्यूशन की

जिम्मेदारी मिनिस्टर साहब के ऊपर है, या नहीं। यह मुझे नहीं मालूम। कांस्टी-ट्यूशन का आर्टिकल ३७६ का असर खत्म हो गया और अब लैंड और फूड स्टेट सबजेक्ट हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि केरल और दूसरी स्टेट्स शिकायत करती हैं कि मिनिस्टर साहब हमको फूड खरीदने की इजाजत नहीं देते, हमको जितना चाहिए उतना फूड सप्लाई नहीं करते। तो हम देखते हैं कि फूड के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी मिनिस्टर साहब के ऊपर है। और पैदावार बढ़ाने का काम स्टेट्स का है—इसका नतीजा यह है कि स्टेट्स के फूड मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पंजाब में इतना गेहूं होते हुए भी लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा लेकिन वहां के फूड मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक इस सारी जिम्मेदारी को आप एक जगह नहीं रखेंगे तब तक काम ठीक नहीं हो सकेगा। या तो मेटर प्रोडक्शन की भी जिम्मेदारी ले लें या डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी स्टेट्स को दे दें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता यह प्राबलम नहीं होगा।

मैं ने पिछली दफा तजवीज की थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस फूड के मसले को अपने हाथ में लें। उसका मतलब यह नहीं था कि मैं श्री अजित प्रसाद पर कोई नो कानफिडेंस ला रहा था। मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं ने वह तजवीज इसलिए की थी कि मैं जानता हूं कि जिस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर साहब और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेते तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता। मैं ने यह तजवीज कोई मजाक के तौर पर नहीं की थी। मेरा ख्याल है कि जब तक ऐसा नहीं होगा यह मसला हल नहीं होगा। आनरेबिल मिनिस्टर साहब स्टेट मिनिस्टर्स पर वह जोर नहीं डाल सकते जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब डाल सकते हैं। मैं जानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एग्रीकल्चर में और फूड में कोई खास तजुर्बा नहीं रखते लेकिन मैं ने इसलिए यह कहा था कि वह चार्ज लें क्योंकि अगर वह इस तरफ तवज्जह देंगे तो हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी ब्रेन वेव आवे कि जिससे यह मसला हो जाय। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक आप कांस्टीट्यूशन को तबदील नहीं करते तब तक यह मसला हल होना गैर मुमकिन है।

as divided responsibility is the bane of administrative efficiency.

15.27 hrs.

[SHRI BARMAN in the Chair]

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं लैंड रिफार्म के बारे में। जब से हमारी गवर्नमेंट पावर में आयी है इसने लैंड के बारे में इतनी बातें कही हैं कि जिनसे लोगों में बड़ी अनसरटेंटी बढ़ गयी है। कोई आदमी आज यह सरटेन फील नहीं करता कि अगर वह आज किसी को अपनी जमीन बोने को दे देगा तो वह उसके पास वापस आयेगी या नहीं। जब से यह कहा गया है कि गवर्नमेंट लैंडलैस लेबरर को जमीन देगी तब से बड़ी अनसरटेंटी फैली हुई है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट कहां से जमीन दे देगी। गवर्नमेंट के पास इतनी जमीन है कहां। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कितनी ही ऐसी बातें हुई हैं कि जिनकी वजह से लैंड के बारे में सख्त अनसरटेंटी पैदा हो गयी है। मैं वकील हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि आज पंजाब में लैंड के मुताल्लिक क्या कानून है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां का कोई मिनिस्टर भी नहीं जानता कि आज लैंड के मुताल्लिक सही ला क्या है। अगर कोई लैंड ओनर आज मेरे पास आकर पूछता है कि वह किस जगह पर है तो मैं उसको ठीक नहीं बतला सकता। तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी लैंड रिफार्म

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आप करना चाहते हैं उनको क्विकली और प्राम्पटली और सरटेंटी के साथ कर दीजिये। जब तक यह हालत रहेगी तब तक कोई आदमी अपने को अपनी जगह पर सीक्योर नहीं समझ सकता। किसी को यह भरोसा नहीं है कि उसकी जमीन उसके पास रहेगी या नहीं। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे एक दो और जरूरी बातें कहनी हैं।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप कोआपरेशन को खूब जोर से चलावें। लेकिन इस तरह से चलावें कि जिससे देश के अन्दर खराबी न पैदा हो। अगर आप देश के अन्दर बड़े बड़े फार्म बनाना चाहते हैं तो बनावें लेकिन एक चीज को न भूलें। वैस्टर्न यूरोप को और हमारे देश का यह तजर्बा है कि जो छोटे छोटे इकानमिक होल्डिंग्स के प्रोप्राइटर होते हैं वह अपनी जमीन के ऊपर जितनी मेहनत से काम करते हैं उतनी मेहनत से कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर उसके पास १५ या २० एकड़ जमीन है तो वह और उसका सारा परिवार सुबह ६ बजे से शाम तक और रात के १२ बजे तक उस पर पूरी मेहनत से काम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। जैसा कि मिल साहब ने लिखा है, उस जमीन में से सोना निकलता है, जहां पेटि कल्चर या पेजन्ट प्रोप्राइटर से खेती हो। सारी दुनिया और यूरोप का तजर्बा यह बताता है कि छोटा मालिक, जिस के पास इकानोमिक होल्डिंग हो, जितनी मेहनत वह और उसका परिवार करता है, उतनी मेहनत हायर्ड लेबर से हरगिज मुमकिन नहीं है। इस को आप न भूलिए।

इसी तरह मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि आप यहां पर सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं। बाशौक मुकर्रर कीजिए। मुझे उस में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वह सीलिंग लुडिकरस नहीं होनी चाहिए। सीलिंग इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि गांव का बड़े से बड़ा आदमी आप के अर्दली के बराबर हो जाये। आज आप अर्दली या खलासी को ६०, ७५ रुपए माहवार देते हैं। इतनी सीलिंग और इतनी आमदनी मुकर्रर न कर दें कि गांव के लोग हयुअर्ज आफ़ वुड एण्ड ड्राअर्ज आफ वाटर बन कर रह जावें। आप ३० एकड़ की सीलिंग बनाते हैं, जिस की आमदनी ३६०० रुपए होगी। पता नहीं कितनी होगी, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट सारी जमीन को पानी देने की गारण्टी नहीं करता है। लेकिन मान लीजिए कि इतनी आमदनी हो, तो कुनबे के पांच आदमियों में से हर एक के हिस्से में क्या आयगा? आज भी सारे पंजाब में मजदूर को ढाई रुपए मिलते हैं। आप जो कुछ करने जा रहे हैं, उस का नतीजा यह होगा कि आप गांव वालों को अर्दली और नौकर के दर्जे तक पहुंचा देंगे और उस से ज्यादा हैसियत उन को नहीं देंगे। किस तरह से अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेंगे? किस तरह वे बीमारों का इलाज करा सकेंगे? किस तरह वे पक्के मकान बना सकेंगे? किस तरह व इलैक्शन लड़ सकेंगे? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इतनी छोटी सीलिंग बनाई जायगी, तो यह एक्सप्रापिएशन होगा—हमारे कान्स्टीच्यूशन के खिलाफ होगा और यह आप को दुख देगा। यह आराम की चीज नहीं है। जब हमारी पार्लियामेंट की रिफार्म्ज कमेटी बनी, जिस में सौ मेम्बर थे, तो उस में बड़ी बहस हुई। आखिर हम एक नतीजे पर पहुंचे। उस वक्त मैं ने कहा था कि सौ एकड़ से कम सीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि पचास एकड़ की इकोनोमिक होल्डिंग २८०० रुपये सालाना या २५० माहवार की आमदनी होनी चाहिये। यह ज्यादा नहीं है। मुश्किल से एक या डेढ़ परसेंट लोग ऐसे होंगे, जिन की यह २०,००० सालाना की आमदनी हो सकती है। दस एकड़ तो चारे और घास के लिये

दीजिए और ६० एकड़ और दीजिए और इस तरह कुल १०० एकड़ की सीलिंग होनी चाहिए, जैसा कि पजाब ने शुरू में कहा था। अगर आप ऐसा न करेंगे, तो मेरी नाकिस राय में आप न पोलीटिकली, न इकानोमिकली और न किसी और तरह से सही काम कर सकेंगे। यह सीलिंग व्यक्तिगत होनी चाहिये वरना बाप बेटो, मिया बीवी व बच्चो में झगडे का पूरा अन्देशा है।

जहा तक को-आपरेटिव फार्म्ज का ताल्लुक है, आप बडे-बडे फार्म बनायें, लेकिन उसमें सबसे बडी जरूरत यह है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में अपनी पालिसी एनाउन्स करे कि बडे फार्म्ज को क्रेडिट, ट्रैक्टर, बीज वगैरह की यह-यह रियायतें दी जायेंगी। इसके अलावा बडे को-आपरेटिव फार्म्ज में छोटे इकानोमिक होल्डर्ज को और जिनकी सीलिंग बनायें, उनको शामिल करने में आप दरेग न करें, क्योकि अगर बडे फार्म्ज के लिए ब्यूरोक्रटिक तरीके से इन्तजाम करेंगे—एक मैनेजर, एक कैशियर और एक सुपरिन्टेंडेंट वगैरह रखेंगे, तो वही सारी आमदनी खा जायेंगे और छोटे जमीदार को कुछ भी नही मिलेगा और करप्शन इतनी बढ़ेगी कि आप इन्तजाम नही कर सकेंगे। खुद गाव वालो को इन्तजाम देने से आप इन मुसीबतो से बरी हो जायेंगे। जिस शख्स का सो पचास एकड का खेत होगा, वह जिम्मेदारी लेगा कि दुसरो के लिए ज्यादा खेती की जाये। इस सिलसिले में ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि बडे रिसोर्सिज का भी फायदा उठाया जाये और जिन आदमियो के बडे खेत है, अगर वे चाहे, तो वे अपनी अलहिदा एग्जिसटेंस कायम कर सकें और साथ ही उसका हिस्सा बना कर काम कर सकें और पेटिट कल्चर के असूल का भी फ़ायदा उठा सकें। मैं अर्ज करना चाहता हू कि हमारे जमींदार बड़े समझदार हैं। उनको कहा गया कि नई काटन बोइये, तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। जमींदार को फ़ायदा पहुचना चाहिए। उसके दिमाग में पहुंचना चाहिए कि फला काम में मेरा फायदा है और वह उस काम में शामिल हो जायेगा। अगर ऐसा किया जायगा, तो हर एक जमीदार को-आपरेटिव फार्म्ज में शामिल हो जायेगा, वर्ना आप कितनी भी कोशिश करें, वह शामिल नही होगा।

अब मैं असल मजमून की तरफ आता हू। मेरी राय मे जिस तरीके से आप पैदावार बढ़ा सकते है, वह तरीका दुनिया में आज रायज है। नाईजर्या, इटली, इजिप्ट व आस्ट्रेलिया में आपको उसके बारे में कई दफा कहा गया। आपके आई० सी० ए० आर० ने कहा कि आप इस का मान लीजिये, लेकिन आपने आज तक उस पर अमल नही किया। हिन्दुस्तान मे आज भी १०० मिलियन एकड के करीब ऐसी जमीन है, जहा या तो इरिगेटिड होने या ट्यूबवैल्ज का पानी पहुचने मे या ईश्वर की तरफ से रेन-फाल होने से दो फसलें बडी आसानी से हो सकती है। आज तक दो फसलो की ऐवरेज ४३ मिलियन एकड की है। मैं समझता हू यह एक बडी भारी गलती है। अभी मैंने अपने दोस्त डा० राम सुभग सिह की तकरीर सुनी। मुझे उन की तकरीर सुन कर यह ख्याल हुआ कि शायद यह मर्ज ऐसा है, जिसका इलाज न हो, लेकिन मैं समझता हू कि ऐसी सूरत नही है, बल्कि यह मर्ज ऐसा है, जिसका हम इलाज तो कर सकते है बशर्ते कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक काम शुरू कर दे। मेरी राय में बारह बरस के तजुर्बे से यह साबित हुआ है कि सैन्टर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फौरन बन्द कर दिया जाये।

श्री ब्रजराज सिंह मिनिस्टरो का क्या होगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब तक १४,६०,००,००० रुपया बाहर से गल्ला मगवाने पर खर्च किया गया है। पिछले पांच सालो में हमने यहा पर ५,४१,००,००० मन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दूध कम कर दिया। ये दो चीजें ही यह दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि इस महकमे का इन्तजाम देश के लिये हानिकर है। लेकिन सैण्ट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो काम बहुत अच्छा किया है, मैं उसकी तरफ भी तवज्जह दिलाना चाहता हू। जितनी रिसर्च हुई है, उसके मुताल्लिक जो कुछ काम हुआ है, वह इसी डिपार्टमेंट की तरफ़ से हुआ है। उसमें जितनी तरक्की हुई है, वह इसी की वजह से हुई है। आज भी उस में बहुत ज्यादा काम करने की पोटेंशियलिटी है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारे के सारे वह खुद अपने हाथ में ले या प्राविंसिज में चला जाये, लेकिन रिसर्च का काम सैण्टर के जिम्मे रहना चाहिए, क्योंकि फैडरल इंस्टीच्यूशन्ज में हमेशा रिसर्च का काम सैण्टर के जिम्मे होता है। मैंने आनरेबल मिनिस्टर साहब से एक सवाल इस गर्ज से पूछा था कि दरअस्ल इस देश में इस देश की इकानोमी मे एनीमल्ज की क्या बुक्कत है। मैंने यह सवाल पूछा था—

"Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) what is the approximate value of cowdung and urine available in the country annually;

(b) what quantities of nitrogen potash and phosphates could be produced from these; and

(c) what is their value?"

The hon. Minister's reply was:

"(a) On the basis of cattle census, 1956, it is estimated that about 1,200 million tons of fresh dung and about 335 million tons of fresh urine is voided annually by the livestock population in India. It is not possible to indicate the money value of these as dung is not sold in raw state.

(b) The following quantities of nitrogen potash and phosphates are estimated to be present in the dung and urine indicated at (a) above in terms of N, K_2O and P_2O_5

	N	K_2O	P_2O_5
	(figures in million tons)		
Dung	2·4	1·8	1·2
Urine	2·0	1·6	0·03"

The reply to part (c) is very important:

"(c) The efficiency of these plant nutrients is estimated at 50 per cent in dung and 100 per cent in urine as compared to chemical fertilisers. On this basis, the value of nitrogen in dung and urine would work out to about Rs. 5,600 million and of phosphate (P_2O_5) and potash (K_2O) to about Rs. 846 million and Rs. 1,482 million respectively."

मेरी गुजारिश यह है कि अभी बड़ा फिक्र जाहिर किया गया कि चार मिलियन के नाइट्रोजन के बगैर इस देश में अनाज की पैदावार पूरी नही बढ सकती। मैं अर्ज करना चाहता हू कि हमारे पास फिगर्ज हैं कि आठ हजार मिलियन की चीजें सिर्फ़ इन जानवरो के फजले से मिल सकती हैं। अगर आप सारे देश में जमीन की फ़र्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप गोबर का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या करते हैं? सारे एनिमल्ज में बहुत थोडे एनिमल्ज ऐसे है, जो कि यूजलैस हैं—कोई डेढ़ परसेंट के करीब होगे लेकिन सारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उस के सब विशेषज्ञ यह कहने के लिए मिले हुए हैं कि वे सत्यानाश कर देंगे और वे सारा अनाज चारान अच्छे जानवरो के हिस्से का खा जाते हैं। जहां तक फ़र्टिलिटी का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बारह सालों में जमीन की कितनी फ़र्टिलिटी बढ़ाई गई हैं। पिछली दफा आई० सी० ए० आर० ने फिगर्ज दिए थे कि पैदावार बढ़ी हैं, लेकिन फ़र्टिलिटी नही बढ़ी हैं। अगर आप फ़र्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वह इन चीजों से बढ़ सकती है, जिनका

आपने अभी फ़ायदा नहीं उठाया है और न उठा रहे हैं । मैं कहना चाहता हू कि आप इसका फ़ायदा उठाइये और आपका प्राबलम खात्म हो जायेगा । जहा तक दूध का सवाल है, उसकी तरफ़ आपने न सिर्फ़ तवज्जह ही नही दी बल्कि एक क्रिमिनल नैगलैक्ट की है । आपने देश का सत्यानाश कर दिया है । यहा पर बच्चो, बूढो, औरतो और हर एक आदमी के लिए जो अव्वल दर्जे की खुराक थी, उसका आपने उपयोग नही किया । मैने इस बारे में एक सवाल पूछा था, जो कि २७ सितम्बर की प्रोसीडिंग्ज में छपा हुआ है । अगर मैं पढ़ कर सुनाऊगा, तो देर लग जायेगी इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज करना चाहता हू । गवर्नमेंट के जवाब में दर्ज है कि एक सेर दूध में नौ अडो की ताकत होती है, सेर भर गोश्त की ताकत होती है, आध सेर चिकन की ताकत होती है । उन्होने यह सब माना था । मै आपको फिगर्ज दूगा, जिन की रू से बिला शको-शुबहा इन विशेषज्ञो की मेहरबानी से इस देश मे १९५१ से १९५६ तक पाच करोड़ मन से ज्यादा दूध कम हो गया । मै आपकी तवज्जह इन एग्रीकल्चर ग्रीफ की तरफ दिलाना हू और इसके पेज ४० की तरफ दिलाता हू । इसमें लिखा हुआ है कि १९५१ में ५२ करोड मन दूध हुआ और १९५६ मे ४७ करोड मन । १९५१ व १९५६ की ग्रीफ की दोनो किताबें मेरे सामने है । मैने एक सवाल आनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछा था और मुझे यकीन है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जवाब को देखा होगा । लेकिन मैं समझता हू कि उनको दूसरे कामो से, गल्ले के काम से ही फुरसत नही मिलती है, इस वास्ते वह अधिक ध्यान इस तरफ नही दे पाते है । उन्होने उस जवाब में लिखा है कि १९५५ में हमने एक सर्वे कराया और उसमें १९५१ के फिगर निकाल लिये । यह आन दी फेस आफ इट एबसर्ड है, ल्यु-डिकरस है । हालांकि पहले की फिगर ५२ करोड़ की थी, लेकिन १९५१ की ४५ करोड़ की दिखला दी । छः सात करोड़ मन दूध ही खा गये । मै समझता हू कि फर्जी फिगर हमको दे दी गई है । सन् १९४१ से लेकर सारी फिगर्स मेरे पास मौजूद है । मैं आपको आपकी रिपोर्ट से भी बता सकता हू कि आपने ५२ करोड की जो फिगर लिखी वह ठीक लिखी और वह १९५१ की फिगर थी । अब फर्जी फिगर जवाब के लिये फर्जी घडली गई और इस बिना पर कि चूकि गाय ने ४१३ पाउण्ड से घटा कर ३६१ पाउण्ड दूध देना शुरू कर दिया और भैंस ने ११०१ के बजाये ९७० देना शुरू कर दिया इसलिये नई फिगर होनी चाहियें । आपने १९५१ की जानवरो की तादाद से ज़रब देकर यह किया है कि ५२ करोड के बजाय ४५ करोड थी । और इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अब ४७ करोड हो गया है । मैं कहना चाहता हू कि यह शर्म की बात है, पोच बात है और किसी रीज़निंग को यह स्टैण्ड नही कर सकती है । मैं कोई विशेषज्ञ नही हू । आपकी किताबो से यह जाहिर है और आपके विशेषज्ञो का यह मत है और बर्नेम जो कि एक बहुत भारी आथारिटी इस विषय मे थे उन्होने एक किताब लिखी है और उसके पेज १०९ में उन्होने कहा है कि इस देश के अन्दर गाय की पोटेंशियलिटी इतनी है कि गाय की ठीक खुराक होने से एक सेर की बजाय उससे डेढ सेर दूध लिया जा सकता है । उन्ही की यह राय नही है, यही राय राइट की भी है, आपकी रिपोर्ट जो मिल्क मार्किटिंग १९४१ के बारे में है, उसमें भी यही दर्ज है, फिर मार्केटिंग आफ मिल्क १९५० में भी आपने यही राय जाहिर की है । एक किताब होती तो मैं उसको न मानता लेकिन हर जगह पर यह चीज लिखी हुई है । इन सभी किताबो मे यह लिखा हुआ है कि गाय और भैंस की इतनी पोटेंशियलिटी महज ठीक फीडिंग से ही बढ जाती है और वह डयोढा दूध दे देती है । अगर गवर्नमेंट ने ठीक तरह से काम किया होता तो पिछले बारह सालो मे दूध की मात्रा ४८

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करोड़ से बढ़ कर ७२ करोड़ मन हो जाती । लेकिन गवर्नमेंट तो खरगोश की नींद सोई हुई है । गाय का नाम चूंकि हिन्दुओं के मजहब के साथ जुड़ा हुआ है और वे इसकी पूजा करते हैं, इसलिये वह उसके बारे में कुछ करना नही चाहती है । अगर उसका नाम हिन्दुओं के नाम से जुड़ा न होता तो उसकी हालत कुछ और ही होती । मैं नही कहता कि गाय के बारे में सभी एक सी राय रखें । हर एक को अपनी-अपनी राय रखने का हक़ हासिल है और कोई किसी को मजबूर नही कर सकता है कि वह मुख्तलिफ राय रखे । कृष्णप्पा साहब ने कहा था एक तकरीर में कि गाय फर्टिलाइजर भी है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है, चितरजन भी है, सिंधरी भी है । यह भी उन्होने कहा था कि इसके बिना गुजर नही है । अगर आप चाहते है कि खाने की चीजो की पैदावार बढे तो आपको दूध की तरफ भी ध्यान देना होगा ।

हमारी बहन श्रीमती रेणुका राय ने कहा कि बच्चो को दूध दिया जाए । विलायत के अन्दर, स्वीडन के अन्दर, डैनमार्क में बच्चो को मुफ्त दूध दिया जाता है । क्या हिन्द सरकार ऐसा कर सकती है ? यह करना तो दूर रहा, पिछले पाच साल में पाच करोड़ मन दूध कम हो गया है जिसकी कीमत कम से कम ८०० करोड़ होती है ।

मै आपको यह भी बतलाना चाहता हू कि मेरे देखते-देखते इस गवर्नमेंट ने हिसार की जितनी भी अच्छी-अच्छी गायों इत्यादि की नस्लें थी, उनको बरबाद कर दिया है । ८० बरस से हिसार से इनको कलकत्ता, बम्बई इत्यादि भेजा जाता था रहा है । एक बार इनका लैक्टेशन होता है और इसके बाद इनको बूचर के हवाले कर दिया जाता है । पंडित नेहरू ने हमारे कहने पर एक कमेटी की स्थापना की थी और उसके अध्यक्ष नन्दा साहब थे जिनका जिक्र सेठ गोविन्द दास जी ने किया है । मैं नन्दा साहब के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता । मैं उन लोगों के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता जो यह कहते है कि खराब गायों को मार दो । मै तो यही चाहता हू कि आप इसको एक इकोनोमिक यूनिट के तौर पर देखें । उस कमेटी ने चन्द तजवीजें रखी थीं और कुछ उसमें गलत बातें भी थी और अच्छी भी थीं । उनकी तरफ हमने गवर्नमेंट का ध्यान भी दिलाया था । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने उस कमेटी की सिफारिशों पर अमल तक नही किया है । हमारे देखते देखते जो गाय १०–१५ सेर दूध देती थी, आज ७–८ सेर दूध देती है ।

उनका दूध सूख गया है और यह सब गवर्नमेंट की खराब पालिसी के कारण हुआ है । इससे ज्यादा खराबी गवर्नमेंट की दूसरी नही हो सकती है कि उसने इन गायो का दूध सुखा दिया है । गायो की नस्लें खराब की है । और यह सब गवर्नमेंट की गलत पालिसी के कारण हुआ है । जिस गलत पालिसी पर पुरानी गवर्नमेंट ने अमल करना शुरू किया था उसी पर हमारी गवर्नमेंट अमल कर रही है ।

श्री ब्रजराज सिंह . गायो का दूध और इन्सानों का खून सूख गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमारे मिनिस्टर साहब कहेंगे कि आरे कालोनी और हरनघाटा को आकर देखो । हरनघाटा के बारे में यह कहा गया कि कलकत्ता की जरूरतों को हम पूरा कर रहे है । जहा तक आरे कालोनी का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि मिल्क पाउडर वगैरह पर कस्टम्स का जितना भी रुपया होता है वह सारे का सारा आप उसको नजर कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप सैल्फ सफिशेंट नहीं हैं । आपने वहां पर ८,०००

मैसें रखी हुई हैं, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि उन में से कितनों के बच्चे हैं जो कि बचे हुए हैं। ८,००० गायों के नीचे आठ हजार ही बच्चे होने चाहियें। मैं समझता हूं कि इन बच्चों की रक्षा न करके देश की दौलत को बरबाद किया जा रहा है। यही हालत हरन-घाटा कालोनी की है। वहां पर अच्छे-अच्छे गायों के बच्चे नीलाम किये जाते हैं और उनको कसाई ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी नस्ल चाहते हैं तो गायों इत्यादि के बच्चे पालना आपका फर्ज है।

एक सवाल मैंने पूछा कि पहले पांच साला प्लान में और दूसरे में कितना रुपया फाडर पर खर्च किया गया। मुझे इसका जवाब दिया गया कि उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। यह सुन कर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। आज मैं देखता हूं कि गायों को खाने के लिए नहीं मिलता है। हमारी गायों को इस तरह खाने को न देकर हमारी गवर्नमेंट ने भूखों मारा है, इन्सानों को ही नहीं, जानवरों को भी इसने भूखों मारा है। मैं समझता हूं कि उन्हीं को नहीं मारा है बल्कि देश को भी तबाह कर दिया है।

मैं समझता हूं कि देश के अन्दर परमात्मा की कृपा से काफी चारा खाने को है। लेकिन गवर्नमेंट खुद अपनी गलत पालिसी की वजह से न तो उनको चारा खाने देती है और न ही दूध ज्यादा होने देती है। दूध को गवर्नमेंट खुराक ही नहीं समझती है। यही नहीं इसका अन्न पर क्या असर पड़ सकता है और पड़ता है, इसकी तरफ भी उसका कोई ध्यान नहीं है। अगर पिछले पांच सात बरसों में दूध कम न होता तो क्या जरूरत थी बाहर से गल्ला मंगाने की। आपके प्लान में लिखा हुआ है कि अगर दूध ज्यादा हो जाए तो इसका असर गल्ले पर पड़ेगा। लेकिन आपने कोई ध्यान न देकर देश को बरबाद कर दिया है।

जानवरों की खुराक का ही सवाल लीजिये। आज आप हिन्दुस्तान के अन्दर चार परसेंट चारा बोते हैं। आप कहते हैं, हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि आज देश के अन्दर जानवरों में और इंसानों में कनफ्लिक्ट है कि चारा उगाया जाए या अनाज उगाया जाए। वे कहते हैं कि अगर चारा उगाया गया तो लोग भूखों मर जायेंगे। मुझे यकीन है कि हमारे मिनिस्टर साहब की यह राय नहीं है और अगर है तो मैं चाहता हूं कि वह इसको निकाल दें और इस राय को निकालने के लिए मैं आज उनको आथोरिटी देता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप विशेषज्ञों की राय को न मानें। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान एक बड़े आथर जिनका नाम रसल है, उनके द्वारा लिखी गई किताब के पेज ४२ की तरफ दिलाता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है:—

"A wider introduction of fodder crops into Indian agriculture would probably effect great improvement in yields and in total output. More food for the animals would mean more manure and enhanced fertility of the soil. This was the prime factor in the improvement of British agriculture and the additional yields of grain more than compensated for the area taken from grain and put into fodder crops. Leguminous fodder crops in addition to increasing the quantity of farmyard manure also enrich the ground on which they grow; they cannot usually be fed alone, however, and generally are mixed with non-leguminous crops."

इसका यह मतलब है कि अगर आप चार परसेंट के बजाय दस परसेंट यहां चारा उगाने लगें, तो इतना ही नहीं कि दूध की मात्रा बढ़ेगी और जानवरों को चारा मिल सकेगा बल्कि इन्सानों के खाने के लिये जितने भी बेंस हैं, उनके अन्दर भी तरक्की होगी। अगर एक आथर ने या एक ही किताब में इस तरह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

की बात लिखी गई होती तो मैं उसको डिसक्लिस कर देता लेकिन सभी जगह इस तरह की बातें लिखी गई हैं।

मैं एक और विशेषज्ञ की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं जो कि बहुत ही मशहूर आदमी है और जिस को पुरानी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने खुद बुलाया था। सफा ५६ पर राइट साहब लिखते हैं :

"I believe that it is necessary, however, to look at this subject from the wider aspect of the possible effect of a 'mixed farming' system on the productive capacity of the land."

जनाब वाला पिछली दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि इस देश में इंटेंसिव कल्टिवेशन होना चाहिये। लेकिन वह गैरमुमकिन है जब तक आप मिक्स्ड फार्मिंग न करें। मिक्स्ड फार्मिंग एक इंसिडेंस इंटसिव कल्टिवेशन है। इसलिये उन्होंने यह लिखा है :

"At present India is virtually attempting to maintain a relatively dense human population by methods only applicable to an 'extensive' system of farming, a system in which large acreages have to be relied upon to off-set low crop yields and poor grazing lands, and in which little attention is paid to the maintenance of soil fertility. Such methods may be suitable for newly developing countries such as Australia and Canada where the human population is small and ample land is available. In these two countries, there is, however, an average of only two to three persons per square mile. In India, there are nearly 200 persons per square mile, a figure nearly equivalent to that of Denmark. With such dense populations, it is essential that the output of produce per acre should be high, and for this purpose, the fertility of the soil must be maintained. It has aptly been said that under these circumstances the development of Indian agriculture urgently requires "the dove-tailing of the arable and animal husbandries into one 'mixed farming' system."

जनाब वाला, इस के अगले ही सफे पर इस से भी ज्यादा रिवीलिंग सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है इस वास्ते मैं उसे यहीं पर खत्म करता हूं। लेकिन फिर भी निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मामला इतना ही नहीं है। आई०सी०ए०आर० जो कि हमारा ही एक इन्स्टिट्यूशन है, उस ने खुद तजुर्बा कराया और उस के बाद एक ब्रोशर निकाला। एन० डब्ल्यू० एफ० पी० में, उत्तर प्रदेश में तजुर्बा कराया और देखा कि मिक्स्ड फार्मिंग का क्या असर होता है साढ़े बारह बीघे की होल्डिंग पर और वह इस ब्रोशर में दर्ज है। उन का तजुर्बा यह था कि मिक्स्ड फार्मिंग ही सिर्फ हमारे देश का वाहिद इलाज है और हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी इरिगेटेड लैंड्स हैं उन की पैदावार इस से कई गुनी हो जायेगी। कैटल भी बढ़ेंगे और ग्रेन भी कई गुना हो जायेगा। यही एक तरीका है जिस के ऊपर इन्हेसार कर के हम ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है, इस की तरफ तवज्जह नहीं दी गई अभी तक। अगर इस की तरफ तवज्जह दी जाती, अगर १०० मिलियन एकड़ पर मिक्स्ड फार्मिंग शुरू की जाती तो आप की सारी प्राब्लेम हल हो जाती। देश को जितने गल्ले की जरूरत है उस से ज्यादा गल्ला पैदा होता और मुझे यकीन है कि अगर यह डबल क्रापिंग की जाय तो हिन्दुस्तान जो ७० मिलियन टन की बात कहता है वह तो होगा ही उस से और ज्यादा भी होगा। अगर आप आइन्दा अपनी उपज बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी किस्मत आप के अपने हाथ में है और वह है ऐनिमल हस्बैन्ड्री की तरफ तवज्जह

देना । अगर आप ऐनिमल हस्बैन्ड्री की तरफ तवज्जह देंगे तो वह आप को रिच डिविडेंड दे करेगी । इस के सिवा और कुछ हो नहीं सकता । आप सोच सकते हैं कि मैं इसलिये कहता हूं कि गाय पर मेरा यकीन है लेकिन अपने देश की एकानमी में सब से ज्यादा यकीन रखता हूं और अगर आप उस को पूरी तरह करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि इस से आप को बहुत फायदा होगा ।

इस के अलावा मैं आप की तवज्जह इन सब चीजों को छोड कर जो सब से जरूरी चीज है उस की तरफ दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि अगर आप इस देश के अन्दर किसी गांव में जायें और वहां के जमींदारों से बात करें कि वह बतलायें कि आखिर देश की पैदावार कैसे बढेगी तो छोटे से छोटा जमींदार कहेगा कि बिना इन जानवरों की ठीक परवरिश किये पैदावार का बढ़ना गैरमुमकिन है । लेकिन आप उस की बात नहीं सुनते । आप ऐसे विशेषज्ञों की जो आप की हां में हां नहीं मिलाते, नहीं सुनते । आप सुनते हैं ऐसे लोगों की बात जो कि ठीक नहीं हैं, जो खेती से दूर रहते हैं, जो बात आप को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती । अगर आप इस तरह यकीन करें तो तीन बरस के अन्दर सारा मसला हल हो सकता है । मिल ने अपनी "पोलिटिकल एकानमी" में लिखा है कि ऐसे ऐग्रिकल्चरल देश में जहां पर जानवर इतने हों अगर किसी दूसरे देश का हमला हो जाये तो भी वह दस सालों में हरा भरा हो सकता है । हमारे मुल्क के अन्दर इतनी उम्दा चीजें मौजूद हैं । पंडित जी रोज कहते हैं कि हमारे यहां दूनी पैदावार क्यों नहीं होती ? क्यों चाइना में ४० परसेंट पैदावार बढ़ गई है और हमारे यहां नहीं बढ़ती ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह गैरमुमकिन है जब तक आप ट्रैक्टिव पावर की तरफ तवज्जह नहीं देंगे । आज आप के पास ३६ मिलियन एकड़ जमीन है ।

15·55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

लेकिन आप के पास सिर्फ १८००० ट्रैक्टर्स हैं । अगर एक ट्रैक्टर १०० एकड की जोताई भी करता हो तो आप कुल जमीन का १ परसेंट ट्रैक्टर के जरिये से जोतते हैं । बाकी सारी की सारी जमीन बैलों के जरिये जोती जाती है । मैं एक पते की बात बतलाता हूं । आज आप किसी कल्टिवेटर से पूछ लीजिये जब तक आप गेहूं की फसल का ६ दफा वाहम नहीं करेंगे तब तक उस में पूरी फसल नहीं होगी । पंजाब का जमींदार हमारे यहां से ज्यादा गल्ला पैदा करता है उस की दो वजूहात हैं । एक तो पानी और दूसरी ट्रैक्टिव पावर । उन के यहां छ दफे फसल वाहम होती है इसी लिये उतने खेत में हम उतनी फसल पैदा नहीं करते क्योंकि हम छ दफे फसल को वाहम नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान के अन्दर एक बडी भारी अथारिटी ने लिखा है कि जितनी फ्रीक्वेंट कल्टिवेशन आप करेंगे उतना ही अनाज होगा । लेकिन आप के पास ट्रैक्टर भी पूरे नहीं, बैल भी पूरे नहीं । आप के यहां २ करोड बैलों की कमी है । एक न्यूट्रिशन की किताब में लिखा है कि बैलों का एक पेअर ८ एकड को जोतता है । आप की मार्केटिंग आफ कैट्ल नाम की किताब में लिखा है कि एक बैलों का पेअर ६ एकड को जोतता है । सन् १९२८ में वह १० एकड जोतता था, ऐग्रिकल्चर कमिशन की रू से । मैं अर्ज करता हूं कि आप के पास ६ करोड १७ लाख काम करने वाले बैल हैं जब कि आप को चाहिये ९ करोड जानवर, अगर आप आर्डिनरी खेती करें । प्रोडक्टिव पावर ट्रैक्टर्स से होती है । आज दिल्ली में घूम आइये आज आप के पास ट्रैक्टर नहीं हैं । आप ने उस के ऊपर इतना कस्टम रखा है । आज हालत यह है कि ट्रैक्टर आप के पास काफी नहीं है । आज बैल आप के पास काफी नहीं हैं । आज गधे जोते जाते हैं, गाय जोती जाती हैं, आदमी जोते जाते हैं खेती के वास्ते ।

श्री ब्रज राज सिंह : गधे बढ़ते आ रहे हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप इस को डाउट कर रहे हैं, लेकिन यह रिपोर्ट दिया हुआ है ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं ने कहा कि गधे बढ़ते जा रहे हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब तक आप ट्रैक्टिव पावर उन के पास नहीं पहुंचायेंगे तब तक आप का मसला हल नही होगा । उस के पहुंचाने की तरकीब यह है कि आप बैलों का इन्तजाम कीजिये । उन से ६० परसेन्ट ट्रैक्टिव पावर बढ जाती है ।

मैं इस लिये सिर्फ तीन चीजें ही कहना चाहता हूं जिन को आप को फौरन अपनाना चाहिये । एक तो मिक्स्ड फार्मिंग, दूसरे ऐनिमल हस्बैन्ड्री का ठीक इन्तजाम । मैं ने अभी अभी आप को पढ कर सुनाया कि कम से कम १० करोड रुपया ऐनिमल हस्बैन्ड्री के लिये आप को खर्च करना चाहिये । तीसरी चीज यह है कि आप एक अलाहदा मिनिस्टर रख दीजिये जो कि इन चीजों की तरफ तवज्जह दे सके । आप को तो फूड से ही फुर्सत नही मिलती । जब मैं ने यह कहा था तो मुझे जवाब मिला कि इस मे खर्च ज्यादा बढ़ जायेगा । मै ने उस वक्त कहा था कि हां, खर्च जरूर बढ जायेगा लेकिन यहां तो अक्ल की कमी है । मै अर्ज करूगा कि एक अलाहदा मिनिस्टर जब तक आप नही करेंगे तब तक आप प्लैनिंग में सेपरेट रिप्रजेन्टेशन नही देंगे, जब तक सारी स्टेट्स के अन्दर एक अलाहदा एनीमल हस्बैन्ड्री मिनिस्टर नही होगा तब तक आप की पैदावार नही बढ़ सकती और हिन्दुस्तान की हालत खराब होती जायेगी । आप को चाहिये कि आप इस की तरफ तवज्जह दें ।

Mr. Deputy-Speaker: The following are the selected cut motions relating to the Demands under the Ministry of Food and Agriculture which may be moved subject to their being otherwise admissible:—

Demand No.	*No. of Cut Motion*
36	286 (Disapproval of Policy), 287 (Disapproval of Policy), 1336 (Disapproval of Policy), 1337 (Disapproval of Policy), 1338 (Disapproval of Policy), (Token) 213, 281, 282, 283, 284, 285, 574, 843, 844, 1078, 1079, 1670, 1671, 1672, 1690, 1691, 1692, 1693, 1774, 1775, 1776, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825.
37	661, 662, 663, 1694, 1695, 1696, 1697, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1778.
38	344, 345, 615, 616, 617, 618, 619, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 664, 665, 666, 667, 668 669, 815, 816, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 1080, 1081, 1082, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1673, 1674, 1675, 1698, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771.
39	346, 347, 362, 363, 1083, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1844, 1845.
40	1779, 1780, 1781, 1782, 1783.
41	1084, 1699, 1700, 1847, 1848.
119	1849.
120	1677, 1701.
121	1090.

Export of beef from India

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced to Re. 1."

Slaughter of cows, bulls, oxen, calves and buffaloes

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced to Re. 1."

Restriction on manufacture of gur in Sugar Factory Reserve Zones

Shri S. L. Saksena: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced to Re. 1."

Restriction on manufacture of Khandsari in Sugar Factory Reserve Zones

Shri S. L. Saksena: I beg to move

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced to Re. 1"

Failure to raise the minimum price of sugarcane to Rs. 1·75 per maund

Shri S. L. Saksena: I beg to move

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced to Re. 1"

Rise in prices of food stuffs

Shri P. T. Punnoose: I beg to move

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for fixation of higher prices of foodgrains in West Bengal and other States

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to provide equitable and reasonable prices for agriculture goods

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to raise the living standard of agriculturists

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to keep purity of prices between agricultural goods and other necessities of life.

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food & Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to construct tubewells successfully in Chausma and Vijapur and other taluks of Mehsana district of Bombay State

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to bring down food prices

Shri S. L. Saksena: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for fixation of lower prices of foodgrains in Uttar Pradesh

Shri Sarju Pandey: I beg to move

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to provide aid to Agriculturists holding small pieces of land in the rural areas

Shri Sarju Pandey: I beg to move

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for coordination of the work of the Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Irrigation and Power

Shri B. Das Gupta: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for giving priority to cooperative societies for the allotment of fair price shops

Shri B. Das Gupta: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to curb the tendency of rising prices in lean months

Shri Nagi Reddy: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to supply rice to the Kerala States

Shri Nagi Reddy: I beg to move.

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to purchase rice in the harvesting season

Shri Nagi Reddy: I beg to move·

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to open cheap grain shops in the scarcity areas of Orissa State

Shri P. K. Deo: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Method of fixing the procurement price of foodgrains

Shri P. K. Deo: I beg to move·

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Desirability of raising the procurement price of foodgrains

Shri P. K. Deo: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Irregularities in the appointment of purchasing agents for foodgrains

Shri P. K. Deo: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for self-sufficiency in food

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure of Japanese method of rice cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Introduction of Chinese method of rice cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move·

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs 100"

Supply of foodgrains to Uttar Pradesh

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Functioning of Central Tractor Organisation

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Supply of wheat to Flour Mills

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to set up a Price Stabilisation Committee

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Grow more food scheme

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to stabilise the prices of foodgrains in the country

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for fixation of sugar-cane price in Uttar Pradesh and Bihar at Rs 1 75 per maund

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to treat Uttar Pradesh Delhi and Punjab as one zone

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100"

Failure to tackle effectively the problem of soil erosion

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Failure to check deforestation.

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100"

Necessity to grow grass on upper slopes of hills bunding and terracing to afford protection against soil erosion

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100"

Desirability of taking up large scale afforestation in the Mahanadi Basin

Shri P. K. Deo: I beg to move.

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Need for arresting the inroads of the great Indian desert by taking up afforestation work

Shri P. K. Deo: I beg to move.

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100"

Desirability of rehabilitating the Adivasis displaced by the stoppage of shifting cultivation on the hill slopes.

Shri P. K. Deo: I beg to move·

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Need for scientific working of the village forests and other community forests

Shri P. K. Deo: I beg to move

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs 100."

Failure to utilise wood for manufacturing paper

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Want of scientific cultivation of medicinal plants

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move·

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Need of a pharmaceutical research laboratory for experimentation in medicinal plants

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Importance of afforestation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Need for scientific selection of dry regions for afforestation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Need to link up afforestation and forest clearance

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs. 100."

Need for soil conservation on a wider scale

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Forest be reduced by Rs 100."

Failure to reclaim flaw and waste land for cultivation

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to provide fertilizers to the farmers of Gujerat and Bombay State

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Failure to put the sugar economy on sound footing

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to increase the yield and to improve the quality of sugarcane

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to bring down the cost of production of the sugar

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Lack of market intelligence regarding agricultural products

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100."

Need for prevention of excessive price fluctuations in Indian Mandis

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Problem of multiplication and distribution of seeds

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Failure to supply pest free potato seed to cultivators

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Failure to prevent adulteration of food-stuffs

Shri D. R Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to prevent adulteration of potato seeds

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to popularise compost, night-soils, bone meal and green manure

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Defects in the present system of agricultural marketing

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Lack of storage facilities in the Indian villages

Shri D. R. Chavan: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to provide mandies in India with ware-houses

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure of grow-more food campaign

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to attain self-sufficiency in food production

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to control effectively pests and plant diseases

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to step up the tempo of land reclamation

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to check effectively the wastage of the cow-dung manure

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to supply fertilizers in sufficient quantities to farmers

Shri D. R. Chavan: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to provide quality seeds to Agriculturists

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to remove mal-administration from marketing yards

Shri M. B Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Failure to prevent adulteration of grain and potato seeds

Shri Sarju Pandey: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to popularise compost, night soil and green manure

Shri Sarju Pandey: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Need for storage facilities in the villages mainly in Uttar Pradesh

Shri Sarju Pandey: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to prevent mal-practices in the seed stores

Shri Sarju Pandey: I beg to move·

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100."

Administration of the marketing yards

Shri Sarju Pandey: I beg to move·

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to provide quality seeds and cheap manure to agriculturists

Shri Sarju Pandey: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Failure to increase the price of sugarcane from Rs. 1·44 to Rs. 1·75 per maund

Shri Sarju Pandey: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to bring down the cost of production of sugar

Shri Sarju Pandey: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to increase the yield and to improve the quality of wheat

Shri Sarju Pandey: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to maintain balance between the prices of agricultural and industrial commodities

Shri Sarju Pandey: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to allot more funds for minor irrigation works

Shri Nagi Reddy: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Failure to increase the production of foodgrains

Shri B. Das Gupta: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Ways and means of improving the potentiality of cultivators for foodgrains production

Shri B. Das Gupta: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Retrenchment and working conditions of the employees of the Central Tractor Organisation

Shri B. Das Gupta: I beg to move·

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Failure to improve the low morale in agricultural services

Shri U. L. Patil: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100."

Failure to expand the field of agricultural services according to the growing need of the country

Shri U L Patil: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Failure to have proper co-ordination between the Departments of Agriculture and Irrigation

Shri U L Patil: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need to evolve a model agricultural organisation to suit the present needs of the country

Shri U L Patil: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Working of the Agriculture Department

Shri U L Patil: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need to step up research programmes and teaching in agricultural services

Shri U L Patil: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Insufficient and belated supply of fertilizers

Shri U L Patil: I beg to move.

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Insufficient marketing and storage facilities for agriculturists

Shri U L Patil: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need to stabilise price level of agricultural produce

Shri U L Patil: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Failure to check the falling prices of jute

Shri Nagi Reddy. I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Failure to provide marketing facilities to tobacco growers

Shri Nagi Reddy. I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need for proper co-ordination between irrigation co-operation, revenue and agricultural departments

Shri Nagi Reddy: I beg to move

'That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Introduction of Chinese method of cultivation of paddy in this country

Shri P K Deo: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Failure to fix up proper price of sugar-cane

Shri Aurobindo Ghosal. I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need to develop the quality of sugarcane

Shri Aurobindo Ghosal. I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need to set up model Government farms for sugar-cane cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Inadequacy of locust warning organisation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to set up units of locust warning organisation region-wise

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Adulteration in vanaspati

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for better marketing system for jute

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Incentive for the production of vegetable oil seeds

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Publication of marketing journals in regional languages

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for improvement in cashew-nut cultivation in the Midnapur District of West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Expenditure on Gosamhardhanam

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure in raising the standard of livestock in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Aid to tobacco cultivators of West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100."

Need for Government ware-housing for tobacco

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Abolition of 'mahajan' system in tobacco cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for simplification of laws for retaining tobacco by the cultivators

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Marketing of tobacco through Co-operatives

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Improvement of lac cultivation in the Purulia district of West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Proper grading of cows and bulls for artificial insemination

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Publicity of artificial insemination scheme for live stock in regional languages in rural areas

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Absence of comprehensive agricultural marketing system

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for introduction of agricultural marketing scheme crop-wise

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need for co-operatives in Agricultural marketing

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100".

Failure to introduce quality control of food grains

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100."

Research for ascertaining the food value of vanaspati

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Research for ascertaining the effect of vanaspati on the human heart

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Administration of Central Mechanised Farm

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to allot more funds for the improvement of ground-nut cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to allocate more funds for improving linseed cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure of the artificial insemination of live stock scheme in rural areas

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to give encouragement to poultries in rural areas as a part of cottage industry

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be redueed by Rs. 100."

Disposal of good tractors

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for supply of more fertilizers

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Diversion of fertilizers to tea-gardens

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for more nitrogenous fertilisers

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for proper distribution of fertilisers

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need of more trawlers for deep sea fishing

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

Undesirability of monopoly business in fish

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100"

High price of fish in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need of better preservation system for fish

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need of quicker transport for fish

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to give encouragement to long-staple cotton cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Desirability of grading ghee according to the standard of cows and buffaloes

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to standardise ghee on the basis of properties available in the milks of respective regions

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need for better grading of wool

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Use of goat-hairs

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to give impetus to horticulture

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Improvement of tobacco cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Failure to improve fruit products in Himachal Pradesh

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to provide cheap transport for fruits

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need to provide quick transport for fruits

Shri Anrobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100."

Inadequate storage system for fruits

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Need for improvement in the fruit packing system

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agriculture be reduced by Rs 100"

Failure to open sub-Agricultural Research Centres all-over India

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 1oo."

Failure to make any research to protect pulses, jowar and bajra from decay

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Failure to protect 'jeera' from damage by different type of insects

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Failure to make agricultural land fit for 'Jeera' cultivation for more than four years

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs 100."

Need for supplying information about agriculture obtained by research to the peasants extensively

Shri B. Das Gupta: I beg to move

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for incentive to gur and khandsari sugar production

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

High prices of milk

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Introduction of hybrid breeding of milch cows

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for supply of adequate fodder for cows

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100"

Need to exhibit films on agricultural topics in regional languages in rural areas

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Selection of crops on the basis of soil testing

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for introduction of bee-keeping as a cottage industry

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move.

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Restrictions on poppy cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for proper botanical survey of all regions

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for more pasturage

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Introduction of mobile vans for instructions to cultivators in village areas before cultivation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need to establish a modern fish processing plant at Balugaon in Orissa to exploit the Chilka lake fish sold out at Calcutta markets

Shri Bamra: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need to establish an All India Deep Fishing Industry by use of modern methods to catch sea fish all round over Indian ocean

Shri Bamra: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for improvement in rearing system of sheep

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for imparting preliminary veterinary education to peasants

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need to provide more veterinary doctors in rural areas

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for supply of good bulls to rural breeding centres

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Need for better breeding of cows in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head Agricultural Research be reduced by Rs. 100."

Import of foodgrains from foreign countries

Shri B. Das Gupta: I beg to move:

"That the demand under the head Miscellaneous Departments and other Expenditure under the Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Preservation of wild life in the country

Shri P. K. Deo: I beg to move:

"That the demand under the head Miscellaneous Departments and other Expenditure under the Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Urgency of stopping poaching in the game sanctuaries

Shri P. K. Deo: I beg to move:

"That the demand under the head Miscellaneous Departments and other Expenditure under the Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to supply pamphlets regarding various aids etc. for the development in agriculture and allied subjects in regional languages direct to farmers and villagers in India

Shri Bamra: I beg to move:

"That the demand under the head Miscellaneous Departments and other Expenditure under the Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Need to construct food storage godowns at Bagdia and Kiakata (Distt. of Dhenkanal) and at Bhojpur and Barkote (Distt. of Sambalpur in the State of Orissa).

Shri Bamra: I beg to move:

"That the demand under the head Miscellaneous Departments and other Expenditure under the Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Desirability of establishing a forest school at Garposh in the Distt. of Sambalpur (Orissa) to meet the growing demand in the Eastern region

Shri Bamra: I beg to move

"That the demand under the head Capital Outlay on Forests be reduced by Rs. 100."

Failure to implement the State trade in foodgrains

Shri Nagi Reddy: I beg to move

"That the demand under the head Purchase of Foodgrains be reduced by Rs. 100."

Defects of the State trading in foodgrains

Shri P. K. Deo: I beg to move:

"That the demand under the head Purchase of Foodgrains be reduced by Rs. 100."

Need to establish Central institutions in every district for training of peasants in improved and up-to-date agricultural methods

Shri B. Das Gupta: I beg to move

"That the demand under the head Other Capital Outlay of the Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

Mr. Deputy-Speaker: All these cut motions are now before the House

Shri Supakar (Sambalpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, day-before yesterday, a document was circulated amongst Members and it gives an insight into the tragic realities of our food situation and strongly contradicts the observations made by Pandit Munishwar Dutt Upadhyay that during the last four or five years the population of India has gone on increasing by about 1·25 per cent every year and that food production during the last four years from 1953 to 1957 has been almost steady and there has been a sharp decline in the year 1957-58. Now, I shall come to discuss these details at a later stage, but I wish to ask, first of all, this question. How are the Government going to achieve the targets laid down in the Second Five-year Plan if this is the progress of our food production? It was stated in the Second Five-year Plan that the normal requirement of an average human being is 3,000 calories and in terms of foodgrains, it comes to about 22·4 ounces, that is to say, about 11 *chataks*.

If we take into account the growth population by the year 1960 as stated in page 1 of the bulletin, we might assume that the population by 1960 or at the beginning of the Third Five Year Plan will be 40 crores, and then the average requirements of food production will be about 91 million tons every year; that is the net figure, not the gross figure.

16 hrs.

But we find that though 3000 calories have been fixed as the minimum requirement, according to scientific standard, the Second Five Year Plan has fixed a very modest target, namely 75 million tons by the end of the Second Five Year Plan One year after the publication of the Second Five Year Plan, this valuable document *Indian Agriculture in Brief* was brought out, and there it was stated that the target was further increased. It was stated there that by the end of the Second Five Year Plan, the annual production of foodgrains will be 80 5 million tons If we see the actual figures mentioned at page 9 of this document, we find that the total production of foodgrains in India in the year 1953-54 was 68,718,000 tons in 1954-55 it was 66 million tons, that is, it was less; in 1955-56 it was still less, namely 65 million tons, in 1956-57 it was 68 million tons and there is a sharp decline in 1957-58, and it comes to 62 million odd tons

Converted in terms of the *per capita* consumption of ounces of foodgrains, it comes to 18 08 oz in 1953-54, and in the year 1957-58, if we take the population figure to be 39 crores, it comes to 15 52 oz That is less than 75 per cent. of the optimum, that is the minimum requirement of foodgrains This is the all-India average

But if we come to the poorer States of India like Orissa—I have made the calculation for 1957-58—it comes to 13·2 oz per head per day in Orissa Whereas the total calorie requirement is 3000 calories per day, this 13·2 oz converted in terms of calories comes to only 1772 calories per day This is a sad state of affairs, and this goes to show that in spite of the Second Five Year Plan and in spite of the fact that we have covered more than three years of it already, we have not gone forward in the production of foodgrains. Now, contrast this with the statement of the President in his Address about two years ago, that is, in 1957, that as a consequence of our National Extension Service programme and the community development programme in those areas, the production of foodgrains has gone up by 25 per cent. If this is a fact, we cannot escape from the conclusion, since the average production has been going down, that this so-called increase by 25 per cent in the community development areas is either unreal or there has been a still sharper decline in the production in the rest of the area We know that a good deal of the total area of India is now covered either by the community development programme or by the national extensive service programme This shortfall in production has entailed a large volume of import, and that is an alarming situation, and it necessarily involves a large expenditure in terms of foreign exchange Figures have been quoted here In 1956-57 it was of the order of Rs 162 crores.

We find that the per ton value of imported foodgrains has been going up It came to nearly Rs 457 in 1957 whereas in 1956 it was only Rs 338 Thus, we see that in the course of these eleven years there has been a steep rise in the prices of imported foodgrains This figure is the landed cost per ton in India inclusive of freight charges If we compare this with the internal prices of foodgrains, you will see that there is a good deal of difference How is this accounted for?

This brings me to the question of maladjustment or rather the indolence in the policy of the Government Before 1952-53 the Government used to give a certain amount of money as subsidy to the States for the distribution of foodgrains imported from abroad or procured inside the country This system has now been abolished While on the one hand we hear complaints that the water meant for irrigation is not being made use of on account of betterment levy and the high water rate, on the other hand we import a large quantity of foodgrains at a very high price, and since we are not able to pay the price

[Shri Supakar]

immediately, we have to pay interest also on the amount till we are able to repay it. This creates a dilemma. I believe if the Government could reorientate their policy so as to adjust the extra amount they have to pay for import of foodgrains with the strict policy of exacting a betterment levy at a rate which the cultivator finds it uneconomical, there could be a good drive to food production.

For example, if we pay an extra amount of Rs. 100 for each ton of foodgrains that is imported as compared with the price of foodgrains available from the internal market, and if we could give the benefit of some of this money to the actual producer by giving him some relief in the betterment levy and the water charges in the irrigated area, I believe for every ton of additional foodgrains produced in our country, we could save not only Rs. 100 as such but probably Rs. 100 every year per ton, excluding interest.

If the Government take into calculation these factors and give relief to the producers, I believe the producers could be encouraged to grow more foodgrains and to make better utilisation of the water made available. That would also put a stop—or at least put a stop—to the agitation that is going on in some parts of the country. I hope the Government would take a rather long-sighted view of these matters and see what is the best way of diminishing the import of foodgrains from foreign countries and giving a stimulus to the producer.

I am sorry to say that this year though the Government were very glad to find that the harvest is a bumper harvest, as I have submitted earlier, they have bungled the whole situation and neither the producer nor the purchaser has been able to take the advantage. I will not labour this point because I have dealt with it on an earlier occasion.

I will just say a word or two regarding the agriculture departments and conclude. Unless the Governments, at the Centre and in the States, improve the agriculture departments, there is no hope of our proceeding further towards becoming self-sufficient in the production of foodgrains. In spite of the fact that we attained independence 12 years ago, in spite of the agriculture departments in the States and in the Centre, in spite of the fact that national extension service and community development programmes are there to give a stimulus to our food production drive, the agriculture department has become more or less a greenhouse plant. It has not taken deep root in the soil of our country and has not been popular with the agriculturists. They have not much benefited from the researches and the advantages offered by the agriculture department. The Government must have some sort of heartsearching and see what is the best way of making the agriculture department really serve the purpose for which it is there

In this connection, I will only say that the Government should lose no time, if they are quite serious about it, in implementing the recommendations of the Agricultural Administration Committee. They have made some valuable suggestions in the matter which, if implemented, will, I believe, help the agriculture department to become stronger.

Mr. Deputy-Speaker: Ch. Ranbir Singh.

श्री नवल प्रभाकर : (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनसूचित जातियां) उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली वालों को भी समय मिलना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: If hon. Members from the Congress Party agree to take ten minutes each, a larger number could be accommodated.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I hope they will fully co-operate.

Mr. Deputy-Speaker: May I enforce the ten-minute limit for Congress Members at least?

Shri Satya Narayan Sinha: Yes. On behalf of the Party, I would request you that that be enforced because a larger number of Members could be accommodated thereby. Let us co-operate.

Some hon. Members: Yes.

Pandit Thakur Das Bhargava: It will be discriminatory.

श्री० रघबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को मुबारकबाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि इस बात के बावजूद कि यह संसद् मन्त्रालय को उतना रुपया नहीं दे सकी, जितना कि उस ने मसूरी कान्फरेंस के जरिये मांगा था, वह आगे बढ़ रहा है । कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद खेत की पैदावार कम हो रही है और इसी लिये शायद देश को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है । उन्हें मालूम नहीं कि जहां देश में हर साल पचास लाख के करीब आबादी में बढ़ोतरी होती है, वहां ऐसे भी बहुत सारे भाई हैं, जो पहले बाजरा खाते थे और आज गेहूं खाते हैं । मुझे खुशी है कि जो गरीब भाई पहले गेहूं नहीं खा सकते थे, चावल नहीं खा सकते थे, आज देश में ऐसी हालत पैदा हुई है कि वे भी गेहूं और चावल खा सकते हैं । इस के साथ साथ हैल्थ मिनिस्ट्री के काम की वजह से देश का स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है और उस की वजह से आदमी का जीवन लम्बा होता जा रहा है और यह अन्दाजा लगाया गया है कि हर आदमी पांच साल ज्यादा जिन्दा रहता है । यह भी खाता ही है । इन सारे मसलों का हल खाद्य और कृषि मंत्रालय ने करना है । मेरी राय है कि इस मंत्रालय को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए—एक खाद्य मंत्रालय रहे, एक कृषि मंत्रालय रहे और एक पशु-पालन का मंत्रालय अलाहिदा बनाया जावे ।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : पशु और पक्षी ।

श्री० रघबीर सिंह : ये तीनों मंत्रालय बहुत जरूरी हैं । ये आपस में एक तरह के विरोधी हैं । खाद्य मंत्रालय का काम है कि देश के लिए सस्ते से सस्ता अनाज दे और कृषि मंत्रालय का काम है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर के दे । कृषि मंत्रालय का यह काम हो सकता है कि इस देश में ज्यादा ट्रैक्टर बनाये, छोटे ट्रैक्टर बनाये, ताकि इस देश में जो बहुत बड़ी तादाद में खेती करने के लिये ऊंटों, बैलों, खोटों, घोड़ों और खच्चरों की आवश्यकता पड़ती है, वह कम हो, ताकि किसान जितना पैदा करता है, वह सब अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने सुख और आराम के लिए इस्तेमाल कर सके ।

मैं मानता हूं कि जो दूध देने वाले पशु हैं, उन की तादाद बेशक बढ़े और उन की दूध देने की शक्ति भी बढ़नी चाहिए और इस के लिए जरूरी है कि एक पशु पालन मंत्रालय अलाहिदा बनाया जाये ।

एक माननीय सदस्य : पशु मन्त्रालय ?

श्री० रघबीर सिंह : उस मन्त्रालय की उधर जरूरत है । पशु-पालन मंत्रालय ।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : पशु और पक्षी मंत्रालय ।

श्री० रघबीर सिंह : सवाल यह है कि इस देश में खेती की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है । आप को यह जान कर ताज्जुब होगा कि १९४६ से ले कर १९५८ तक इस देश में बाहर से जो अनाज आया है, उस की कीमत १४५६ करोड़ रुपये है और उस पर जो सबसिडी दी गई है, वह २४० करोड़ रुपये है और इस के अलावा जो बोनस की शक्ल में दिया गया, वह २१ करोड़ है । दूसरे मायनों में जो भाई अनाज खाते हैं, उन के लिए एक तरफ देश के बाहर से १४५६ करोड़ का अनाज

[चौ० रणबीर सिंह]

मंगाया गया और उन को सस्ता अनाज खिलाने के लिए २६१ करोड़ रुपया खर्च किया गया । आप को यह जान कर ताज्जुब होगा कि इस के मुकाबले में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए या पानी का इन्तजाम करने के लिए देश में कितना रुपया सबसिडी या मदद के तौर पर खर्च किया गया । पहले पाच साला प्लान मे ८,२०,००,००० रुपये रखा गया । १९५६-५७ और १९५७-५८ को भी उस में शामिल कर दिया जाये तो ११ करोड १९ लाख रुपया हो जाता है जिस के मुकाबले में २६१ करोड़ रुपया सस्ता अनाज लोगो को खिलाने मे खर्च किया गया है । आप जानते ही है कि देश की अनाज की पैदावार बढाने के लिए देश के अन्दर जो दरिया हैं, उन के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है । मै समझता हू कि इस प्रोग्राम को आपको और भी बढाना होगा । आप भाखडा डैम के ऊपर १७० करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और इसके ऊपर ५० करोड रुपया सूद का लगेगा । तकरीबन २१ फी सदी रुपया अनाज की पैदावार बढाने के लिए किसानो को सूद की शक्ल में देना होगा । किसानो मे तो २१ फी सदी रुपया सूद का लिया जायेगा और दूसरी तरफ २६१ करोड रुपया और लोगों को मुफ्त मे दिया जाता है ।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) . यह आपकी पार्टी का कसूर है ।

चौ०रणबीर सिंह: मै समझता हू कि इसके अन्दर मेरे दूसरे साथी भी शामिल हैं क्योंकि वह भी ससद् के सदस्य हैं और दूसरे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वे भी शामल हैं । इन साथियों ने कोशिश की थी इसके बारे में लेकिन वे नाकामयाब रहे हैं और वे इसलिए नाकामयाब रहे हैं कि लोग समझते है कि उनके अन्दर ताकत नहीं है और जनता के पास ही ताकत है । लोग चाहते हैं कि जल्दी से भाखड़ा डैम को बनाया जाये और जितना कम से कम बोझ किसानों के ऊपर पड सकता है, पड़े । चूंकि लोगो को गवर्नमेंट में विश्वास था इसलिए उन्होने इन साथियों का साथ नही दिया । मेरी हमदर्दी लोगों के साथ है। मेरे साथी दौलता साहब जेल हो आये हैं, मैं इसको जानता हूं । मै समझता हूं कि आज भी पंजाब के लोगों का मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों के ऊपर विश्वास है, किसानो का उनके ऊपर विश्वास है । कैरों साहब ने बैटरमेंट लेवी का जो १११ करोड़ का अंदाजा था उसको घटवा कर ३३ करोड़ कर दिया है । किसान लोग जानते है कि भारत की और पजाब की सरकार जो कुछ उनके लिए कर सकती है, करेगी ।

मै कहना चाहता हू कि हमारे भाई जो शहरो के अन्दर रहते है, उनके पास अखबार है, उन के अन्दर ताकत है, उनकी आवाज ऊची है और इस सदन के अन्दर भी और बाहर भी वे अपना दबाव डाल लेते है । यही वजह है कि उनको २६१ करोड रुपया मिला । वर्ना आज अगर कोई दोस्त कहे कि बिना गुड डाले या थोडा गुड डाले ज्यादा मीठा हो जाये, तो यह नही हो सकता है, जितना गुड डाला जायेगा उतना ही मीठा होगा । मै समझता हू कि तकरीरो मे ज्यादा अनाज पैदा होने वाला नही है और जो समझते है कि यह हो सकता है वे भ्रम में है । अनाज अधिक पैदा करने के लिए पैसा खर्च करना होगा और किसानो को रुपया देना होगा ।

सर्विस कोआपरेटिव्स का जिक्र भी किया जाता है । मुझे मालूम है कि सार्ज साइज कोआपरेटिव चलाने के लिए जो इमदाद दी जाती थी उस इमदाद को प्लानिंग कमिशन की सलाह के ऊपर बन्द किया गया है । आज हमारे देश के अन्दर एक नया युग शुरू होने जा रहा है । मुझे मालूम नही आया वह युग तकरीरो से शुरू हो सकेगा या उसके लिए हम रुपया खर्च करने को भी तैयार हैं । अगर खर्च करना है तो मैं समझता हूं कि कम से कम १५०

करोड़ रुपया कैपिटल चाहिये सर्विस कोआप्रेटिव्स में हिस्सेदारी के लिये । इसके साथ ही साथ कम से कम ३० करोड़ रुपया उन कार्यकर्ताओं पर खर्च करना पड़ेगा जोकि शुरू शुरू में वहां पर काम करेंगे और इस काम को आगे बढ़ायेंगे । उनको हमें इतने रुपये की मदद देनी होगी । इसके अलावा कम से कम १,००० करोड़ रुपया बतौर कर्ज के देना होगा ।

आज देखा जाता है कि अगर कोई किसान अपने खेत के अन्दर कुआं लगाना चाहता है तो उसको रुपया नहीं मिलता है, कर्जा नहीं दिया जाता है । अगर खाद्य और कृषि मंत्रालय अनाज ज्यादा पैदा करवाना चाहता है तो उसे ज्यादा रुपया इस तरह के कामों के लिए कर्ज देना होगा ।

मैं मानता हूं कि आज भी देश के ऊपर ११०५ करोड़ रुपये का कर्जा है और उस पर हमें ब्याज देना पड़ता है । लेकिन ऐसी चीजों पर खर्च होते हैं जहां से ब्याज नहीं मिलता है, जो इंटरेस्ट बेयरिंग आबलीगेशन्स के अन्दर शामिल होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बेयरिंग सेट के अन्दर वह रकम शामिल नहीं है, उसके मुकाबले में डिफिसिट फाइनेंसिंग की रकम कोई १५०० करोड़ के करीब की है । मैं समझता हूं कि अगर डिफिसिट फाइनेंसिंग को कामयाबी के साथ चलाना है तो यह जरूरी है कि रुपया खाद्य और कृषि मंत्रालय को दिया जाये ताकि सस्ता अनाज पैदा हो सके और उसकी कीमत ना बढ़ सके ।

अब मैं खंडसारी और गुड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । अजीब बात है कि यू० पी० के अन्दर गुड़ का सट्टा करने के लिये चार पांच सैंटर्स को इजाजत दी गई है । लेकिन पंजाब के अन्दर एक भी सैंटर को इजाजत नहीं दी गई है । अगर सट्टा बुरी चीज है तो वह पंजाब के लिए भी है और यू० पी० के लिए भी बुरा है और वह वहां भी बन्द होना चाहिये। लेकिन अगर अच्छी चीज है तो उस में पंजाब को भी हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि वहां भी गुड़ पैदा होता है । मुझे मालूम है कि इससे काश्तकार को जो भाव मिलता है उसमें फर्क पड़ता है । लेकिन मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ है कि जो रिपोर्ट भेजी गई है कमिशन की तरफ से उसमें कुछ गलत बातें कही गई हैं । उसके अन्दर कहा गया कि रोहतक की आबादी ५५,००० है जबकि आज रोहतक की आबादी एक लाख के ऊपर है । इसके अलावा वह कहते हैं कि वहां पर नौ टेलीफोन लाइंस

श्री अ० प्र० जैन : इससे इस मिनिस्ट्री का ताल्लुक नहीं है ।

चौ० रणबीर सिंह : मैं इसको जानता हूं, लेकिन भावों से तो है । गन्ने की जो कीमत मुकर्रर होनी है वह यहां से सलाह मश्विरा करके ही होनी है । उसका सीधा सम्बन्ध गुड़ की कीमत से है और उसके भाव से है । मैं मानता हूं कि फार्वर्ड ट्रेडिंग जो है वह कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अन्दर आती है । लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी इमदाद ली जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि जो इर्रिगेशन प्रोजैक्ट्स हैं उनके लिए बगैर सूद के रुपया दिया जाये । किसी इर्रिगेशन प्रोजैक्ट को पूरा होने में १५ बरस लगते हैं और किसी प्राजैक्ट के कामयाब होने में उसके पानी का पूरा इस्तेमाल होने में और पंद्रह बरस लगते हैं । गुड़ के बारे में जो सहूलियतें आपने यू० पी० को दी हैं, वे पंजाब और रोहतक को भी दें ।

खंडसारी के सिलसिले में मैं एक अर्ज करना चाहता हूं । बड़े बड़े सलफ्यूटेशन प्लांट्स वाले जो लोग हैं उन के साथ मुझे ज्यादा हमदर्दी नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी कोआप्रेटिव्स पंजाब में बनेंगी या देश में बनेंगी या जितनी भी कोआप्रेटिव सोसाइटीज ने खंडसारी के कारखाने लगाये हैं, उनके ऊपर यह टैक्स जो आपने लगाया है नहीं लगना चाहिये और उसकी वजह यह है कि इससे काश्तकार को उसके गन्ने की ज्यादा कीमत मिल सकती है ।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड और एग्रिकलचर, मिनिस्ट्री की जो डिमांड्स सदन के सामने रखी गई हैं, मैं उन का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

अभी तक जितने भी भाषण हुए हैं और जितने भी वक्ता बोले हैं उन सभी ने कंज्यूमर्स का, शहर वालों का प्वाइंट आफ व्यू ही आपके सामने रखा है । सभी ने यह कहा है कि गल्ले के दाम कम हों । हमारे अशोक मेहता मेरे जिले के बगल वाले इलाके से चुन कर आये और *किसानों के वोटों से चुन कर आये हैं* और कांग्रेस की मदद से चुन कर आये हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि कीमत कम होनी चाहिये । सभी यह चाहते हैं कि किसान जितना कम पाये उतना ही अच्छा है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसान के ऊपर कितना बोझा है । भिन्न भिन्न चीजें जो किसान पैदा करता है जैसे चना, चावल, गेहूं, इत्यादि उस सब की कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालने का हमारी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है । अगर ऐसा किया गया होता तो हम देख सकते थे कि किसान का फायदा किया जा रहा है या नुकसान किया जा रहा है । सब से बड़ी बात तो यह है कि जितने व्याख्यान मैं ने सुने उन में कहीं पर यह नहीं सुना कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय । उत्पादन बढ़ाने की सहूलियत तो देनी चाहिये । मैं बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ३५० मिलियन एकड़ जमीन खेती के लिये है और ३५० मिलियन एकड़ में से सिर्फ ६८ मिलियन टन गल्ला होता है । एक एकड़ का हिसाब लगाया जाय तो यह करीब पौने पांच मन फी एकड़ पड़ता है । इस पौने पांच मन को कैसे बढ़ाया जा सकता है ? मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि पौने पांच मन का दून तो हो सकता है बशर्ते उसके लिये सहूलियतें और साधन हों । मैं अभी हाल में पैरिस गया था । हमारे साथ प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र जी भी थे । उन को भी पता होगा कि किसी खेत में तो अच्छी फसल है और किसी में खराब, एक ही जगह पर । इस के माने यह है कि जिस खेत में फसल अच्छी है उस को ज्यादा सहूलियत मिली और जिस में कम है उस को कम सहूलियत मिली । मैं बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हमारा खेती का तरीका है उस में हम को मदद की जरूरत है लेकिन हम किसानों को उतनी मदद नहीं मिलती । अभी हमारी सरकार के पहले टाटा ने कारखाना खोला । उस वक्त सेंट्रल असेम्बली में पंडित मोती लाल नेहरू हमारे नेता थे उन्होंने उसे पूंजी दिलाने के लिये कहा था हालांकि *उस से घाटा होता था । लेकिन हमारे* किसान जब कर्ज लेते हैं तो उन को ६ परसेन्ट और १० परसेन्ट ब्याज पड़ता है । जब हमारी अन्य कोई आमदनी नहीं है, जब हमारी खेती के साथ अन्न की खेती का पड़ता नहीं पड़ता । हमारे खेत बिना सींचे रह जाते हैं । तो अगर अन्न की हालत को सुधारना है तो अन्न की पैदावार के लिये मदद कीजिये । अन्न की पैदावार होती है पानी से, खाद से, अच्छे बीज से । ऐसी चीजें की जायें तो उस से अन्न की पैदावार ज्यादा होती है लेकिन अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिये हमारे कितने खेत सींचे गये ? हमारे जिले में, हमारी तहसील में, हमारे गांव में कितनी खाद सरकार से मिली ? मैं फर्टिलाइजर का हामी नहीं हूं लेकिन अगर थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर भी हो जाय, हालांकि गांव के लिये जो जरूरी चीज है वह है हरी खाद, थोड़ा सा फर्टिलाइजर हम लोगों को दिया जाय तो उस से गांव के अन्न की पैदावार बढ़ सकती है । गांव का कूड़ा करकट जो है उसे ठीक से रखें तो उस की खाद बन सकती है । मेरा अपना अन्दाजा है कि अगर खेत को ठीक से जोता जाय—यहां पर जो खेतिहर होगा वह समझेगा अगर धान के खेत को अच्छे ढंग से माघ के महीने में जोता जाय और चैत के महीने में जोता जाय और आसाढ़ के महीने में धान बोया जाय तो पैदावार पूरी होगी । खाद की

कोई ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि खेत को ठीक से जोतने से उस में नाइट्रोजन स्वयं पैदा हो सकती है । उस के लिये गोबर की खाद न भी मिले, तो कार्तिक, अगहन, पूस और माघ में थोड़ी सी खाद डालने के बाद खेत को ठीक से जोतें तो नाइट्रोजन पैदा हो जाती है और उस से पैदावार बढ़ सकती है ।

हिन्दुस्तान में अभी तक जो खेती की हालत है उस में पूरे ५ करोड़, ५५ लाख, ४४ हजार एकड़ खेत की आबपाशी होती है । उस में हम को पैदावार बढ़ानी है । मेरे साथी श्री भोला शुक्ल ने बताया था कि एक एकड़ में उन्होंने ६० मन धान पैदा किया । तो यदि हर अपने खेत को जो कि हमारी सिंचाई के अन्दर है, ठीक करें, उस में अच्छी तरह मेहनत करें, तो पैदावार बढ़ सकती है । बिहार में जो हमारे पुराने जमींदार थे वह गांवों में तालाबों पर और जो दूसरे सिंचाई के साधन हुआ करते थे, उन पर कुछ पैसा खर्च करते थे । लेकिन जब से जमींदारी हमारे हाथों में आई, तब से हम ने उन को उसी तरह से छोड़ दिया है और बहुत से गांवों में तो मैं ने देखा कि वे यों ही पड़े हुए है । इस साल हमारे उत्तर बिहार में सरकार ने ३०० ट्यूबवेल लगाये, लेकिन ट्यूबवेल तो लगाये पर उनके लिये चैनल ठीक नहीं की । नतीजा यह है कि पानी को जितनी दूर तक जाना चाहिये, जितनी ऐरिया ट्यूबवेल को कवर करना चाहिये उस को कनाल्ड न करने से नुकसान हो रहा है । अगर हम सिंचाई की तरफ ध्यान दें तो पैदावार बढ़ सकती है लेकिन चूंकि हम सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं इस लिये सारी दिक्कत पैदा हो रही है ।

दूसरी बात यह है कि हमें दुफसला खेती बढ़ानी चाहिये । देश में जितने खेत हैं उन में से सिर्फ १५ फीसदी खेत दुफसला हैं । अगर हम उस को तीन फसला कर दें तो पैदावार और भी बढ़ सकती है । यहां पर एक बात है । हमारे भाई कहते हैं, हमारे सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट भाई, कि साहब, हम को अच्छा अन्न नहीं मिलता । बात असल यह है कि मोटा अन्न खाने का तरीका हम ने छोड़ दिया । हमारे यहां एक चीज होती है जिस को मड़ुआ कहते हैं, कोदां कहते हैं वह बहुत पैदा होता है । लेकिन हम लोगों का स्टैन्डर्ड इतना बढ़ गया है कि कोई उस को खाना नहीं चाहता । इसी लिये हमारी अन्न की पैदावार कम हो जाती है । अगर हम दुफसला खेती करें तो उस से अन्न ज्यादा होगा । रबी की फसल हमारे यहां कम होती है, लेकिन अगहन में ज्यादा पैदावार होती है । अगर हम दुफसला पैदावार करे तो पैदावार काफी बढ़ जायेगी ।

हमारे पंडित ठाकुर दास जी ने कहा कि कृषि मंत्रालय को तोड़ देना चाहिये । उन्हें पता नहीं—हमारा भी कृषि मंत्रालय से थोड़ा सा सम्बन्ध है—मैं बिहार में भी गया और देखा कि कृषि मंत्रालय हमारी बहुत मदद करता है और उस के अन्दर बड़े बड़े जानकार आदमी हैं । उन को पता है कि जो आदमी नये ढंग से खेती करता है उस की पैदावार बढ़ जाती है । लेकिन हमारे पंडित ठाकुर दास जी को पता नहीं । उन्होंने कहा कि इस लिये कृषि मंत्रालय से सब्सिडी नहीं मिलती है कि खेती से सम्बन्ध रखने वाले आदमी उस के अन्दर नहीं हैं । लेकिन मैं उन को बतलाता हूं कि उस में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं पैदावार बढ़ाने के । मेरा अपना खयाल है कि इस विभाग से उन लोगों का सम्बन्ध रखना चाहिये और उन को बढ़ावा मिलना चाहिये ।

हमारी सरकार हर साल जितना गल्ला इम्पोर्ट करती है अगर इम्पोर्ट के बराबर कीमत खेतिहर को सबसिडी के रूप में दे दें तो खेती की उपज काफी बढ़ सकती है । सन् १९५७ में सरकार ने १६२ २ करोड़ रुपये का गल्ला मंगाया और सन् १९५८ में उसने १२०.५ करोड़ रु० का गल्ला मंगाया ।

[श्री विभूति मिश्र]

यानी हमारी सरकार ने दो वर्षों के अन्दर २८७.७ करोड़ रु० का गल्ला मंगाया। यह सरकार जितने रुपये का गल्ला बाहर से मंगा कर हमको खिलाती है अगर उतने रुपये को वह खेतिहरों को बगैर सूद के दे दे तो हम पैदावार काफी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार का हाल यह है कि जब अनाज घट जाता है तब तो बाहर से मंगा कर खिलाती है, लेकिन जब हालत अच्छी हो जाती है तो ध्यान नही देती। मैं जैन साहब से कहूंगा कि इस साल आप इतने रुपये हम को दे दें तो हम अगले साल के लिये निश्चिन्त हो जायें। खेती की बात तो यह है कि अगर ठीक से खेत की जोताई की जाय तो पानी की कमी होने पर भी अच्छी पैदावार हो सकती है। हमारे झूलन सिन्हा साहब जानते है कि अगर खेत को ठीक से जोता जाये और उसमें गोबर की खाद दी जाये तो आखिर महीने मे अगर पानी कम भी हो तो भी धान फूट जायेगा। यह बात हमारे दूसरे भाई नहीं जानते हैं। आखीर सरकार क्या करे? वह कितने भाखरा नंगल बना सकती है? यदि अच्छे साधन और सहूलियतें हमारे पास आज हों और उनको ठीक से काम में लाया जाय तो हमारी पैदावार बहुत बढ़ सकती है।

श्री यादव (बाराबंकी) : भाषण से ही खेत सिंच जाते हैं?

श्री विभूति मिश्र : जी नहीं वह मेरे पहले आपने अपने भाषण से ही सींच दिया।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जिस समय पार्टिशन हुआ उस समय १७ लाख बेल जूट पैदा हुआ था। आज सन् १९५७-५८ में ७८ लाख बेल जूट पैदा हुआ। उस वक्त जूट की जो कीमत हमको मिलती थी, आज हमारी अपनी गवर्नमेंट होते हुए उतनी कीमत नहीं मिलती है। मुझे इस के लिये जैन साहब से कहना है कि वह तो हमारे वकील हैं। यह मामला चला गया है कामर्स मिनिस्ट्री के हाथ में। ४०, ५० फैमिली कलकत्ते में रहती हैं वह हम से जूट खरीदती हैं। इस महीने में वह पैदा होता है, लेकिन भादों और आश्विन में किसानों को पैसे की ज्यादा जरूरत रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप गांवों में कभी नहीं गये होंगे। मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप बिहार में भादों के महीने के आखीर में आकर देखिये कि किसानों को पैसों की कितनी जरूरत रहती है। हमारे यहां १२ रु० या १३ रु० मन जूट मिलता है लेकिन कलकत्ते में, हमारे जैन साहब कहते थे, २३ रु० मन बिकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बिना बुलाये मैं वहा नही आऊंगा। आप बुलायें तब आऊंगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं बुलाता हूं, आप आइये, क्योंकि जूट जो है उसको बोते वक्त जो कीमत लगती है वह हमको उसके दाम मे नही मिलती है।

दूसरी बात यह है कि गन्ने के दाम भी बढ़ने चाहियें। क्योंकि ४५ करोड़ रु० तो हमारी सेंट्रल सरकार एक्साइज के रूप में ले लेती है गन्ने के ऊपर, फिर १० करोड़ रु० स्टेट की सरकार लेती है। इस तरह से अगर देखा जाय तो एक मन चीनी के ऊपर १४ रु० १० आ० किसान को मिलता है और १३ रु० ६ आ० सरकार लेती है। फिर जैन साहब कहते हैं कि तुम गन्ना क्यों बढ़ाते हो। हम गन्ना इस लिये बढाते हैं कि उसमें हम को पैसा ज्यादा मिलता है। वजह यह है कि आप गल्ले का दाम ठीक नहीं रखते। आप गल्ले का दाम कम रखते हैं इसलिये हम लोग गन्ना ज्यादा पैदा करते हैं। अगर हम को गल्ले का दाम ठीक से दिया जाये तो हम उसे भी पैदा कर सकते हैं।

जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह दाम जरूर बढ़ सकता है लेकिन हमारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भाइयों ने हड़ताल कराई उसकी वजह से हमारे गन्ने का दाम ठीक से नहीं बढ़ पाया। दुनिया में सब जगहों

पर हड़ताल चल सकती है, लेकिन गन्ने के बारे में हड़ताल नहीं चल सकती।

एक माननीय सदस्य : चलेगी।

श्री विभूति मिश्र : नहीं चलेगी, यह बात गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन अभी से यहां पर तो इस का फैसला न किया जाय।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लोग गन्ना नहीं पाते। यह रस उसके मुंह में नहीं जाता जो कि गन्ना उगाते हैं। दूसरे दूसरे आदमी सब रस चूस जाते हैं।

जो गन्ने की खेती करता है उसे हड़ताल से दुःख होता है। ये हमारे भाई तो खाली राजनीति में किसान को बढ़ाना चाहते हैं, वे किसान की भलाई नहीं चाहते। जो गन्ने की खेती करेगा वह कभी हड़ताल पसन्द नहीं करेगा। मैं इन से ही पूछता हूं कि यह भगवान का नाम लेकर बतायें कि क्या गन्ने की खेती करने वाला हड़ताल करना पसन्द करता है। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इन भाइयों का ख्याल न करें क्योंकि ये किसान का भला नहीं चाहते। पर किसान के गन्ने का दाम कम से कम दो आने बढ़ा दें।

श्री ब्रज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यहां इस प्रकार के शब्द कहने की अनुमति है कि "भगवान् का नाम लेकर बतायें।"

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें झगड़े की क्या बात है। जो आदमी भगवान् में यकीन करता है उसके मुंह से स्वाभाविक तौर पर यह निकल जाता है कि इनसे भगवान् का नाम लेकर पूछ लिया जाये। लेकिन जो भगवान् में यकीन नहीं रखते उनको इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है।

माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री विभूति मिश्र : मैं खत्म ही करता हूं।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत बढ़ाना जैन साहब के हाथ में है। वह इसकी कीमत दो आने मन जरूर बढ़ा दें। आज किसान शहर वालों के लिए, दुकानदारों के लिए और इंडस्ट्री वालों के लिए पैदा करता है। अखबार नवीसों के लिए भी किसान गल्ला पैदा करता है। उनको कम से कम एक कालम रोज लिखना चाहिए कि किस तरह किसान उपज बढ़ा सकता है और किस तरह उसको उचित दाम मिल सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आज स्वतन्त्र देश में चाहे वह राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे प्रधान मन्त्री का लड़का हो और चाहे गरीब किसान का लड़का हो सबके लिए शिक्षा की समान सुविधायें होनी चाहियें। आज किसानों के लड़कों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रबन्ध किया जाये। और इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि किसान को अपनी उपज की उचित कीमत मिले।

Shri Rami Reddy (Cuddapah): Mr. Deputy-Speaker, in the limited time at my disposal, I wish to touch only on one point and that is a point which Shri Bibhuti Mishra, the previous speaker appears to have touched. I could not follow the Hindi version of his speech. But I believe I will be in complete agreement with him or he must have been in complete agreement with the views that I am going to express.

In regard to the prices of agricultural commodities, my point is this. When I visited the India—1958 Exhibition, I visited the pavillion of the Food and Agriculture Ministry. At the entrance, in very bold letters, it was inscribed that the farmer is the most important person in this country. True, it is, because, agricultural

[Shri Rami Reddy]

population constitutes about 250 millions out of the total population of 360 millions. It is the agricultural population that contributes about 50 per cent. of our national wealth. He supplies food to the entire community. But, my complaint is, except this inscription in very bold letters, the Agriculture Ministry is not paying proper attention that is due to the farmer. It is in this context that I wish to point out that the control price fixed for paddy and rice is not commensurate with the cost of cultivation. That is to say, the cost of cultivation has gone up. The cost of fertiliser has gone up. The cost of labour has also terribly gone up. These factors do not seem to have been taken into consideration when fixing the price of paddy. Only the interest of the consumer seems to be the concern of the Ministry. Although the urban population forms a very small number of the entire population, they are well-organised compared to the population in the rural areas. They have got trade union movements. Whenever prices go up they make a hue and cry throughout the country and even Government is afraid and therefore they go out of their way. The rural population is illiterate and ignorant and they are not well-organised. They have no Press behind them. So, whenever prices fall there is no one to look after their interest. So, my submission is that the Ministry should take care and they should devise some methods to fix the price of paddy and other agricultural commodities commensurate with the cost of cultivation.

The price appears to have been fixed this year on the basis of the average of the prices prevailing during the previous three years. This is not the correct way of fixing the prices of agricultural commodities. We have to take into account the commodities absolutely necessary only for cultivation. I do not refer to commodities which he purchases for his livelihood or any other necessities. I am referring only to the commodities which are absolutely necessary for cultivation purposes. Even when these things are taken into consideration, I submit, the price fixed for paddy is not commensurate. If fertilisers, agricultural implements etc. were supplied to the farmer at subsidised rates, I can understand that.

In this connection, I want to point out only one thing in regard to the finer variety of rice in Andhra Pradesh. It is called Bangarutheegalu rice. The price fixed for it was only Rs. 21:50 per maund, whereas, for the same quality of rice in Uttar Pradesh, Grade I, the price has been fixed at Rs. 29 per maund.

Shri A. P. Jain: It is Basmati rice, not Grade I.

Shri Rami Reddy: It is of equal quality. It is not superior to Bangarutheegalu variety of rice of Andhra Pradesh. I do not know why a lower price has been fixed for the particular variety of rice in Andhra. I want to say this with regard to the price aspect.

Regarding iron and steel required for agricultural purposes, supplies have not been made on the basis of the requirements of agriculture. Andhra Pradesh has made repeated requests for provision of iron and steel for agricultural purposes. Last year I asked a Question on this point. For the year 1958-59, out of a total requirement of about 10,000 tons, only about 4,000 tons have been allotted to Andhra Pradesh. I do not know whether the quota is fixed on population basis. In the case of non-agricultural purposes it has been fixed on population basis. But this does not appear to have been fixed on population basis. At any rate, it does not appear to have been fixed on the overall requirements for agricultural purposes in these States. For, Andhra Pradesh is one of the surplus States in this country, and it is purely an agricultural State. Even if only the agricultural population of the State is

taken into consideration, it deserves more allotment. But even the required quantity of iron and steel has not been supplied to Andhra Pradesh for agricultural purposes.

In this connection, though irrigation is not directly the concern of this Ministry, I wish to point out one thing. The iron and steel for the completion of several medium and minor irrigation projects in Andhra Pradesh has not been supplied as per requirements. Several of these minor irrigation projects, about sixteen or seventeen of them, have been held up, as the required quantity of iron and steel has not been supplied. In some instances, some of the projects have been held up purely for want of iron and steel for fixing up the shutters or the gates. The total area involved under these seventeen or eighteen schemes is about 6·5 lakhs acres, and a food production of about 3·5 lakhs tons is anticipated under these projects But the projects have been held up for want of iron and steel for the shutters or gates. Therefore, I request the Ministry to prevail upon the Ministry of Steel, Mines and Fuel to allot the required steel for the completion of these projects

My hon. friend Shri Thirumala Rao was quoting figures of production from the bulletin on food statistics for the various States. On going through these things, I find that Andhra Pradesh stands as the best producing State in the country, because in 1952-54 it produced 30 lakhs tons of rice, and in 1957-58 it produced nearly 35 lakhs tons. I am mentioning this only to point out that fertilisers are in the greatest demand in this State. The requirement of the State in regard to fertilisers is about 2 lakhs of tons per annum. When the State requested the Central Government to allot the required quantity of fertilisers, it was said that the latter were not in a position to supply more than 50 per cent. of the required quantity But even that 50 per cent. has not been supplied to Andhra Pradesh.

Shri A. P. Jain: No, it has been supplied

Shri Rami Reddy: It has not reached the State in time so that the fertiliser could be used for the crop in season.

Andhra Pradesh is one of the States where fertilisers are in very great demand, nearly 70 per cent. of the production of the Sindri Fertiliser Factory would be consumed in that very State, if only the Central Government are prepared to supply the full requirements of that State. On reading the Explanatory Memorandum on the Demands for Grants, I find that about 18 72 lakhs tons of fertilisers are necessary for the whole country; as against that, we are able to produce only about 4·02 lakhs tons That means we are short by about 14 lakhs tons In view of this, I submit that the establishment of a fertiliser factory in Andhra Pradesh is an absolute necessity The Government of the State have been making a request for this from time to time, and I request this Ministry to prevail upon the Commerce and Industry Ministry to establish one fertiliser factory in our State

Mr. Deputy-Speaker: Now, Shri D A Katti from the Republican Party The hon Member is absent. Now, Shri Yadav

श्री यादव : उपाध्यक्ष महोदय किसी भी समय सरकार का और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि देशवासियो को आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओ को उपलब्ध करे । उन वस्तुओ मे सर्व-प्रथम भोजन, कपड़ा और मकान होते है । इन में से यदि हम भोजन की स्थिति की दिशा में देखते है, तो पाते है कि इन बारह सालो में देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है । अभी हमारे बुजुर्ग साथी पडित ठाकुर दास भार्गव ने पिछले वर्ष की हालत बयान की । आज दस करोड ऐसे लोग होगे कि जिनके यहा एक ही बार

[श्री यादव]

चूल्हा जलता है। श्री भार्गव ने इसमें शक जाहिर किया कि भूखों मरने वाले लोग न हों, लेकिन मैं इस विषय में बता सकता हूं—तफ़सील के साथ नहीं, क्योंकि समय कम है। मैं केवल एक ही मिसाल दूंगा कि लोग धनाभाव के कारण और अन्न की कमी के कारण भूखों मर रहे हैं। इसी सदन में मैंने एक बार बरेली की एक घटना के बारे में काम-रोको प्रस्ताव रखा था। एक आदमी जेब में पैसा न होने के कारण और कोई काम न मिलने के कारण अन्न न खरीद सका और मजबूर होकर उसने एक लोटे की चोरी की। जब पुलिस दरोगा ने उसकी तलाशी ली और उसको उस आदमी की असलियत का पता चला, तो उसको रहम आया और उसने पांच रुपए उस आदमी को दिया। वह शख्स आटा लाया और आटे में जहर मिला कर उसने रोटी बनाई और फिर पूरे परिवार को खिला दी और वह पूरे का पूरा परिवार इस दुनिया से चल बसा। इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं। हमारा खाद्य मन्त्रालय इस बारे में क्या कर रहा है?

Shri A. P. Jain: The story was denied by the District Magistrate of Bareilly.

Mr. Deputy-Speaker: This has been denied by the District Magistrate of Bareilly.

श्री यादव : इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि ४ मार्च, १९४९ को प्रधान मंत्री ने एलान किया था कि "१९५१ तक खाद्यान्नों के मामले में देश आत्म-निर्भर हो जायेगा।" फिर २२ अगस्त को उन्होंने रेडियो पर एलान किया कि मैं इसे एक दिन के लिए भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन फिर मालूम हुआ कि इस को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया।

(Interruption.)

माननीय सदस्य को भी बोलने का मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को यह कैसे मालूम है कि उन को मौका जरूर मिलेगा?

श्री यादव : हम को तो आप की दया-दृष्टि पर ज्यादा भरोसा है। १७-११-५० को उस समय के खाद्य मंत्री, श्री मुंशी, ने कहा कि "भारत छोड़ो आन्दोलन" के बाद मुल्क ने सब से बड़ा फ़ैसला यह किया है कि ३१ मार्च, १९५२ तक खाद्यान्नों के मामले में देश आत्म-निर्भर हो जाये। "भारत छोड़ो" का नारा गांधी जी ने दिया था और अन्न-संकट के दूर करने का नारा के० एम० मुंशी महोदय ने दिया। लेकिन होता क्या है? वह तिथि बदल गई और प्रधान मंत्री ने १८-११-५० को फिर कहा कि मैं ने कोई वक्तव्य दिए हैं कि १९५२ तक खाद्यान्नों का आयात बन्द हो जायेगा, मुझे अफ़सोस है कि मेरा वादा ग़लत साबित हुआ, लेकिन हम हर सम्भव कोशिश करेंगे कि योजना की समाप्ति तक खाद्यान्नों का आयात बन्द हो जाये। एक योजना का अन्त हुआ। दूसरी योजना चल रही है और उस के भी तीन वर्ष बीतना चाहते हैं और तीसरी योजना की चर्चा चल रही है। पिछले वर्ष जब इसी सदन में खाद्यान्नों के सम्बन्ध में बहस हुई थी, तो प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि अन्न के मामले में देश में इतना जबर्दस्त संकट है कि मुझे ज्ञात नहीं था, मैं समझ नहीं पाया था। यह सरकार बारह साल से खाद्य स्थिति में सुधार नहीं कर पाई है। इस विषय में पंच-वर्षीय योजनाओं की बात की जाती है। पंच-वर्षीय योजनाओं और राजनीति का भी सर्व-प्रथम उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश में रहने वाले सभी वासियों को पेट-भर भोजन तो दिया जाये। लेकिन पेट-भर भोजन की कौन कहे, आधे भोजन के लिए, किसी तरह जी कर रहें, रगड़ कर रहें, उतना भोजन देने के लिए ९५ करोड़ का भोजन बाहर से मंगाया जाता है, जब कि भारत एक कृषि-प्रधान देश

है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ८२ देशों में से केवल मिश्र को छोड़ कर भारत खाद्यान्नों के मामले में सब से पीछे है। लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर क्यों नहीं गया? उस का केवल एक कारण है। आज भूखों मरने वाले कौन है? श्रीमान्, मैं कह सकता हू कि न तो इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं और न मंत्रीगण हैं। मरते कौन लोग हैं? मरते वे हैं जो इक्के वाले होते हैं, जो रिक्शा वाले होते हैं, गावों में रहने वाले जो हरिजन लोग होते हैं, जो पिछड़ी जातियो के लोग होते हैं। सवर्ण हिन्दुओं में वही लोग मरते हैं, जो पिछड़े हुए होते है, जो पाजामा, धोती, कुरता पहनते है, जो गरीब होते हैं और गरीबी की हालत में अपनी जिन्दगी गुजारते है। प्रधान मन्त्री को उनकी क्या चिन्ता है? मुझे एक कहावत याद आती है। विष्णु भगवान को लक्ष्मी से फुरसत नही, शहनशाह जहागीर को नूरजहा से फुरसत नहीं और आज शहनशाह जहागीर नेहरू को पंचशील से फुरसत नही है। दुनिया को शान्ति का सन्देश वह देते फिरते है, उनके आपसी झगडो का फैसला करवाते फिरते है। घर में नही हैं दाने, मा चली भुनवाने वही बात आज हो रही है। लोग भूखों मर रहे है, और उनको कोई चिन्ता ही नही है।

17 hrs.

देश भूखा है और वह गुलदस्तों से खेलने जाते हैं और वह भी पब्लिक स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों से, नैनीताल जैसे पब्लिक स्कूलों के बच्चों से। क्या प्रधान मंत्री कभी म्यूनिसिपैलिटियों और नोटिफाइड एरिया द्वारा जो स्कूल चलाये जाते हैं और जिन स्कूलों में गरीब लोग, हरिजनों के बच्चे, साधारण लोग, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बच्चे, जिनीने बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर तशरीफ़ ले गये हैं, क्या उनका उनकी तरफ भी कभी ध्यान गया है? उनको पेट भर भोजन खाने को नहीं मिलता है। वहा वह जाना पसन्द नहीं करते है। खाद्य समस्या तब तक हल नही हो सकती है जब तक हम उन लोगों को रोटी नही दे पायेंगे जो कि भूख की ज्वाला में झुलस रहे हैं। इस सब का परिणाम आज क्या हो रहा है? नेहरू नौकरशाही का, नेहरू मन्त्रिमडल का ध्यान उस तरफ है ही नही। उनको लोग चाचा नेहरू कहते हैं। लेकिन उनको उन्हीं भतीजो का पता है जो भतीजे गुलदस्तो से खेलते है, जो बुशर्ट पहनते है, जो टाई और पैंट पहनते है, और उन बच्चो का पता तक नही जो भूखो मरते हैं, जिन के तन पर कपड़ा नही है जिन के पढने लिखने का कोई इंतिजाम तक नही है।

श्री वी० पं० शर्मा (गुरदासपुर) वह सब जानते है।

श्री यादव: तब तो और भी बुरी बात है। जानते हुए भी कुछ न करना, इससे बुरी बात क्या हो सकती है।

सरकार कहती है कि खाद्य समस्या को राजनीतिक प्रश्न न बनाया जाए। मैं पूछना चाहता हू कि आखिर राजनीति है किस के लिए अगर वह खाद्य की समस्या को हल नहीं कर सकती है। सरकार चाहती है कि विरोधी दल वाले उसके साथ सहयोग करें। सरकार सर्वदलीय समिति बनाती है। लेकिन जितना भी सलाह मशविरा वहा दिया जाता है, सब पर कोई अमल नही होता है। ऐसी सर्वदलीय समिति से क्या लाभ हो सकता है? इसीं वास्ते तो सोशलिस्ट पार्टी ने उसमें भाग लेना छोड दिया है। इस तरह से कोई कल्याण होने नही जा रहा है।

अगर आप खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बतलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। अन्न की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, इसके बारे में माननीय सदस्य ने अपने अपने सुझाव दिये है, किसी ने कहा है, पानी की सुविधा मिलनी चाहिये, बीज मिलना चाहिये इत्यादि। लेकिन सब से बुनियादी

[श्री यादव]

बात जो है वह यह है कि जो खेती करता है, वह जमीन का ही मालिक नहीं है। आज जमीन का मालिक वह है जिस का हल कागजों पर चलता है, लेखापाल की कलम द्वारा लिखे गये कागजों पर चलता है लेकिन जिस का हल जमीन पर चलता है उसके पास जमीन ही नहीं है, वह जमीन का मालिक ही नही है। कहीं-कही पर भूमि सुधार लागू किये गये हैं। लेकिन जब तक इस बुनियादी सिद्धान्त को नहीं माना जाता है कि सायल टू दी टिल्लर, खेत उसका जो खेती करता है, तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अधिक अन्न पैदा हो तो जमीन का पुनर्वितरण करना होगा और इसके लिए कानून बनाना होगा। १४ करोड़ एकड़ जो भूमि बंजर पड़ी हुई है उसको आपको तुड़वाना होगा और उसमें खेती करने के लिए दस लाख खेतिहरों की पलटन तैयार करनी होगी। आज पांच करोड़ एकड़ के लिए पानी उपलब्ध है लेकिन बाकी की जो कोई २२ करोड़ एकड़ भूमि है, जिस पर कि खेती होती है, उसके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए आपको पानी की व्यवस्था करनी होगी। कुएं इत्यादि आपको खुदवाने होंगे। लेकिन ये सब काम न करके आप तो उद्घाटन भाषण ही करते रहते हैं, इससे खाद्य समस्या हल होने वाली नही है। कई खाद्य मंत्री आ चुके हैं। के० एम० मुंशी साहब आए, जयरामदास दौलत राम साहब आए। उन्होंने कहा कि गमलों में खेती हो, छतों पर खेती हो और कलैक्टरों के बंगलोस के कम्पाउंड में खेती हो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो खेती करने वाले है, उनके लिए न कोई साधन उपलब्ध किये जा रहे हैं और न ही उनको जमीन दी जा रही है और केवल भाषणों से ही सारा काम चलाया जा रहा है।

मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं। एक बात सुनाने की योजना चली है। केन्द्रीय सरकार का कृषि मंत्रालय उस सिलसिले में राज्यों को पैसा देता है। उत्तर प्रदेश को भी पैसा मिला और उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत बाराबंकी जिले को भी मिला। ४०,००० की एक इंस्टालमेंट आई। लेकिन वह पैसा उस को कब मिला, वह तब मिला जब फाइनेंशल ईयर खत्म होने को था और अधिकांश पैसा बरागांव, मसौली, और भयारह, इन तीन गांवों में तीन ही आदमियों के बीच बांट दिया गया। इस के बाद १५,००० रुपया और उसी समय गया और यह रुपया भी जिन को भूमिधर कहा जाता है और जिन के पास सारी जायदाद है, जो पुराने जमींदार हैं, उन के बीच बांट दिया गया। गरीबों को कोई एक पैसा भी नही देता है। जब ऐसी बात है तो किस तरह से अन्न संकट दूर हो सकता है। अगर सरकार चाहती है कि अन्न संकट दूर हो, तो उस को इन गरीब किसानो की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि जिस खेती से कोई मुनाफा नहीं होता है, उस पर लगान न लगे। लेकिन इस ओर ध्यान न दे कर और खेतिहरों के पलटन तैयार न कर के अफसरो की पलटनें तैयार की जाती हैं। ये लोग तजवीजें भेजते है, उद्घाटन करते है और इन की तसवीरें भी अखबारों में छप जाती है। हमारे यहां भी एक फूड कंसलटेटिव कमेटी बनी हुई है जहां पर हम भी जाते है। वहां पर काजू, चाय, इत्यादि खाने को मिल जाता है और खा पी कर हम लोग तशरीफ ले आते हैं, होता कुछ नही है। इस वास्ते मैंने अब वहां जाना भी छोड़ दिया है।

दामो के बारे में मेरे माननीय मित्रों ने सोशलिस्टों पर लांछन लगाया है और कहा है कि किसानों का इस पार्टी ने बहुत अहित किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

आज जो लोग खाद्यान्नों के मूल्य को ले कर उपभोक्ता और किसान में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, वे बहुत ना-समझ हैं। यह किसान और उपभोक्ता का झगड़ा नहीं है। प्रश्न यह है कि जब फसल कटती है, अब जब गेहूं कट रहा है, तब तो वह बहुत सस्ता बिकता है, १४ रुपये सन बिकता है। लेकिन जब यह सारा गेहूं किसान के घर से निकल जायेगा क्योंकि वह ज्यादा दिन तक इस को रख नहीं सकता है, उस को लगान अदा करना होती है, उस को शादी में खर्च करना होता है तथा दूसरी अपनी जरूरत पूरी करनी होती है और ८०-८५ परसेंट घरों से बाहर चला जायेगा और छोटे व्यापारियों के हाथ से भी निकल जायेगा और करोड़-पतियों के हाथ में, बिड़ला जैसे पूंजीपतियों के हाथ में चला जायेगा तो इस की कीमत १४ रुपये के बजाय २५-२८ रुपये मन हो जायेगी। सोशलिस्टों ने तहरीक शुरू की थी और कहा था खाद्यान्नों के मूल्य गिरे, उस से किसानों को कहां नुकसान था। मेरी पार्टी की यही मांग है कि सरकार कोई निश्चित और सुदृढ़ दाम नीति अपनाये और उस का आधार यह हो कि दो फसलों के बीच में किसी भी खाद्यान्न का मूल्य मेर पीछे एक आना से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये। इसी तरह से हम यह भी चाहते हैं कि कारखानों में बनी किसी भी जीवनोपयोगी वस्तु का बिक्री दाम लागत खर्च से ड्योढ़े से अधिक किसी हालत में न हो। तीसरे, किसान को उस के अनाज और कच्चे माल का ऐसा दाम मिले जो लागत खर्च और जीवन निर्वाह को सुभीते से कर सके, उस से किसी सूरत में भी कम न हो ताकि खेतिहर और औद्योगिक चीजों के उत्पादन में संतुलन और समता कायम हो सके। इसलिये यदि सरकार चाहती है कि निश्चित दाम नीति अपनाये तब तो वह जो सरकार आज व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है उस से कुछ फायदा हो सकता है और अगर इस नीति को तय नहीं करती है तो जो व्यापार आज सरकार लेने जा रही है, उस में भी इस को कामयाबी नहीं मिल सकती है। आज दाम की लूट के सिलसिले में यह हो रहा है कि एक तरफ करोड़पति सरदार बिड़ला जैसे हैं, दूसरी तरफ सरकारी सेठ जिन में सब से बड़े नेहरू साहब और जैन साहब हैं और तीसरे वे हैं जिन के पास ५०० से १००० एकड़ या उस से ऊपर भूमि है और ये तीनों मिल कर के दामों की लूट कर रहे हैं। अगर आप ने अब जब आप व्यापार अपने हाथ में ले रहे हैं निश्चित दाम नीति नहीं अपनाई तो इस का यह नतीजा होगा कि इन तीनों की जगह केवल सरकार और उस की भ्रष्ट नौकरशाही ले लेगी और उस से कोई कल्याण नहीं होगा।

सहकारी खेती के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस का स्वागत करता हूं। लेकिन आवडी के समाजवाद के प्रस्ताव का जिस तरह से इलैक्शन में नाजायज फायदा उठाया गया था उसी तरह से इस सहकारिता का १९६२ में होने वाले इलैक्शन में इस्तेमाल करने के लिये इस को अगर अपनाया गया है, तो यह बहुत खतरनाक बात है। लेकिन अगर यह सही मानों में सहकारिता का नारा है तो मैं इस का स्वागत करता हूं। मैं इसलिये यह कहता हूं कि जब दूसरी जगहों पर सहकारिता चल सकती है, तो खेती में भी अवश्य चल सकती है।

भ्रष्टाचार का मैं जिक्र कर चुका हूं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल मैं और देना चाहता हूं। आन्ध्र में राजा महेन्द्री जेल है। उस जेल में अमरीका द्वारा ५,००० डिब्बे दूध के भेजे गये। वहां पर खाने को भोजन ही नहीं मिलता, दूध मिलने की बात तो दूर रही। लेकिन दूध अमरीका की तरफ से भेजा गया। लेकिन वहां पर पहुंचते-पहुंचते यानी कैदियों तक पहुंचते-पहुंचते केवल चार डिब्बे दूध के ही रह गये, बाकी डिब्बे कहां चले गये, कोई जानता ही नहीं।

[श्री यादव]

आज कहा जाता है कि उपज में तरक्की हुई है । इस की भी एक मिसाल मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में नौ कृषि पंडितों को इनाम मिला है और जिन नौ कृषि पंडितों को मिला है उन्होंने सिंचाई के साधनों से सिर्फ अपने निजी साधनों का इस्तेमाल किया है, सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं किया है, सरकारी साधनों का इस्तेमाल पूरी तरह से वे नहीं करते हैं । क्योंकि वह नाकाफ़ी हैं । अगर औसत पैदावार और जो कृषि पंडितों की पैदावार है, उस का मुकाबला किया जाय तो दुगुने का फर्क पड़ेगा । और जब औसत पैदावार और कृषि पंडित की पैदावार के बीच में कोई नजदीकी रिश्ता न हो, तो इतना तो समझ ही लेना चाहिये कि आम तौर से जो भारत का कृषि आन्दोलन रहा है वह असफल रहा है और उस से देश की फसल नहीं बढ़ सकती ।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा कि हमारे माननीय अजित प्रसाद जैन से जब कभी गन्ने के बारे में बातचीत होती है तो जिस ढंग से बिच्छू डंक मार देता है, वैसे ही वह जान पड़ते हैं । यह बहुत पुराना फार्मूला रहा है कि जितने आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी और अगर इस आधार को माननीय मंत्री महोदय मान कर गन्ने का दाम निश्चित कर दें तो अच्छा है । पिछली बार जब हड़ताल चल रही थी तो इसी सदन में काम रोको प्रस्ताव रक्खा गया था । माननीय मंत्री महोदय ने फ़रमाया था कि दाम तो कम निश्चित हो चुके हैं इसलिये अब मौका नहीं है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि फिर मौका आ गया है दाम निश्चित होने का । वे केवल यह कह कर कि पड़ता नहीं पड़ता, केवल हां या न में उत्तर दे कर इस सवाल को टाल न जायें । यह अच्छा नहीं होगा । मैं चाहूंगा कि किसी दिन आप बहस करवायें गन्ने के मूल्य पर । चीनी के मूल्य में और गन्ने के मूल्य में कोई रिश्ता कायम करना चाहिये । चीनी के बारे में यह कि छः आने, साढ़े सात आने सेर की लागत पड़ती है जबकि चीनी ? रुपये सेर बिकती है । चीनी के दाम गिरने चाहियें और गन्ने के दाम बढ़ने चाहियें ।

एक जुम्ला अन्त में कह कर मैं समाप्त कर दूंगा कि इस से अगर मंत्री जी को सन्तोष हो गया है कि सरदार नगर की सरया शूगर मिल के किसानों के ऊपर, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया जैसे मालिकों की प्यास *ढेकू और चन्द्र शेखर मिश्र के खून से बुझ* चुकी है तो फिर समय आ गया है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गन्ने के दाम २ रु० मन जरूर रक्खे जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन का यह कर्तव्य है कि वे इस पर गौर करें ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Sinhasan Singh—I find he is not present. Then, Shrimati Laxmi Bai·

Some hon. Members *rose*—

Shri I. Eacharan (Palghat)· Sir Kerala is a deficit State.

Mr. Deputy-Speaker: Still we are carrying on this debate Kerala will also be represented.

Shri Naval Prabhakar: What about Delhi?

Shri Bishwanath Roy (Salempur) Uttar Pradesh?

Shri R. S. Tiwari (Khajuraho) Madhya Pradesh?

श्रीमती लक्ष्मी बाई · उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं, बहुत बोलना नहीं चाहती । हमारा अन्न का मंत्रालय जानवरों और इन्सानों सब के लिये बहुत करीब है । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती

हूं कि आज गांव गांव, घर घर में आप के नाम का स्मरण हो रहा है । कारण यह है कि जो भी सुझाव आप के पास आते हैं उन पर जब आप चलने की कोशिश करते हैं तो उस में कहीं गड़बड़ी हो जाती है और उस से आप की बदनामी हो जाती है । और किसी भी मंत्रालय की इतनी बदनामी नहीं होती है जितनी बदनामी आप के मंत्रालय की होती है क्योंकि इस देश के लोगों के रोजाना के इस्तेमाल की चीजों में आप का महकमा सब से करीब है । पहले खाना बाद में वस्त्र । यह आप के लिये बहुत अहम चीज है । लेकिन आप गांव में जा कर जगह जगह अपनी पैरवी तो नहीं कर सकते । बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं । जो भी आप की रिपोर्ट आती हैं उन में सीधी सीधी बात नहीं रहती है, कोई न कोई गोलमाल कर के लाई जाती है । उन में कई इधर उधर की बातें रहती हैं जोकि मैं समझती हूं कि बहुत गलत होती हैं । आप हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहां मछलियां बढ़ गईं, दूध बढ़ गया, दाल बढ़ गयी और साथ ही कहते हैं कि लोग भी बढ़ गये । इसीलिये हम को बाहर के बाजारों से अनाज लाना पड़ता है । मैं आप के सामने एक चीज कहना चाहती हूं । आज रोजाना एक आदमी को अगर आधा सेर दूध मिलने का औसत हो तो आप सोचिये कि ३६ करोड़ आदमियों को आधा सेर दूध के हिसाब से कितना दूध चाहिये । उस का हिसाब कई करोड़ आता है । इस के लिये हमारे देश में मछलियां आईं, गोश्त आया, दूध आता है । इस तरह की न जाने कितनी चीजें आती रहती हैं, इस का कोई हिसाब नहीं । हालांकि आज इतनी जरूरत नहीं है फिर भी आप रोज कहते रहते हैं कि बहुत सी चीजें बाहर से आ रही हैं । हिन्दुस्तान सब चीजों के लिये मोहताज ही है । लेकिन यह चीज गलत है । हमारे यहां चीफ मनिस्टर कहते हैं कि जमीन बढ़ रही है, नई जमीन लाखों एकड़ जोती जा रही है । वह समझते हैं कि अगर हम इस तरह से नहीं कहेंगे, अगर यह नहीं बतलायेंगे कि पिछले साल से इतनी ज्यादा जमीन जोत के नीचे लाई गई तो वह नाकाबिल साबित होंगे । इसलिये वह जमीन को बढ़ाते चलते हैं, लेकिन जो हकीकत है उस को नहीं लिखते हैं । इस तरह से जिले से स्टेट में आ कर और स्टेट से सेन्टर में आते आते जमीन बहुत बढ़ जाती है । लेकिन दरअस्ल सरकार को यह पता नहीं है कि असलियत क्या है । आप के आंकड़े बढ़ते जाते हैं । इस तरह से चोरी हो रही है, शैतान लोग बैठे बैठे खा रहे हैं । बात यह है कि आप के यहां नई जमीन तो बढ़ रही है, कल्टिवेशन भी बढ़ रहा है मगर पुरानी जमीन कितनी खराब हो रही है, इस का अन्दाजा आप को नहीं है । चूंकि आप को कोई यह चीज नहीं बतलाता है इसलिये उस के आंकड़े आप के पास नहीं हैं । दिल्ली में दस पंद्रह मील तक चले जाइये । वहां की जमीन ऐसी है कि १५ या २० सालों में जमीन मलाई जैसी हो सकती है और तिगुना अनाज पैदा किया जा सकता है । लेकिन हम देखते क्या हैं कि पत्थरों वाली जमीन बढ़ती जा रही है, इस तरह तो दस साल तक भी वह खेती के काबिल नहीं होगी । जैसे नये वकील की बात होती है कि कोई आदमी उस के पास जाता नहीं है, उस की प्रैक्टिस नहीं चलती है, उसी तरह से आज आप जमीन को तालाबों में, बागों में इस्तेमाल कर के खराब कर रहे हैं । आप को इतना रहम नहीं है कि आप क्यों जमीन में पत्थर फैलाते हैं । जो जमीन अच्छी हो सकती है उस की ओर आप का ध्यान नहीं है, इसी लिये आज पैदावार कम हो रही है, लेकिन इतना होते हुए भी आप के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आप को सही पता नहीं लगता कि कितनी पैदावार हो रही है । हमारे लोग आफिसों में शान से जा कर बैठ जाते हैं, वह सोचने का काम नहीं करते हैं । वह क्यों नहीं देखते कि आज जमीन पर ट्रैक्टर चल रहे हैं या कि पत्थर लग रहे हैं, ईंट बन रही हैं ।

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि आप के पास खाद नहीं, ताकत देने वाली चीज नहीं । फर्टिलाइजर का आप व्यापार करते हैं । आप कहते हैं कि एक साल के अन्दर आप ने ३ करोड़ रुपये कमाये, सिंदरी फैक्ट्री ने ३ करोड़ रुपये के व्यापार की व्यवस्था की है । मैं जा कर देख आई हूं । भले ही उसने ३ करोड़ रुपया एक साल में कमाया लेकिन उस से किसानों की कितनी भलाई हुई । जब हमारे सामने वाले भाई बोलते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम उन को कैसे जवाब दें ? वह लोग सही बात कहते हैं । लेकिन हमारे यादव जी ने जो कुछ कहा वह गलत है । दो महीने लगातार स्ट्राइक करने से कितनी पैदावार बढ़ी है अगर काम न करें उल्टे बगावत करें तो उस से तो नुकसान होगा । आज हमारे यहां फर्टिलाईजर की बहुत जरूरत है । आज श्री राम सुभग सिंह, मिश्र जी और भार्गव साहब ने जो सुझाव दिये हैं वे मानने की बहुत जरूरत है । ११ साल से हमारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इस से हमारे मेहनत करने वाले कल्टिवेटर का कितना हित होता है, हमारी सारी कोशिशों का क्या फल होता है ? इसलिये जो आप का ११ साल का तजुर्बा है उस से कुछ सीखिये और नये तजुर्बे को कीजिये । मैं आप से कहना चाहती हूं कि थ्योरेटिकल अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल चीज अलग होती है । हमारे यहां थ्योरेटिकल बात बहुत जोर से चलती है । अगर आप प्रैक्टिकल चीज को देखें तो चार पांच साल आप के लिये बहुत अच्छा रहेगा । आप का नाम तो राम नाम की तरह से सारे गांवों गावो में फैल जायेगा । आज औरतों के लिये बड़ी मुश्किल है । औरतें रोती हैं कि कहां जाय, एक रु० की १४ छटांक दाल कैसे लाये ? कैसे १०० रु० पाने वाला चावल अपने लोगों को खिलाने के लिये लाये ? लाने के बाद उस को बनाने और खिलाने में औरतों को बड़ी दिक्कत होती है । खाद्य समस्या औरतों के लिये बड़ी मुश्किल है । इस वास्ते आप मेरी बात सुनिये । आप औरतों को बुलाकर उन से मशविरा लीजिये कि पैदावार कैसे बढ़े? अगर आप इसके लिए १ करोड़ रु० रखिए । अगर आप चाहेंगे तो यह बुड्ढे के हाथ में एक लकड़ी का सहारा जैसी चीज होगी । आज गांव गांव में खाद के लिये काम किया जा रहा है । लोग कहते हैं कि खाद के लिये कुछ होना चाहिये । आज लाखों रु० का गोबर बरबाद हो रहा है । गोबर आज ईंधन के काम में लाया जा रहा है । इस पर बोलने के लिये मेरे पास बहुत चीज है किसी और समय में इस को बतलाऊंगी । ईंधन के बारे में मेरे पास बहुत सामान है । मैं ने इसके वास्ते बहुत काम किया है । मुझे बहुत कुछ कहना है । आप मेहरबानी करके मुझे एक मिनट और दें ।

आप पंचायतो को मदद दीजिये । मैं ने इस बारे में अपनी स्टेट में भी कहा था । पंचायतों को दो दो सौ रुपये की सबसिडी दी जाये ताकि गांवों में ट्रेंच लेटरिन बनायें जायं जैसे कि वरधा में हैं । इससे आरोग्य भी बढ़ेगा और इससे सस्ती खाद भी मिलेगी ।

इसी तरह से शहर का जो ड्रेनेज का पानी है उसका उपयोग खाद के लिए किया जा सकता है । जो लोग जी० टी० एक्सप्रेस से जाते हैं वे देख सकते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज का पानी बीस मील तक जाता है । मैं हैदराबाद के ड्रेनेज के पानी से २० एकड़ का प्रबन्ध करती हूं । अगर इस पानी को काम में लाया जाये तो इससे ५ परसेंट खाद मिल सकता है । इसमें पैसा भी नहीं लगता । ड्रेनेज वाटर में बहुत खाद होता है ।

अब मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूं जो कि मरदों को नहीं मालूम । अगर आपको सेर दो सेर आटे की जरूरत होती है तो चार सेर तरकारी की भी जरूरत होती है ।

आजकल दिल्ली में १२ लाख रुपये रोज की तरकारी की बिक्री होती है । आजकल टमाटर यहां ६ आने पाव हैं । घर घर में यह शिकायत है कि देश आजाद हो गया लेकिन खाना नहीं मिलता । यह बुरी बात है । मैं इसके लिए एक हल बताती हूं । आप देखें कि किसान तीन महीने में टमाटर उगाता है, साढ़े तीन महीने में बैंगन उगाता है । जब तरकारी पैदा हो जाती है तो उसको उसे १५ या २० मील बाजार में लाना पड़ता है जिसमें उसके दो तीन रुपये लग जाते हैं, और कभी कभी उसको जो तरकारी बेच कर मिलता है वह उसके किराये से भी कम होता है । इस तरह किसान को नुकसान होता है और लेने वालों को भी तरकारी महंगी मिलती है । सिर्फ जो बैठकर बेचता है उसको लाभ होता है । वह किसानों से भी लाभ उठाता है और खाने वालों से भी लाभ उठाता है । ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए । मेरा सुझाव है कि तरकारी देहात से लाने के लिए ट्रकों का इन्तिजाम होना चाहिए । किसान अपनी तरकारी ट्रकों में लावें, यहां बेचें और उनको वापस पहुंचा दिया जाये और उनसे केवल, पेट्रोल का दाम और ड्राइवर की तनख्वाह ही ली जाये जैसे कि पब्लिक स्कूलों में होता है । यह चीज बहुत जरूरी है । आप गावों का, बैलों का, घोड़ों आदि का इन्तिजाम करते हैं लेकिन इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं । मैं चाहती हूं कि लोगों को अच्छी तरकारी सस्ती मिलनी चाहिए और किसान को भी लाभ होना चाहिए । अगर किसान को लाभ नहीं होगा तो वह उस गाय की तरह होगा कि जिसको खाना कम दिया जाये । वह आठ दिन में दूध देना बन्द कर देगी । तो मैं चाहती हूं कि किसान की हालत उस सोने के अंडे देने वाली मुरगी जैसी न हो जाये । आज जो हालत है उसमें किसान भी नाराज है और खाने वाले भी नाराज हैं । प्रेस वाले भी नाराज हैं । प्रेस वाले इन बातों के बारे में नहीं लिखते । वे तो बेजेज के बारे में ही लिखते हैं ।

मेरे पास और भी बहुत सी बातें हैं । अगर एग्रीकल्चर वाले चाहें तो मैं उनको बतला सकती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय . और किसी वक्त सही ।

Pandit K. C. Sharma (Hapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to make a few remarks. There is not enough time to make a speech; I will simply point out certain basic characteristics of backward agriculture. Thus all over the world wherever there is what is called uneconomic agriculture firstly there is low capitalisation; that is, they have not got enough of investment. And where there is a rich agriculturist or a landholder he spends his income on marriages and other costly things which have little to do with the productive capacity of the farm. That is one thing. A certain attitude has to be adopted there, and that will come from education. The second thing is low agrarian technique. Here I want to point out that this plough, wooden plough has perhaps originated when the Vedas were written when half the people were living in the villages and the other half were living in the jungles Now the world has changed and our Prime Minister often talks of atomic energy and nuclear energy experiments. But this wooden plough has not changed. This curse must go. I should say it is criminal for the cultivator to use this plough. for the simple reason that it tantamounts to starving the people to death very slowly. It does not go deep enough into the soil and because of that the heat of the sun does not go into the particles. Therefore, it gives poor income.

It is said that with modern manuring and better technique the difference

[Pandit K. C. Sharma]

in yield can be 20 times. Our soil has been impoverished for 2,000 years. It is poor and is dying as an aged man without food dies. Therefore, a revolution in the enrichment of the soil, in the change of technique in the change of investment is necessary.

About investment I might make one point. There is a serious consideration about co-operatives and changing shape of things and in that connection many plans are thought out. The simple proposition is this. Uptill now agriculture has been, what is called, self-sufficing agriculture or subsistence occupation. If you have to change it into an industrial enterprise or commercial enterprise then investment is necessary. Situated as we are the cultivator cannot provide the investment. He has little to save, poor technique and poor soil. So, the State has to provide the investment. Now all commerce and industry requires investment. If agriculture is to be changed into an industrial enterprise, as it must, then investment is an essential thing. And the State alone can provide it.

All the new changes of co-operative farming, whatever you may talk of, will cost the State something like Rs. 2,100 crores for improving the land. It is impossible to think about new things, new changes, without investment.

There is a lot of confusion in thinking here. People think that because there is lot of unemployment in the country, therefore, by resorting to this co-operative farming you can put everyman on the farm. Now any land economist will say that in a progressive country the percentage of labour to work on the field to provide food for the country should not exceed 10 per cent. of the labour force. Your civilisation, your claim to culture, your claim to a developing community will depend upon this single factor—whether there are 11 per cent. labour working on the field for providing you food or 10 per cent. The more people than 10 per cent working on the field, the less civilized you are, and less force would be there in your voice anywhere in the world in any matter whatsoever. It is not a question of making big plans. The question is simple. What is your capacity to work? How is that capacity to be judged? A simple elementary principle of judging the capacity of the country is: whether there are 10 per cent of the labour force working in the fields for providing food for the country or there are more. If there is more, it means, the capacity is less and if the capacity is less, you are certainly a lesser man in the comity of nations.

Passing to another characteristic, the holdings are very small. The small and uneconomic holdings should be consolidated. They may be consolidated on co-operative farming basis or they may be consolidated under any other system. Production would increase only after investment and adoption of scientific methods. Then, Sir, I come to indebtedness. I want that a law should be passed that if there is debt on a cultivator and five years have passed, that debt should be wiped out. No more indebtedness should remain on the basis of past contract if five years have passed. Let us have a clean slate. Let the cultivator be relieved of all the old worries so that he may have fresh air to breathe and fresh opportunity to move his limbs.

The method of production, as I said, is old fashioned. I refer to the plough. You have got a number of research institutions. There are hybrid corns which are more resistant to disease and they give greater yield. I want that better seeds of the more improved varieties should be given to the peasant so that he may increase the yield. For instance, in sugarcane, you

have No 312 and 313 There is a lot of dispute and so many strikes are going on about the price of sugarcane That is a fundamental problem Somebody, either the State or the sugar mill should be made responsible for providing a better variety of seeds, for providing the manure Somebody should be there to watch how many times the sugarcane field has been properly watered In the U S A, the State is responsible for conservation of the land The State authorities see that proper precaution is taken for conservation of the land and if proper precaution and necessary steps are not taken, the cultivator is to be punished What I beg to submit is that we have to improve and radical changes are necessary

The Research institutions are, in the first place, few in number and in the second place, the fruits of their researches do not go to the tenant Now, fortunately, there are enough educated people in the villages,—education has spread and it will spread more rapidly—so that they can catch up with them I want to ask you, how many of the gentlemen in the Research institutions go to the village panchayats or even district levels and how many of the district officers working in the Agriculture Department go to the villages to explain the results of the new researches What is the use of these institutions if the results of the researches do not go to the man for whom the institutions are established? This is a point I emphasise regarding potato, sugarcane, wheat and rice Thanks to Dr P S Deshmukh, a new method has been evolved. I belong to a district where there is enough paddy grown This method of transplanting the plants has been long in use It gives good results But, the trouble is that, in our part, it is given to the labourer and he takes a half share. Giving a half share, the cultivator is not satisfied with the other half. We have experimented transplanting the saplings three or four times and the result is very beneficial.

I want to point out that in the matter of seed, this experiment should be made with every corn It is not good only in the case of potato, it is equally good in the case of wheat and any other corn In our district, we have mango trees A mango plant is transplanted in 8 or 9 places Every month he changes and the fruit is a beautiful result It is much better and it is much sweeter So, for the purpose of improving the variety of seed, such experiments should be useful

Our low agricultural production is due to mal-nutrition of the farmers. Although an average person requires 1880 calories per day, our agriculturist labour do not get more than 1320 calories It is just impossible to carry on one's work in an efficient way with such low calories So, their food habits must be changed Our Agricultural Department could take to what is called mixed farming Some method should be devised whereby more nutritious food could be provided to our peasants The fundamental trouble with our peasant is that he does not get enough food to keep him strong enough to work hard He says that God has made him and that God will give him food. We have learnt the doctrine of distribution We say that when there is some wealth, we are equal partners The fundamental core of this socialistic principle is a dynamic creative force To create, we forget, to share, we learn What is to be shared in the land of poverty, except poverty? What is to be shared in the land of ignorance and disease, except ignorance and disease? So, our effort should be to create more wealth for the nation For this purpose, we must educate our agriculturists We should inculcate the necessary creative incentive into our peasants and we should make him work harder and better for the good of the community and for the good of the country

Mr. Deputy-Speaker: Now the hon Member must conclude

Pandit K. C. Sharma: Another point I would request that new

[Pandit K. C. Sharma]

demonstration farms should be opened to demonstrate new methods. This is very necessary. Since my time is up, I do not want to say more on this point.

Dr. P. S. Deshmukh: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not want to take more than half an hour. During the time at my disposal I can touch only a few of the subjects and the points raised by the hon. Members who spoke before me. The first point which I would like to take up is with respect to what Shri Asoka Mehta said, about the contract for supply of *jowar* having been given to a non-existent firm. He read out some portions from the report of the Public Accounts Committee of the State of Bombay, and it does give a wrong impression about the facts, which I would like to correct.

I know Shri Asoka Mehta is not a sensation-monger in any sense of the term, and yet what he has said may create a sensation, because all such things attract more attention of the people than any other sober and real facts.

It is not true that this firm was non-existent. Of course, first of all, I would like to point out that this matter is as old as February, 1953. When the State of Bombay was hard pressed for providing food to their people and they were badly in need of *jowar*, we came across a certain firm which was, I think, registered in U.P., which took the responsibility of providing about 10,000 tons of *jowar* to the Bombay Government at the rate of Rs. 10 per maund. We did suggest that since this agent and this firm was prepared to provide the *jowar*, the Bombay Government might deal with it, and the Bombay Government started dealing with this firm; the firm actually were not able to supply more than about 126 tons of *jowar*. So, first of all, the dimension of the deal with this non-existent firm was not as much as 10,000 tons but it dwindled down only to 126 tons. Secondly, it is not by any means non-existent, because there is already a suit filed in the court in Delhi by this non-existent firm against the Bombay Government asking for a damage of Rs. 2.71 lakhs. Actually, the trouble between the Bombay Government and this firm is about. . .

Mr. Deputy-Speaker: It is rather kicking.

Dr. P. S. Deshmukh: It is not only not non-existent, but it is trying to kick.

There is also no dispute about the 126 tons having been given; they have not claimed any price on account of that. The trouble has arisen because the Government of Bombay did give to this firm some gunny bags worth about Rs. 25,000; these gunny bags were received by the firm, and the Bombay Government wanted certain security. That security was not provided. The contention of the firm is that the price in the meantime rose up, and the Bombay Government did not give them credit in the proper time, the offer of credit on the bank and so on. That is the dispute between the Bombay Government and the firm.

So, all that I want to point out is that we were not dealing with any non-existent firm, and that the statement here is palpably incorrect, namely that the firm was non-existent. I would not like to go into the details, because the matter is already in the court. In any case, the dimensions of the money involved are not as much as they are likely to be imagined by the Members of the House on hearing Shri Asoka Mehta.

The next point he made was about soil conservation. It is true that we did not realise the importance of soil conservation very early. It was only in 1953 that we constituted a soil conservation board. But, since then we have been able to make fairly good progress not only in the shape of reclamation of lands or stopping soil

erosion and having contour bunding and so on, but we have taken a comprehensive view of the whole matter of soil conservation.

Undoubtedly, this is a colossal problem, a problem which affects our production and certainly causes a good deal of harm not only to land but consequently to the crops we grow, and to the farmers who are interested in growing those crops. We have fully realised the importance of this. There is no time for me to go into the details, but I would only mention that these are the four aspects which the board is dealing with, namely reclamation of land, afforestation, and preservation of land by scientific management, land practices on farm lands and engineering measures like contour bunding and so on. An amount of Rs 3·25 crores was allotted for soil conservation in the last two years of the First Plan, and we spent Rs 1·6 crores There were, of course, difficulties in the way of our proceeding fast in the beginning because there was lack of proper organisation for soil conservation in the States. There was paucity of trained personnel, and there was also lack of legislative measures in order to compulsorily carry out some of these measures, but all these are getting progressively countered, and now there are seven States which have already got soil conservation boards. We have also allotted certain large sums for a survey, because even soil survey was missing. When we started with this Board, there was not a complete survey of our lands. Even that had to be undertaken on a large scale, and we are intending to complete a survey of about 4 million acres of land. This will show to my hon. friend that we are not sleeping over this front, that we are trying to tackle it, and the tempo of whatever work we are doing is likely to be faster in the years to come

I may particularly mention the excellent work that is being done by the Bombay Government, especially in the Sholapur District which is a famine-stricken district more or less, where contour-bunding is being done by the farmers on the advice of the Agricultural Department, and the tempo of their work is very high. I think they deserve a word of praise for the way in which they are tackling this problem

My hon friend Shri Nagi Reddy referred to the tobacco trade and complained against grading. I for one can never understand anybody's complaint against grading Lack of grading will mean that you sell the best varities at almost the price of the middle quality if not the lowest quality of that particular goods. So, this is a thing which really speaking, not only benefits the growers; it also benefits the trade I am sorry to see that a good many of the merchants are perpetually complaining against grading methods and so on

Shri Panigrahi (Puri). How many grades are there in tobacco?

Dr. P. S Deshmukh: His main complaint was that as against three grades in U S A we have as many as 13 grades I am sure our experts are not ignorant of what exists in the U S A, and if they have as many as 13 grades, there must be some purpose behind it, and that purpose is quite simple In our country the varieties of tobacco which is grown and the various standards of purity and so on are so varied that we feel that the best way to give to the growers the best possible price is to have a larger number of grades than to restrict it to three, because if you combine all sorts of grades into one, you are likely to get the price not of the best but of the lowest thus causing some loss, in fact considerable loss, to the grower. I am sure on proper study my hon. friend Shri Nagi Reddy would not find fault with our having 13 grades and 13 qualities as against three in U.S.A. I do not know how far his information is correct, but I am taking what he said as correct

[Dr. P. S. Deshmukh]

Before I come to cows and milk, I will deal with the speech of my friend Shri Chavan. He gave a lot of figures, referred to the large sterling balance we had in the U.K. and so on. He complained that as against the rate of interest charged by the Reserve Bank, the co-operatives were charging a high rate. Although I am no longer in charge of co-operatives, I would like to tell him that this is rather a difficult problem, because the various agencies which actually provide the credit to the farmer also have to subsist and live Although it is our policy to reduce the interest rate to the lowest possible minimum, and we have placed 6½ per cent as the target, in most places this has been achieved also, difficulties arise as a result of the co-operative societies which have to maintain their offices. Then we have the central banks and then the apex bank and so on. So I can assure him that we are all interested in providing to the farmers credit at the lowest possible rates. We are all determined to see that he will not have to pay anything more than he can afford to

Dr. Ram Subhag Singh referred to tractors and said that if there was a 40 HP tractor, then 40 pairs of bul locks would be rendered useless I think the mathematics is somewhat exaggerated I do not think that a 40 HP tractor can do the work of 40 pairs of bullocks. I for one would like to say that Indian tillage is not as efficient as it should be. Although we do not want to go to the extent the Chinese have done, there is need for tilling our lands more and better In many places, this cannot be done merely with the aid of bullocks. But I am not one who is in favour of wholesale mechanisation. We are also agreeable, since holdings are likely to be small hereafter, to have smaller tractors. We are trying to manufacture them in our own country

The problem of waterlogging has also been referred to. The hon. lady Member (Shrimati Laxmi Bai) referred to several thousands of acres of land lying fallow. It is really a heart-rending spectacle; there is no doubt about it. The problem of the usar land which we meet with in Punjab, round about Delhi and in U.P. is a tremendous one But it will have to be tackled also on a big scale. I am sure we will do it. We have not neglected the problem altogether. A large number of tube-wells were dug in the Punjab merely for the purpose of preventing waterlogging. Similar schemes will have to be undertaken hereafter also. So it cannot be said that we have neglected this problem completely Additional resources will certainly have to be made available for tackling this There is no doubt that if these lands could be resurrected and brought back to cultivation, our food production will increase and to that extent the situation will be easier

Some hon Members referred to mixed farming They laid considerable emphasis on it I do not know what they mean, because we have ourselves been preaching mixed farming In India there is probably not as much of animal husbandry as they have in foreign countries But we have always asked the people to take to mixed farming We have laid emphasis on it So long as the bullock and the cow are with the cultivator, it is nothing but mixed farming

Shri Yadav made more a propagandist speech than advanced any reasoned arguments. He wanted to condemn the Government on every score and referred to happenings of 1948 and so on. In spite of contradictions, in spite of more or less effective proof to the effect that there have been no starvation deaths, he tried to refer to certain things which really did not exist. I am sure he wanted merely to catch the eye of the people against the Government rather than to make any particular points which require to be dealt with.

Pandit Munishwar Dutt Upadhyay made two suggestions. One was about

double cropping and the other about co-operative farming. We are trying to encourage double cropping, wherever possible. If figures are studied, it will be found that double cropping is on the increase in India.

The idea of co-operative farming is not a new one. As will be found from my speech of last year, we had already indicated that Government were intending to establish co-operative farms—at least 600—in the country during the last year. Considerable progress has been made in that direction. So there is no disagreement so far as co-operative farming is concerned. I do not see any reason why people should be so much against it so long as it is clear that it is voluntary and it is meant to benefit the people. There will also be considerable assistance that would be made available.

I would now come to the speeches of the two 'Dases'—Seth Govinda Das and Pandit Thakur Das. It just occurred to me a few hours back that probably they feel they are morally responsible for the cow because of the names they carry. Thakurji means Gopalji and Gopalji means Krishnaji which comes to the same as Govindji I think probably even their names have a certain amount of effect on them because there could be no speech on the Food and Agriculture Ministry without either of these two Members referring to the cow and the milk and so on. It is all good and I do not condemn them. I should not be misunderstood that I want to condemn their references. It is very good. .

Mr. Deputy-Speaker: Is it that the name had been given after it had been found out that they had certain inclinations or is it because they have those names that they are always one in this point.... (*Interruptions.*)

Shri D. C. Sharma: Does the hon. Minister agree that one seer of milk is equal to nine eggs—that is the equation that Pandit Thakur Das Bhargava gave.

Dr. P. S. Deshmukh: I have not had time to ascertain the equivalent value. I will investigate into it a little later. I am afraid I cannot answer his question just now. Now, both of my friends have lamented that milk yield has gone down not only per cow but also so far as the total is concerned. He has referred to certain replies given by us. In actual fact, when there was some careful investigation into this question, we have found that although there has not been any spectacular rise it is not correct to say that the total milk yield is much less in the hon. Member's region. The Northern region, etc where we have carried out very detailed survey and census through the ICAR; it has not substantially diminished. In fact it has shown improvement but one fact which I have referred to more than once is that it is very difficult to maintain or increase the average because the survival of cows and especially of bad cows is increasing so fast because of the preventive measures that we have undertaken that it is not at all easy to keep pace with the growing demand for milk or to make any substantial progress. My friends have also regretted the fact that we are not making arrangements for a larger amount of fodder and so on. So far as the increase of fodder supply is concerned, we have taken a large number of steps, right from research and try to get new varieties of grasses that will grow under our conditions and also to spread the habit of growing certain green fodder and so on. My friends unfortunately are not prepared to face these two problems, namely, the increase in the number of the cattle in the country, especially the survival of the dilapidated and old cattle which are at least not yielding the same quantity of milk—they could not even yield very much of cowdung—as the others; in fact their yield of milk is bound to be nothing. This is one fact which our friends forget. Secondly, it is impossible to maintain the health of the cows even as it was ten years ago if the fodder supply is diminished as it is bound to. It cannot be increased, as we know and as

[Dr. P. S. Deshmukh]

the statistics will also show, when the acreage under agriculture has considerably increased by quite a few million acres. To that extent the cows must have been deprived of the fodder produced in that area. The very fact that we have more cultivated land will show that the fodder must have gone down On the other hand, the number of cattle has increased so much that the average availability of the fodder must have been diminished and that must have affected not only the health but also the yield of cows' milk

18 hrs.

So, Sir, we will have to face this problem some time or the other. On the other hand, we are attending to the question of fodder supply. We have got the key village centres We have also the gosadans where we want to care for the cows and so on

Now, both of these hon. friends are fully associated with the Government's policy so far as everything in this respect is concerned. Both of them are members of our Gosamvardhan Council, and they are almost day to day in the know of the facts and the things that we are doing.

Mr. Deputy-Speaker: Is the hon Minister likely to take some more time?

Dr. P. S. Deshmukh: I will take a few minutes more

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 8, 1959/Chaitra 18, 1881 (Saka).